

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. V Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 8, Wednesday, December 03, 2014/Agrahayana 12, 1936 (Saka)**

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCE	2-3
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 145	5-49
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 146 to 160	50-97
Unstarred Question Nos. 1611 to 1768, 1770 to 1787 and 1789 to 1840	98-611

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	612-616
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
2nd Report	617
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i) Incident in District-Sukma, Chhattisgarh which happened on 01.12.2014	
Shri Rajnath Singh	618-621
(ii) Prime Minister's recent visits abroad	
Shrimati Sushma Swaraj	622-627
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO.622 DATED 26TH NOVEMBER, 2014 REGARDING 'DECONGESTION OF DELHI'	628-629
ELECTIONS TO COMMITTEES	630-631
(i) Advisory Council of the Delhi Development Authority	630
(ii) Council of Indian Institute of Science Bangalore	630-631
(iii) National Board for Micro, Small and Medium Enterprises	631
MOTION RE: SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	632

SUBMISSION BY MEMBERS

- (i) Re: Issue of alleged destruction of a church in East Delhi due to fire prompting allegation of foul play by church authorities 638
- (ii) Re: Alleged Misbehaviour with a woman Member of Parliament by Local District Administration during foundation stone laying ceremony for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Munger, Bihar. 649-951

MATTERS UNDER RULE 657-678

- (i) Need to make Gorra and Ami rivers in Gorakhpur pollution free
Yogi Aditya Nath 657
- (ii) Need to provide honorarium at uniform rate to Anganwadi workers and extend them social security benefits particularly in Uttar Pradesh
Shri Jagdambika Pal 658
- (iii) Need to take action on report of the National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes
Shri Nana Patole 659
- (iv) Need to include Bikaner city in Rajasthan in the list of 100 cities proposed to be developed as smart cities
Shri Arjun Ram Meghwal 660
- (v) Need to include 12 key cancer drugs recommended by the Tata Memorial Centre in the list of essential medicines
Shri Janardan Singh 'Sigriwal' 661

- (vi) Need to provide compensation to families of victims died in gas tanker explosion at Charoti Naka on National Highway No. 8 in Palghar district of Maharashtra
Shri Chintaman Navasha Wanga 662
- (vii) Need to establish a cancer Institute in Rampur, Uttar Pradesh, by the Central Government
Dr. Nepal Singh 663
- (viii) Need to take remedial measures to check the annual floods occurring in various parts of the country
Shrimati Krishna Raj 664
- (ix) Need to ensure proper implementation of electrification of villages under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in West Bengal
Shri Adhir Ranjan Chowdhury 665-666
- (x) Need to introduce new DEMU train service between Salem and Puducherry via Vriddhachalem
Dr. K. Kamaraj 667
- (xi) Need to provide adequate grant under subsidy component to Government of Tamil Nadu and also permit cooperative banks to operate accounts for transfer of LPG subsidy to consumers.
Shri S.R. Vijay Kumar 668-669
- (xii) Need to provide adequate funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in West Bengal
Dr. Ratna De (Nag) 670

- (xiii) Need to take suitable steps for revival of the Mumbai Port Trust
- Shri Arvind Sawant
- 671
- (xiv) Need to take remedial measures to check increasing number of fatal road accidents in the country
- Shri Bhagwant Mann
- 672
- (xv) Need to provide free sanitary napkins to women to boost female health and hygiene in the country
- Shri Dhananjay Mahadik
- 673
- (xvi) Need to observe 19th February, the birth day of Shivaji Maharaj as 'Rashtra Bhakti Prerna Diwas'
- Shri Raju Shetty
- 674
- (xvii) Need to resume extraction of copper in Khetri Copper Complex in Jhunjhunu, Rajasthan
- Shrimati Santosh Ahlawat
- 676
- (xviii) Need to improve the standards of teaching and facilities in government-run educational institutions for higher education in the country and also establish more colleges keeping in view the large number of students seeking admissions in such colleges particularly in Delhi
- Shri Ramesh Bidhuri
- 677
- (xix) Need to expedite gauge conversion of Ratangarh-Sardarshahr and Sadulpur-Hanumangarh railway lines in Rajasthan and augment train services in the State connecting Churu Parliamentary Constituency
- Shri Rahul Kaswan
- 678

BUSINESS OF THE HOUSE	679-680
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE BILL, 2014	681
Motion to Consider	681
Shrimati Smriti Zubin Irani	681,744-752
Shri Gaurav Gogoi	682-687
Shri Alok Sanjar	688-690
Shri K. N. Ramachandran	691-693
Prof. Saugata Roy	694-700
Shri Tathagata Satpathy	701-705
Shri Arvind Sawant	706-709
Shri Jayadev Galla	710-712
Dr. Boora Narsaiah Goud	713-716
Shri P.K. Biju	717-719
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	720-721
Shri Dharam Vira Gandhi	722-724
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	725-728
Shri E. T. Mohammad Basheer	729-731
Shri Prem Das Rai	732-733
Shri Kaushalendra Kumar	734
Shri N.K. Premachandran	735-737
Dr. Manoj Rajoria	738-739
Shri K. Parasuraman	740
Adv. Joice George	741-742
Shri Konda Vishweshwar Reddy	743
Clauses 2 to 42 and 1	749-751
Motion to pass	752

REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2014 753-754**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	755
Member-wise Index to Unstarred Questions	756-760

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	761
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	762

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 03, 2014/Agrahayana 12, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को तीन भूतपूर्व सदस्यों श्री आनंद पाठक, श्री जरबोम गामलिन और श्री अब्दुल रहमान अंतुले की दुखद मृत्यु के बारे में सूचित करना है।

श्री आनंद पाठक पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सातवीं, आठवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री पाठक बारहवीं लोक सभा के दौरान उद्योग संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री पाठक वर्ष 1977 से 1980 तक राज्य सभा के सदस्य थे। वे वर्ष 1971 से 1972 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे थे। विद्वान श्री पाठक एक नेपाली पाक्षिक पत्रिका 'अग्रदूत' के संपादक भी रहे। श्री आनंद पाठक का निधन 28 नवम्बर, 2014 को 84 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ।

श्री जरबोम गामलिन अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री गामलिन तेरहवीं लोक सभा के दौरान रक्षा संबंधी समिति, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां संबंधी समिति तथा ग्रंथालय समिति के सदस्य थे।

श्री गामलिन अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। श्री जरबोम गामलिन का निधन 30 नवम्बर, 2014 को गुड़गांव में 53 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के कुलाबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो आज रायगढ़ है, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री अंतुले दसवीं लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति और संसद सदस्यों के लिए सुविधाएं और लाभ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति थे। वे दो बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे। समर्थ प्रशासक श्री अंतुले जून, 1995 से मई, 1996 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, फरवरी, 1996 से मई 1996 तक जल संसाधन मंत्री और जनवरी, 2006 से मई, 2009 तक केन्द्रीय सरकार में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री रहे। श्री अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 1962 से 1976 तक और 1980 से 1989 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। श्री अब्दुल रहमान अंतुले का निधन 2 दिसम्बर, 2014 को 85 वर्ष की आयु में मुम्बई में हुआ।

हम अपने सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी है। आज ही के दिन भोपाल को भीषण औद्योगिक दुर्घटना का सामना करना पड़ा जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य अनेक लोग जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आने के कारण अशक्त बना देने वाली गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए।

यह सभा इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए अपना सतत् समर्थन सहानुभूति दोहराती है।

अब सभा में उपस्थित सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कृपया थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

11.02 hrs

The Members then stood in silence for short while.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधान मंत्री जी हमारे सामने मौजूद हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि सस्पेंशन ऑफ क्वश्चन आवर का रूल नहीं होता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हरेक की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आज प्रधान मंत्री जी आए हैं तो मैं उनके सामने एक महत्वपूर्ण विचार लाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने नोटिसेज़ में जो तीन विषय लिखकर दिए हैं, उन्हीं के बारे में बोलना चाहेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं नोटिसेज़ के अलावा एक विषय के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। कल एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया था जिसके ऊपर चर्चा भी हो गई थी। उन्होंने अपना अपराध मान लिया। जब उन्होंने अपना अपराध मान लिया है तो प्रधान मंत्री जी को उन्हें अपने मंत्री पद से हटा देना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो एडजर्नमेंट नोटिसेज़ दिए हैं, उन पर चर्चा भी हो चुकी है। अब एक भी एडजर्नमेंट नोटिस एडमिट करने जैसा नहीं है। मैं इसे निरस्त करती हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 141 - श्री महेश गिरी।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. ऐसा नहीं होता है।

*(Interruptions) ... **

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(Interruptions) ... **

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

11.07 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 141, Shri Maheish Girri

(Q. 141)

श्री महेश गिरी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सैंटर फार डैवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग/सुपर कंप्यूटर ग्रिड विकसित कर रहा है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वर्ष 2014-15 में इस प्रयोजन में कितना बजट आवंटित किया गया था? सुपर कंप्यूटरों की उपलब्ध संख्या कितनी है और अनुसंधान विकास के लिए प्रचालन करने वाली संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, इसमें कई प्रश्न हैं। सुपर कंप्यूटर एक प्रकार से कई कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं और इनके काम करने के कारण क्लाउडिग, मॉड्युलिंग, वैदर प्रैडिक्शन, एयरो स्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशन, बायोलॉजी, इन सबमें इसका उपयोग होता है। भारत की वर्तमान सरकार ने इस दिशा में बहुत ही आगे कार्यवाही करने का निर्णय किया है। हमने 4,500 करोड़ रुपये की योजना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्ट्री के साथ बनाई है। इसका एक्सपेंडीचर फाइनेंस कमेटी ने एप्रूव कर दिया है। हम जल्द ही कैबिनेट के सामने जाएंगे और भारत की वर्तमान सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी, का निर्देश है कि सुपर कंप्यूटर की दिशा में भारत को आगे बढ़ना है। हम भारत को एक बड़ी ताकत बनाएंगे। उन्होंने जो स्पैसिफिक सवाल किया है कि कितने सुपर कंप्यूटर हैं, तो अभी देश में 30 सुपर कंप्यूटर हैं और सी-डाक संस्था अच्छा काम कर रही है। इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, यह हमारा संकल्प है।

श्री महेश गिरी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों कुछ ऐसा पता चला कि पिछली सरकारों ने जब इसका प्रयोजन किया था तो इंडिजनस सुपर कम्प्यूटर के ऑर्डर दिए गए, उस वक्त इंडिजनस सुपर कम्प्यूटर के नाम पर अमरिकी सुपर कम्प्यूटर के ऊपर अपने ही लोगो लगाकर दिए गए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार सुपर कम्प्यूटर क्षमता के मामले भारत चीन के मुकाबले कहां खड़ी है और क्या हम उसके समकक्ष लाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं।

11.11 hrs

At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, जो सवाल पूछा गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि चीन की तुलना में भारत पीछे है। एक समय हम चार नम्बर पर थे आज हम 71 पर हैं। एक समय चीन 71 पर था वह आज ऊपर चला गया है। हमारी सरकार इस दिशा में कृतसंकल्प है कि सुपर कम्प्यूटर की दुनिया में भारत एक अच्छा स्थान बनाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है और सीडॉट संस्था इस बारे में बहुत ही विस्तार से साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रही है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। माननीय मंत्री जी का मूल प्रश्न का उत्तर पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि सुपर कम्प्यूटर के संबंध में भारत अमेरिका, चीन और फ्रांस आदि विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस सुपर कम्प्यूटर ग्रिड का प्रयोग धरती के गर्भ में छिपे विभिन्न खनिज पदार्थों की खोज करने तथा मौसम की मार से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त समयपूर्व मौसम भविष्यवाणी करने में किस प्रकार इसका उपयोग करेगी।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं सुपर कम्प्यूटर के मामले में बताना चाहता हूँ कि मौसम की सही जानकारी देने में, डिजास्टर के बारे में बताने में और अपने किसानों की सेवा में भी इसका काफी उपयोग होगा। आपने खनिज के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में सही कहा। इस दिशा में सुपर कम्प्यूटर के माध्यम से किसानों की अधिक से अधिक सेवा हो सके, खनिज पदार्थों की खोज में सहयोग हो सके, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में आगे जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, हम उसे करेंगे।

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): इस विषय पर कल चर्चा हुई थी और उसके बाद माननीय मंत्री ने माफी मांग ली, उस समय सदन के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की, अचानक उसी विषय को वापस लेकर आने का क्या औचित्य है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर माननीय सदस्य यहां आए हैं तो यह बिल्कुल सदन की कार्रवाई का अवमानना है।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, अगर ऐसा करेंगे तो रोज सबको माफी मांगनी पड़ेगी। Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जो हो गई, उसको दुबारा नहीं दोहराते।

... (*Interruptions*)

SHRI P.R. SUNDARAM : Madam Speaker, I thank you for allowing me to ask a supplementary question.

India is one of the best IT sectors in the world. It is also producing a number of quality and talented IT professionals. We are behind in developing super computers compared to countries like USA, Japan, China and countries of Europe. I would like a clarification from the hon. Minister whether C-DAC and IISc have signed any agreement with any country on the proposal of building capacity and capability Mission. If so, I would like to have the details please.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As far as capacity building exercise is concerned, it is an on-going exercise where scientists of C-DAC exchange notes with many other countries. I wish to inform this hon. House and the hon. Member that our scientists in C-DAC, Pune are very competent. They have helped develop a lot of super computers. They were not given the requisite support in the past. The present Government is keen to give all the support.

As far as specific cooperation agreement is concerned, I will get those facts and supply to you. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran ji. Do you want to ask the question?

SHRI P. KARUNAKARAN : No.

HON. SPEAKER: No, all right.

Prof. Saugata Roy ji.

PROF. SAUGATA ROY : No. ...

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

(Q. 142)

HON. SPEAKER: Q.No. 142. Shri Bishnu Pada Ray. Is he there? Not here.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप 'ले' कर दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो अंडमान-निकोबार के नहीं हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि वर्ल्ड के 500 टॉप इंस्टीट्यूट्स में हमारे देश के दो आईआईटीज का नम्बर आता है, उसमें एक आईआईटी का 254वां नम्बर है और दूसरे आईआईटी का 258वां नम्बर है। क्या माननीय मंत्री जी विस्तारीकरण के बजाय, नये इंस्टीट्यूट्स खोलने के बजाय हमारे आईआईटीज को वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं?

दूसरा, हमारे देश में अभी भी फ्रॉंटियर टेक्नोलॉजी के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में डीप माइनिंग के बारे में, चाहे गैस, ऑयल, मिनरल्स, न्युक्लियर एनर्जी या एरोनोटिकल इंजीनियरिंग का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये।

डॉ. सत्यपाल सिंह : क्या हम ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश कर रहे हैं?

तीसरा, हमारे देश में, प्राचीन भारत में जो टेक्नोलॉजी थी, क्या हम उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam Speaker, through you, I would like to inform the hon. Member that we are looking at building capacities within current Institutes of Technology which include even understanding of new knowledge which is developed across the world.

Insofar as mining is concerned, there is an institution called the Indian School of Mining in Dhanbad which looks at various methodologies and

knowledge avenues vis-à-vis mining. We are looking at even strengthening academia in that institution.

SHRI KADIYAM SRIHARI : Madam Speaker, I am having one reputed institution, NIT at Warangal. Earlier it was REC. It was re-named as NIT. Now all the national institutes of technologies acquired national status. These institutes have to compete globally in all respects. But many institutions in India are having faculty vacancies. They do not have sufficient funds to take up research work. I would like to know from the hon. Minister whether she is going to allot any funds specially for research work in NITs for competing it globally.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you, I would like to express solidarity with the concern that has been put forth by the hon. Member of Parliament. There are two aspects to the concern that he puts forth. One is that we make our institutions globally competent enough. To complement that concern, the Prime Minister had instructed our Department to ensure that those illustrious academicians and professors and industry experts who are available world-over be invited to India, to our institutions so that our students and our faculty can benefit from their presence and interaction. Under the Global Initiative of Academic Network, we have provided for the same. Similarly, in a meeting which was held of the NIT Councils, we gave equal emphasis to research areas which the faculty and students are interested in.

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ग्लोबल पैरामीटर के, वर्ल्ड बैंक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रैकिंग में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम निश्चित तौर से उनके आभारी हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि टैन्थ फाइव ईयर प्लान में इस देश के विभिन्न राज्यों में 20 एनआईटीज थे। सरकार ने 11वें प्लान में दस एनआईटी को खोलने का निर्णय लिया है। अब सभी राज्यों में एनआईटी हो गया है, यूटी में हो गया है। किसी राज्य की जनसंख्या 16 करोड़ है और किसी राज्य की चार करोड़ है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या राज्यों की जनसंख्या का पैरामीटर देखने के बजाय क्षेत्रीय असंतुलन को

देखते हुए रीजनल इम्बैलेंसिस को समाप्त करने के लिए जनसंख्या के आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ एनआईटी खोलने के बारे में विचार करेगी?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you I would like to highlight to the hon. Member of Parliament that we take into cognizance the changing demography of our country and also the regional imbalance challenge that he speaks of, and within the provisions and the governance structure of the NIT we try and ensure that students from all walks and all regions of our country are accommodated.

Example, Madam Speaker, is that through a project called Ishan Vikas we are inviting students of the North-East to partake in faculty and academia arrangements and activities across institutions of higher learning in the country like the IITs, NITs, IISERs; and we have even requested ISRO to accommodate our students.

(Q. 143)

डॉ. नैपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अब तक विश्वविद्यालयों में 96645 पद सृजित हैं और 26584 रिक्तियां हैं। रिक्तियां अधिक होने की वजह से विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति खराब हो गई है। इस कारण प्रत्येक वर्ष रिजल्ट खराब होता है, ... (व्यवधान) टीचर्स की नियुक्तियां कम हो रही हैं, रिटायरमेंट हो रही हैं, लेकिन आयोग द्वारा नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। यहां एकेडेमिक पूल भी है, नैट क्वालीफाइड होती हैं और पीएचडी होते हैं, उनकी सीधी नियुक्ति की जा सकती है।... (व्यवधान)

मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो नियुक्तियां आयोग और प्रदेश वाइज़ होती हैं, उसमें संशोधन द्वारा केंद्र द्वारा सीधी नियुक्तियां की जा सकें?

डॉ. रामशंकर कठेरिया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में अध्यापकों की शिक्षण और गैर - शिक्षण नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं जिसके कारण बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं।... (व्यवधान) यह बात बिल्कुल सही है और माननीय सदस्य ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 39 हैं। वर्तमान स्थिति में यह आंकड़ा 10441 है जबकि यह 16692 होना चाहिए था। 6251 पद रिक्त हैं। इसकी भरपाई की दिशा में आपने कहा है कि सीधे केंद्र सरकार नियुक्तियां करे। संघीय व्यवस्था में उनकी स्वयं की बॉडी है इसलिए यह कर पाना मुश्किल होगा।... (व्यवधान)

डॉ. नैपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी? कुछ ऐसी स्थान भी हैं जहां लड़कों की संख्या ज्यादा है और पद स्वीकृत हैं। क्या सरकार हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए सीधी नियुक्ति कराएगी?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam Speaker, through you I would like to tell the hon. Member of Parliament that to maintain autonomy and the autonomous status of all Central universities the Central Government cannot pool in and centralize recruitment, but we recognize the challenge vis-à-vis the gaps in faculty arrangements in institutions. Hence, on the 12th and 13th of September in Chandigarh I myself, Madam Speaker, conducted a two-day retreat with the Vice-Chancellors of all Central universities. We took the further action plan to fill up the faculty gaps.

I would also like to, Madam Speaker through you, tell the hon. Member that in the month of February the Visitor, which is the President of India, is also taking cognizance of this challenge and holding meetings with the Vice-Chancellors. We are recognizing the challenge and addressing it to the best of our abilities.

HON. SPEAKER: Shrimati Ranjeet Ranjan - Not present.

Shri R. Dhruv narayana - Not present.

SHRI B. VINOD KUMAR : Hon. Speaker Madam, the Minister has given a detailed reply wherein the vacancies are mentioned in Annexures 1 & 2. I would like to know from the hon. Minister about the steps taken with regard to part 'd' of the question. ... (*Interruptions*) The hon. Minister has given a detailed reply saying that the meeting of the Vice Chancellors was held. I would like to ask the hon. Minister whether salary is a constraint in recruiting the teachers because not only in the Central Universities, but even in IITs, IIMs and in medical colleges across the country, we are not attracting good lecturers and professors because of constraints of salaries. ... (*Interruptions*) The salary fixed by UGC is not attracting the teaching faculty. Is the Government taking any steps to increase salary, perks and other facilities? ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to tell the hon. Member that salary is not a constraint in hiring a faculty. There are areas where the faculty wants additional support vis-à-vis research and this in itself is discussed not only in meeting with vice chancellors. ... (*Interruptions*) In the discussions in IIT and NIT councils also, we took cognizance of the fact that we want even industry experts to come in as our faculty members. ... (*Interruptions*) UGC has provided for the same and the global initiative of academic network as directed by the hon. Prime Minister will also ensure that world reputed academicians professors come even to our central universities from next academic year and teach our students. ... (*Interruptions*)

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ... (व्यवधान) कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर में रिक्त पदों के बारे में माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहता हूँ। ... (व्यवधान) उन्होंने अपने उत्तर में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल मिलाकर 188 पदों के विरुद्ध 94 पदों को भरा गया है और लगभग 94 पद रिक्त हैं। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। ... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उदयपुर में एक राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है। ... (व्यवधान) वहाँ मात्र एक वी.सी. और एक चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। ... (व्यवधान) राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार को उसे भी टेक-अप करना चाहिए। ... (व्यवधान) वहाँ वी.सी. के अलावा और भी पदों को भरा जाए तथा उसे यू.जी.सी. ग्रांट मिले, यही मेरा निवेदन है। ... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय से यह कहना चाहूंगी कि रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के पास नहीं है। ... (व्यवधान) चूंकि यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में स्वतंत्र हैं। ... (व्यवधान) नियुक्तियाँ करने संबंधी इनकी जिम्मेदारी उन्हीं तक सीमित है, लेकिन केन्द्र सरकार निरंतर इस प्रयास में रहती है कि संवाद के माध्यम से हम यूनिवर्सिटीज को अवगत कराएँ कि कहाँ-कहाँ रिक्त स्थानों को भरने की शीघ्र कोशिश करनी चाहिए। ... (व्यवधान) उदयपुर के जिस संस्थान के बारे में माननीय सांसद महोदय ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है, ... (व्यवधान) यदि वे लिखित रूप में अपनी चिन्ता मुझ तक पहुंचाएंगे तो मैं यथासंभव सहायता करने का प्रयास करूँगी।

Q. 144)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, आज देश में अनेक ऐसे जिम्मेदार एवं जागरूक व्यक्ति हैं, जो व्यापक जनहित में सतर्कता अधिकारियों को मुखबिर बनकर सूचना देते हैं। उनकी सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है। आम जन भी भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी काम या कानूनी व्यवस्था संबंधी कई जानकारियां पुलिस या मुख्य सतर्कता अधिकारी को देते हैं, जो देशहित में है, परन्तु कई मामलों में देखा गया है कि सूचना देने वाले ऐसे व्यक्ति प्रताड़ना एवं हिंसा के शिकार हो जाते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रहनी चाहिए, जो कानूनसम्मत है, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस, विशेषकर सीतामढ़ी इसका एक उदाहरण है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर के दौरे पर थी, मुझे सैकड़ों लोग मिले, उन लोगों ने मुझे एक पेन ड्राइव भी दिया, जिसमें अपराधियों द्वारा धमकी, जबरन वसूली एवं हत्या करने की बात रिकॉर्डेड है। अगर सदन चाहे तो मैं उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना समय-समय पर सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक को दी गयी, परन्तु उसका परिणाम यह निकला कि इसकी सूचना अधिकारियों को मिल गयी और पीड़ित परिवार को अपनी जान बचाने के लिए गांव से पलायन करना पड़ा। ...(व्यवधान) स्वयं मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब अपने शस्त्र छीनने वालों के संबंध में जब बरगिनिया पुलिस को सूचना दी, तब उल्टे मेरे ऊपर आरोपियों द्वारा गलत केस दर्ज करा दिया गया। जब सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य लोग कैसे बच सकते हैं। सीतामढ़ी में हाल-फिलहाल में दर्जनों हत्याएं होने एवं सूचना देने के बावजूद पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिल रही है यानि उनकी संलिप्तता उजागर हुई है। लोग डरे हुए हैं, ...(व्यवधान) वरिष्ठ अधिकारियों के एवं पुलिस के ...(व्यवधान) खतरा है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि सूचना देने वालों को सुरक्षा देने के लिए बिहार सहित पूरे देश में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गयी है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, माननीय सांसद द्वारा व्यक्त की गयी चिंता उचित है और हमारे ध्यान में है। सरकार जहां एक ओर प्रशासन में पारदर्शिता रखने को प्राथमिकता देती है, उसके प्रतिबद्ध है, वहीं साथ ही साथ इस बात की भी चिन्ता करती है कि पब्लिक इंटरैस्ट डिसक्लोजर नियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करता है, उसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाए ताकि जांच की प्रक्रिया आरंभ होने के उपरांत उसको किसी भी प्रकार के दबाव अथवा खतरे का सामना नहीं करना पड़े। माननीय सदस्या ने जिस एक विशेष घटना की ओर संकेत किया है, यद्यपि उसका इस प्रश्न के साथ सीधा संबंध नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह इसका लिखित विवरण देंगी तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, मैंने इसके बारे में लिखित रूप में प्रधान मंत्री जी को दिया है।

आपने जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर सुरक्षा संकल्प के तहत सीवीओ द्वारा कंप्लेंट निपटाने की प्रक्रिया की जानकारी दी है, जो संतोषजनक है, परन्तु गत तीन वर्षों से जो 18 मामले आयोग की जांच के अधीन हैं, उनकी जांच पूर्ण होने की किसी समय-सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। अगर भ्रष्टाचार का खात्मा करना है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि आयोग के अधीन जिन मामलों की जांच लम्बित है, उन मामलों की जांच समय से पूरी हो और उस पर आगे की कार्रवाई हो, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है? ...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, आदरणीय सांसद जी की चिंताओं का संज्ञान लेते हुए, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि गत तीन वर्षों के आंकड़े, जिनकी ओर उन्होंने संकेत किया है, उनके अनुसार हमें 3202 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच के उपरांत 343 शिकायतों के बारे में प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है, उनमें से 144 ऐसे मामले थे, जिनमें कोई ठोस सबस्टेंस नहीं पाया गया, अतः वे फाइलें बंद कर दी गयीं। 36 ऐसे केसेज हैं, जिनमें आगे की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। दण्ड इत्यादि की भी प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। 163 केसेज ऐसे हैं, जिनमें यह प्रक्रिया जारी है। जहां तक सीमाबद्ध अथवा डेडलाइन की बात है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में गोपनीयता के पक्ष को बहुत चिंता के साथ रखा जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जाता है। जब भी हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस बंद लिफाफे को खोलने का अधिकार, सैक्शन ऑफिसर से नीचे के अधिकारी को नहीं होता और जब भी उसे खोलना होता है, तो एक और अधिकारी की उपस्थिति में खोलना होता है। जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, वह भले ही चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो या संबंधित अधिकारी हो। उसके बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता कि वह कोई फर्जी शिकायत करने वाला तो नहीं है, जब स्थापित हो जाती है, तो उसका नाम हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक डमी नम्बर लगाकर प्रक्रिया आरम्भ होती है। इस घटना और प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है क्योंकि हमारी प्राथमिकता रहती है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार के खतरे, दबाव या धमकी का सामना न करना पड़े।

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह इसमें है और उसी के प्रति मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुल मिलाकर 344 में से केवल 2 केसेज सी.बी.आई. को रैफर हुए हैं। अब इस प्रावधान को 10 वर्ष हो गये हैं। दोनों पक्ष उपयोग और दुरुपयोग चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि 10 साल के पश्चात, इस प्रावधान का रिव्यू

करने की आवश्यकता है। इसमें फुल-प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, सिर्फ 2 केस सी.बी.आई. को जाते हैं तो क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है या फिर प्रकरण अधिक लम्बित रहते हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, केस और शिकायत की मैरिट के आधार पर निर्णय किया जाता है। इसमें संबंधित विभाग तथा विजिलेंस कमीशन का भी संज्ञान लिया जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार की जांच, किस संस्था या एजेंसी के अंतर्गत करवाई जानी उपयुक्त रहेगी।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.45 a.m.

11.37 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Forty
Five Minutes past Eleven of the Clock.*

11.45 hrs

The Lok Sabha reassembled at Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने यह विषय उठाया था। मैंने और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि उनसे माफी मंगवा दी गयी है। इस तरह की बातें आगे नहीं बढ़ायी जाती हैं, क्योंकि यह सदन के बाहर की बातें हैं, फिर भी मंत्री जी सदन में माफ़ी मांग चुकी हैं। मुझे लगता है कि सभाओं में मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। अगर आप बार-बार इसका जिक्र करेंगे तो हम सभी लोगों के कहीं न कहीं इस प्रकार के भाषण निकलेंगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यह बात अब आप यहीं रहने दीजिए, कल माफी हो चुकी है और आज आपने फिर अपना विरोध प्रधानमंत्री जी के सामने दर्ज कर दिया है। अब जो करना है, उसको वह देखेंगे। प्लीज़, अब हाउस को चलने दीजिए, यही मेरा आप सभी से निवेदन है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से नहीं होता है। अब आप क्या बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी जो रिक्वेस्ट थी, वही बात मैंने अभी कही है और कल इस विषय पर माफी भी हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कृपया मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी भी रिक्वेस्ट एक दिन के लिए मान लीजिए। फिर कभी आप बोलेंगे तो उल्लेख कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बोलने का मौका दिया था।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ज़ीरो ऑवर में अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, आपने जो कहा है, वह तो कल हुआ था, लेकिन मैंने उस बात को इसलिए उठाया था, क्योंकि उसके बाद दो-तीन स्टेटमेंट और आए थे और कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्टेटमेंट में अपने लोगों से कहा कि यूपी की दृष्टि से मंत्री को शक्ति दिलाना ज़रूरी है।... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : अध्यक्ष जी, हमने कांग्रेस के नेता को मौका दिया, उन्होंने जो कहना था, कह दिया है। मेरी पूरे सदन से रिक्वैस्ट है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : मेरा सदन से निवेदन है, जैसा कि अभी खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री जी ने अपना अभिप्राय इस बारे में व्यक्त किया है। कल जब इश्यू यहां उठाया गया था... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी बात सुन लीजिए। आप कृपया करके बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों को मर्यादा और परम्पराओं का आदर करना चाहिए। आपके बोलते समय हम बैठ कर सुनेंगे और हमारे बोलते समय आपको बैठ कर सुनना चाहिए। आप बाद में बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग अनुभवी हैं, हम से भी ज्यादा अनुभवी हैं।

मेरा कहना यह है कि कल यह विषय उठाया गया। तुरंत मैडम, आपने संकेत दिया तो मैंने मंत्री जी से बात की। मंत्री जी भी खुद इस बात को रिएलाइज कर रहीं थीं। वह पहली बार यहां चुनकर आई हैं। गांवों के इलाके की महिला हैं और इसीलिए फिर भी उन्होंने आकर कहा कि ऐसे नहीं कहना था। गलती हो गई, मैं इसको स्वीकार कर रही हूं और माफी चाहती हूं, आकर इतना कह दिया। यह विषय वहीं समाप्त हो गया। फिर सदन आगे चला। अभी आज अचानक क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

दूसरे, जैसे आपने रिमार्क किया, मैं सभी को बताना चाहता हूं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दोनों तरफ से कमेंट नहीं होगा। यहां से भी नहीं होगा। आपके मंत्री सक्षम हैं। आप उनकी बात तो सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : मैडम, मैं आपके द्वारा श्री खड़गे जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आपकी सरकार में एक मंत्री ने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या बोला था और बाद में आपकी पार्टी ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। फिर बाद में कुछ समय

के बाद श्री मनमोहन सिंह जी को वह काम करना पड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे, तृणमूल के एक एम.पी. ने ...(व्यवधान)

11.52 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष जी, एक श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, एक तपस पॉल, इस सदन के एम.पी. ने कहा ...(व्यवधान) "महिलाओं को रेप करने के लिए कहा" ...(व्यवधान) यह भावना में हुआ।...(व्यवधान) उस गलती को स्वीकार करना, ममता जी ने स्वीकार किया...(व्यवधान) और उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया।...(व्यवधान) उन्होंने कहा "Should I kill him?" These were the words used. इसलिए इसको यहां पर ही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : हो गया। सबकी तरफ से हो गया।

...(व्यवधान)

11.53 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS... Contd.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न- 145, श्री कौशलेन्द्र कुमार।

(Q. 145)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय प्रधान मंत्री जी आज यहां बैठे हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने जो प्रश्न रखा है, उसका मूल प्रश्न यह है कि यूपीएससी की परीक्षा में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वहां से बोलने में तकलीफ हो रही हो तो आप इधर आ जाइए. मैं एलाउ कर रही हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि यूपीएससी की परीक्षा में पिछले साल पूरे देश भर में हिन्दी भाषी लोगों ने यह प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठी चली।... (व्यवधान) उसी के संदर्भ में मैंने यह प्रश्न किया था ... (व्यवधान) मेरी मुख्य मांग है कि हिन्दी के अनुवाद को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जो आंदोलन किया, क्या सरकार इंग्लिश को हटाने का विचार रखती है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं संसद को अवगत कराना चाहूंगा और जैसा कि हम सब जानते हैं, ... (व्यवधान) इस विषय को लेकर पिछले कुछ मास से चर्चा चल रही है, संसद के पिछले सत्र में भी इसका जिक्र आया था।... (व्यवधान) अब स्थिति यह है कि गत 26 नवम्बर को सांसदों के ही सुझावों पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों का संज्ञान लिया गया और अन्ततः यह निर्णय किया गया कि डीओपीटी की ओर से एक संक्षिप्त पत्र निकालकर उन्हें पूरे क्रोनोलॉजी ईवेंट से अवगत कराया जाएगा।... (व्यवधान) उसमें डीओपीटी की तरफ से कोई सुझाव या पक्ष नहीं रखा जाएगा। मात्र यह बताने का प्रयास रहेगा कि किस- किस समय पर इस परीक्षा प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन हुए, किस-किस समिति के सुझावों के आधार पर हुए और उसका संज्ञान लेते हुए नेतागण अगले दो सप्ताह के भीतर हमें अपने लिखित सुझाव देंगे ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। उसमें अनुवाद का विषय भी शामिल है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है।

मैंडम, जब से सी-सैट आया है, तब से यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में गिरावट आई है, अब ग्रामीण परिवेश के बच्चे यू.पी.एस.सी. में नहीं आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सी-सैट को फिर से समाप्त करने के लिए आपने कोई विचार किया है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब यह विषय चर्चा में आया तो उन सब सुझावों का संज्ञान लेने के उपरांत इसी संसद में एक वक्तव्य देने के उपरांत सी-सैट में 22 अंकों के अंग्रेजी के प्रश्न भाग को निकाल दिया गया और परीक्षा के मूल अंकों की संख्या में उसे शामिल न करने का निर्णय किया गया। अब सी-सैट रखा जाए कि नहीं रखा जाए, यह भी एक विषय है, जिसे सर्वदलीय बैठक में रखा गया। हमारा नेताओं से और भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह निवेदन है कि वे लिखित रूप में अपने सुझाव दें और जिन विषयों को संज्ञान में रखा गया है, उनमें एक विषय सी-सैट को रखने अथवा नहीं रखने का भी है।

SHRI THOTA NARASIMHAM : Madam Speaker, I would like to ask the Minister, through you, whether it is a fact that science and mathematics students are scoring much higher as compared to arts students in CSAT. Have you conducted any scientific study on this? ... (*Interruptions*)

The main purpose of language is communication. Students of rural India are more familiar and comfortable with their local language than English. Does it not affect the fate of the rural students? How are you going to protect the interests of the civil service aspirants from rural areas? ... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon. Member's concerns are well taken. This also has been the opinion of certain sections, both inside as well as outside the House. ... (*Interruptions*) There has been an opinion that some of the science and mathematics aspirants have an advantage over those who opt for humanities. ... (*Interruptions*)

Before coming to any conclusion, we are actually approaching this issue with an open mind. Therefore, in keeping with that spirit, an all-party meeting was held. After we receive a written document from you, this would also be taken up for further analysis by the experts concerned. ... (*Interruptions*)

Meanwhile I would just like to inform you that after the last Session of Parliament, the UPSC also had formed an Expert Committee under the chairmanship of Prof. Bhattacharya, which has also given its recommendations, which are under our study. ... (*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि हमने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के नाम पर मनोनीत किया। जितने भी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अफसर बनते हैं, जब उन्हें राज्यों का कैंडर मिलता है तो अगर बिहार के आदमी को केरल का कैंडर मिलता है तो उसे वहां मलयालम सीखनी पड़ती है, कर्नाटक कैंडर मिलने पर कन्नड़ सीखनी पड़ती है और अगर कर्नाटक या मलयालम इलाके के आदमी को यू.पी. कैंडर मिलता है तो उन्हें हिन्दी सीखनी पड़ती है। यह हिन्दी और अंग्रेजी का मसला नहीं है। किन्तु जो हमारे ग्रामीण इलाके के छात्र हैं, उनका जो कैलिबर है, उसे अंग्रेजी रोकती है या पीछे की तरफ खींचती है। इसलिए क्यों न रीजनल भाषाओं में यह प्राथमिकता दी जाए कि जो आई.ए.एस., आई.पी.एस. के एग्जामिनेशन हों, उनमें रीजनल भाषा को प्राथमिकता दी जाए और अंग्रेजी को कम महत्व दिया जाए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, यह विषय हमारे संज्ञान में आया है और एक सुझाव यह भी आया कि जहां ऑप्शनल भाषाएं अंग्रेजी और हिन्दी होती हैं, उसके अतिरिक्त वे तमाम 22 भाषाएं, जो संविधान के आठवें शेड्यूल में हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाए। परंतु इसमें कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ रही थीं, इसीलिए इसे एक एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और सर्वदलीय बैठक में यह अनुरोध भी किया गया कि इसके ऊपर यदि कोई लिखित पत्रक हमें प्राप्त हो जाता है तो वह भी हम उस एक्सपर्ट कमेटी के हवाले कर देंगे।

SHRI V. ELUMALAI : Madam Speaker, I would like to know whether the Government is considering reduction of age limit for civil service aspirants. Does the Government have any plan to reduce the number of attempts in civil service examination for OBCs and Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Thank you....

(Interruptions)

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a very relevant question. I am sure this is also a question which is bothering the minds of several other hon. Members because incidentally just a few days back there was a report in a section of the Press.... *(Interruptions)* There was a report in a section of the media saying that the DoPT or some other Department has reduced the age limit of the IAS aspirants but we have since then refuted this.... *(Interruptions)*

As of today, I would like to inform you that the age limit for the general category is 32 years with six attempts; the age limit for the OBC category is 35

years with nine attempts and the age limit for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe category is 37 years with unlimited attempts.... (*Interruptions*) The concern of the hon. Member is well taken because it was generated by a report in a section of the Press which we have since refuted.... (*Interruptions*) Therefore, as it is, it stands at the limit of 32, 35 and 37 years with unlimited attempts for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe category.

HON. SPEAKER: Question Hour Over.

12.00 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House. Shri M. Venkaiah Naidu.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
- (3) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 924/16/14]

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD):

I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Registry, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Registry, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 925/16/14]

(2) A copy of Notification No. S.O. 2905(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th November, 2014, including 15 products, mentioned therein, to the Schedule of the Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012 issued under sub-section (1) of Section 10 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986.

[Placed in Library,See No. LT 926/16/14]

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI):

I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.T. Chandigarh Sarva Shiksha Abhiyan Society, Chandigarh, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.T. Chandigarh Sarva Shiksha Abhiyan Society, Chandigarh, for the year 2013-2014.

[Placed in Library,See No. LT 927/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Tamil Nadu, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Tamil Nadu, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library,See No. LT 928/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajasthan Council of Secondary Education (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Jaipur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajasthan Council of Secondary Education (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Jaipur, for the year 2012-2013.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library,See No. LT 929/16/14]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan of the Rajiv Vidya Mission, Hyderabad, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan of the Rajiv Vidya Mission, Hyderabad, for the year 2012-2013.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library,See No. LT 930/16/14]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the UEE Mission Delhi, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the UEE Mission Delhi, Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library,See No. LT 931/16/14]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN):

I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Bioresources and Sustainable Development, Imphal, for the year 2013-2014.

[Placed in Library,See No. LT 932/16/14]
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Immunology, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library,See No. LT 933/16/14]
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Cell Science, Pune, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 934/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 935/16/14]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 936/16/14]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Centre for Biotechnology, Gurgaon, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Centre for Biotechnology, Gurgaon, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 937/16/14]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 938/16/14]

- (2) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 939/16/14]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 940/16/14]

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): देश में ऐसी अशांति रखने की कोशिश की जा रही है। ... (व्यवधान) उसका प्रोटेस्ट करते हुए हम वॉकआउट करते हैं। ... (व्यवधान)

12.03 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shrimati Sonia Gandhi and some other hon. Members left the House.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, it is a *sub judice* issue. The hon. Court will decide it.... (*Interruptions*) In protest, we walk out.

12.04 hrs

*At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other
hon. Members left the House.*

12.04 ¼ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

2nd Report

DR. M.THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.04 ½ hrs.**STATEMENTS BY MINISTERS****(i) Incident in District-Sukma, Chhattisgarh which happened on 01.12.2014 ***

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, दिनांक एक दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बहुत ही पीड़ादायी और निंदनीय घटना घटी थी। उससे संबंधित स्टेटमेंट में सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, माओवादी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस एवं केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा लगातार इस समस्या से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सी.पी.आई. (माओवादी) काडर के दस्तों की गतिविधियों की खुफिया जानकारी के आधार पर, सी.आर.पी.एफ. ने 16 नवंबर, 2014 से एक वृहद अभियान छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा क्षेत्र में कई चरणों में चलाया।

इस अभियान में सी.आर.पी.एफ. के 2253 एवं राज्य पुलिस के 224 कुल 2477 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस अभियान के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 17.11.2014 और 21.11.2014 को कई बार सुरक्षाबलों एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर, जिनमें खुफिया सूचनाएं एवं मीडिया के स्रोत सम्मिलित हैं, दिनांक 21.11.2014 को 12 माओवादियों के मारे जाने की सूचनाएं हैं, लेकिन इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इन चरणों में कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, जिनका उपचार कराया गया।

इस ऑपरेशन का तीसरा चरण दिनांक 27.11.2014 को शुरू हुआ था। इस घने जंगली क्षेत्र की Combing के पश्चात जब सी.आर.पी.एफ की 223 बटालियन एवं कोबरा की 206 बटालियन के सुरक्षाकर्मी अपने कैंप को वापस लौट रहे थे, माओवादियों ने कसलपार गांव के निकट उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह घटना 01.12.2014 को दिन में लगभग 10:30 बजे घटित हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी हमला किया और पूरी बहादुरी के साथ माओवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। यह मुठभेड़ लगभग तीन घंटे चली। इसमें 223 बटालियन के 14 सुरक्षाकर्मी शहदी हो गए एवं अन्य 14 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। जैसे ही यह मुठभेड़ शुरू हुई, सीआर.पी.एफ. की निकटस्थ अन्य टुकड़ियाँ भी घटना स्थल पर मदद के लिए पहुंच गईं।

* Placed in Library, See No. LT 941/16/14

घायल सुरक्षाकर्मियों को चिंता गुफा बेस कैंप में ले जाया गया और इसके उपरान्त उपचार के लिए जगदलपुर एवं रायपुर भेज दिया गया। इस हमले में माओवादी मृतक जवानों के शस्त्र एवं गोला बारूद ले जाने में सफल हो गए।

आज दिनांक 02.12.2014 को दो एम.आई. - 17 हैलीकॉप्टरों के द्वारा शहीद एवं घायल सुरक्षाकर्मियों को चिंता गुफा से जगदलपुर एवं रायपुर लाया गया है।

अध्यक्ष महोदया, घटना की जानकारी मिलते ही मैं कल प्रातः वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर गया और स्थिति की समीक्षा की। सी.आर.पी.एफ. के महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं।

मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सरकार माओवादी उग्रवाद से पूरी दृढ़ता से निबटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति क्रियान्वित की जा रही है। इसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास से संबंधित उपाय एवं आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित कदम शामिल हैं। सरकार की नीति के परणामस्वरूप माओवादियों के हौसले कमजोर हुए हैं। उनके कैंडर के द्वारा आत्मसमर्पण करने की संख्या में इस वर्ष काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 से माओवादी हिंसा की घटना में निरंतर गिरावट आ रही है, जो इस वर्ष भी जारी है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपने सुरक्षा बलों को सभी संभव साधन मुहैया कराएंगे और तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे, जब तक कि इस समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन न हो जाए। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें जब भी शांति व्यवस्था कायम करने, उग्रवाद के संकट, प्राकृतिक आपदा आदि से निबटने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सिज़ की मांग करती हैं, तो सामान्यतः मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विचार करके फोर्स उपलब्ध कराती है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सिज़ बराबर राज्य सरकारों के निर्देशन पर कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करती हैं। हम राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी सभी संभव उपाय कर रहे हैं।

दिनांक 01.12.2014 की इस घटना में शहीद हुए सभी सुरक्षाकर्मियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I wish that our friends from the Opposition were also here when hon. Home Minister is making statement about the dastardly attack on our CRPF personnel in Chhattisgarh. The incident took place in Chhattisgarh. He had been there and has since come back. They had given notices. So, I expected them to be here so that they can hear the Minister and also offer their suggestions. Unfortunately, that could not happen.

Secondly, Madam, I am trying to put one thing on record and as a Minister for Parliamentary Affairs, I have a responsibility also. If 20 people start shouting that *tanashahi nahin chalegi*, then should 520 people keep quiet? They are keeping quiet helplessly. किसकी तानाशाही है? आप चेयर पर हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि कुछ लोग मिल कर पूरे सदन को डिकटेट करें, हम बाकी लोग चुप बैठें, यह कितने दिन चलेगा? इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए।

मैडम, हम इसी समाज में रह रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि मेरे मन में भी वेदना है, पीड़ा है, प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा कि उन्हें मंत्री का वक्तव्य स्वीकार्य नहीं है। मंत्री जी ने सदन में आकर दिल से माफ़ी मांगी, बाहर भी जाकर उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी ऐसा करें तो यह ठीक नहीं है। महिला एम.पी. मुझसे आकर कह रही हैं कि हमें मौका दीजिए, हम बोलना चाहते हैं। हमारी महिला मंत्री, साथी के ऊपर हमला हो रहा है, हमें बोलने दीजिए। मैं महिला, पुरुष, दलित, पिछड़ा आदि में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन समाज में ऐसी स्थिति है। पहले ही दिन मैंने आपको सब्मिट किया था और अपोजिशन को भी कहा कि हम किसी भी विषय के बारे में किसी भी स्तर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज दो मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, गृह मंत्री जी हैं और विदेश मंत्री जी दौरे के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं। नारेबाजी करना, बीच में प्रधानमंत्री जी का नाम लेना ठीक नहीं है। We have got such a massive mandate. The Opposition go on inserting the Prime Minister and take his name everyday. Madam, I would like to put the record straight. The Minister is not tainted but my other friends from the Opposition are trying to paint the Minister as tainted.

महोदया, तीसरी बात मैं आदरपूर्वक सभ्मिट करना चाहता हूँ, मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी इसी हाउस में एक मंत्री जी ने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग किया। वह बहुत गलत था। सबने उनसे कहा कि आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। उन्होंने इन्कार कर दिया और बाहर भी बोला। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री, मैं उनका आदर करता हूँ, श्री मनमोहन सिंह जी को वह काम करना पड़ा। वह रिकार्ड में है। अब वे कह रहे हैं कि वे मंत्री नहीं हैं। उस समय वे मंत्री थे। एक सदस्य दूसरी पार्टी के हैं, अभी सुदीप बाबू मुझे बता रहे थे कि वह मैटर कोर्ट में है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। एक एम.पी. ने कहा कि सी.पी.एम. वालों ने हमारे ऊपर हमला बन्द नहीं किया तो मैं अपने लोगों को कहूँगा कि उनके ऊपर हमला करें और अपने पुरुषों को बताऊँगा कि उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करें। उस एम.पी. ने ऐसा कहा है। उन्होंने आउट ऑफ कन्ट्रोल में आकर ऐसा कहा होगा, लेकिन यह निन्दनीय है। मुख्यमंत्री ममता जी ने अपने विवेक से, अपने संस्कार से उसको कन्डेम किया। कल ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया। कल उस विषय पर यहाँ चर्चा हुई, आपने अनुमति दी और तुरन्त हमने रिस्पॉन्ड किया और चर्चा समाप्त हो गयी। आज अचानक क्या हुआ? कुछ पॉलिटिकल गाइडेंस या कोई पॉलिटिकल कारण से सदन का इस तरह बाधित रहना अच्छी बात नहीं है। यह मेरी सभी पार्टियों से, कांग्रेस से प्रार्थना है। हम पार्लियामेंट्री नियम के अनुसार किसी भी विषय के बारे में किसी भी स्तर पर बहस करने के लिए तैयार हैं। कृपया आप भी उन लोगों को सलाह दीजिए, मैं भी उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं भी यहाँ से बार-बार बोलती हूँ और चर्चा भी करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी खेद होता है कि मुझे हंगामे में सदन चलाना पड़ता है। सभी लोग मेहनत करके, अभ्यास करके प्रश्न पूछते हैं और वे मंत्रियों से उत्तर चाहते हैं। इसलिए प्रश्नकाल चले, ऐसा सबका आग्रह रहता है। मैं भी उसे ध्यान रखती हूँ। मुझे वास्तव में अच्छा नहीं लगता कि मैं हंगामे में सदन चलाऊँ। मैं सबका सहयोग चाहती हूँ। मैं बार-बार निवेदन भी करती हूँ। हर एक के अपने-अपने पॉलिटिकल भाषण में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, मगर हर एक को अपना-अपना ध्यान रखना चाहिए। हम सब समझदार लोग हैं।

12.14 hrs**(ii) Prime Minister's recent visits abroad***

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किये गये विदेश के दौरों और सदन के पिछले सत्र के बाद से हमारे विदेशी सम्बन्धों में विस्तार पर मैं एक वक्तव्य देना चाहती हूँ।

अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि भारत में सम्पन्न हुए ऐतिहासिक आम चुनावों ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति एक नई रूचि जागृत की है और विश्व का भारत में विश्वास फिर से बहाल हुआ है। जब विश्व अनिश्चय और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित भारत की नई सरकार ने विश्व में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास की आशा को अभूतपूर्व बल मिला है और विश्व में शान्ति, स्थायित्व और सम्पन्नता के लिए भारत के व्यापक, असरदार और सार्थक योगदान के प्रति एक नई आशा जगी है।

अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने सदा एक ऐसी विदेश नीति पर बल दिया जो आगे बढ़कर विश्व मामलों में सक्रियता दिखाने और अभिनव प्रयोगों से युक्त हो और जो हमारी सरकार के आर्थिक विकास के प्राथमिक उद्देश्य से सम्बद्ध हो। पूँजी, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ऊर्जा, बाजार और दक्षता के लिए भारत को आज एक सुरक्षित परिवेश, शान्तिपूर्ण पड़ोस, स्थायित्वपूर्ण विश्व और एक खुली और मजबूत विश्व व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारी नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और सभी को साथ लेकर चलने की चिरकालीन परम्परा से जुड़ी हुई है और वसुधैवकुटुम्बकम् के आदर्श से प्रभावित है।

भारत की विदेश नीति ने नए मुकाम हासिल किए हैं और नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे इन प्रयासों पर विश्व ने अभूतपूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अध्यक्ष महोदया, संसद के पिछले सत्र के बाद प्रधानमंत्री जी ने जापान, अमेरिका, म्यांमार, आस्ट्रेलिया, फीजी और नेपाल की यात्रा की और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भाग लिया। हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी ऐबट और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सितम्बर माह में भारत की यात्रा की। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सभी महाद्वीपों के 45 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भारत-आसियान, पूर्वी एशिया, जी-20 और सार्क शिखर वार्ताओं में भाग लिया। ये सभी शिखर वार्ताएं हमारे क्षेत्र, एशिया और विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फीजी प्रशांत महासागर क्षेत्र का एक प्रभावी राष्ट्र है और इसकी 37 प्रतिशत आबादी

* Placed in Library, See No. LT 942/16/14

भारतीय मूल के लोगों की है, फिर भी, आप हैरान होंगे, पिछले 33 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली फीजी यात्रा थी। फीजी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले भारतीय नेता बने जिन्होंने प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के साथ बैठक की। प्रशांत महासागर देशों के राष्ट्र हमारी चुनौतियों में हमारे साझेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। इस अनुपम पहल को प्रशांत महासागर देशों के नेताओं ने हृदय से सराहा। यह भविष्य में इन देशों के साथ हमारे सतत् सहयोग की शुरुआत है।

प्रधानमंत्री जी को आस्ट्रेलिया की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ - वे इस प्रकार का गौरव प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वे फीजी द्वीप में नए संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की बहाली के बाद चुनी गई संसद को संबोधित करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बने। दोनों संबोधनों को मेजबान देश और विश्व भर में खूब सराहा गया।

प्रत्येक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की, जिसे पहले किसी भारतीय नेता की यात्रा के दौरान नहीं देखा गया। यह हमारे उस विश्वास को परिलक्षित करता है जिसमें आधुनिक काल में राष्ट्रों के बीच संबंध उनकी राजधानियों और आधिकारिक मुलाकातों से कहीं आगे बढ़कर है।

अध्यक्ष जी, हमारे विदेशी संबंध मात्र गौरव का प्रतीक ही नहीं हैं, अपितु यह परिणामों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हम जापान के साथ अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक ले गए हैं। चीन के साथ बकाया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में गति को बहाल किया है। आस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को एक नई दिशा दी है और हिचकिचाहट भरी "लुक ईस्ट" नीति को "एक्ट ईस्ट" नीति में तब्दील किया है।

हमारी सरकार अगले दौर के सुधारों के जरिए आधारभूत ढांचे और निर्माण क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी में है। ऐसे समय में हमें जापान से अगले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3.5 खरब येन - तकरीबन 35 अरब अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता की वचनबद्धता मिली है। चीन के साथ हमने दो औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने और 20 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के समझौते किए हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अमरीकी कंपनियों द्वारा 42 अरब अमरीकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आशा है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हमने नेपाल के साथ साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश किया है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। नेपाल के साथ महाकाली संधि के दो दशकों के पश्चात 5600 मेगावाट वाली बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना हेतु हमने पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया है।

इसके अलावा हमने नेपाल के साथ एक नया ऊर्जा व्यापार समझौता किया है। दो भारतीय कंपनियों को 900-900 मेगावाट जलविद्युत उत्पन्न करने का परियोजना लाइसेंस मिला है। दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा और पर्यटन को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन समझौता किया है जो काफी समय से लंबित था।

अध्यक्ष जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत से विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा के हमारे हितों की रक्षा और दोहा विकास चक्र की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस पहल से विश्व व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है जो भारत के हित में है और साथ ही हमने गरीबों के हितों की रक्षा हेतु उनके प्रति हमारे मौलिक दायित्वों में किसी प्रकार की कमी किये बिना भारत के हितों की रक्षा की है।

हमारा ध्यान केवल निर्माण और आधारभूत ढांचे पर ही केंद्रित नहीं है। विदेशों में प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र हित के बिन्दुओं पर भी ज़ोर दिया है। जैसे- दक्षता के विकास में सहयोग को आगे बढ़ाना, बीमारियों से लड़ने के लिए उन्नत चिकित्सीय अनुसंधान में सहयोग जैसे मलेरिया और टीबी के अनुसंधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करना, जैसे खाद्य सुरक्षा जैसे हमारे किसानों के फायदे के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि अनुसंधान में सहयोग करना, जैसे शिक्षा जैसे अगले दौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग पर समझौता करना, और भारत में पढ़ाने के लिए 1000 उच्च अमेरिकी प्राध्यापकों को भारत लाने की योजना बनाना।

अध्यक्ष जी, क्योटो-वाराणसी के बीच विकासात्मक सहयोग की व्यवस्था, अहमदाबाद-ग्वांगझू और मुम्बई-शंघाई शहरों के बीच सहयोग संबंधी समझौते और अमेरिका के साथ तीन स्मार्ट शहरों को विकसित करने की योजना ऐसी है, जिससे भारत के तीव्र शहरीकरण के अवसरों पर काम किया जा सके और इससे उत्पन्न चुनौतियों को सुलझाया जा सकेगा।

अध्यक्ष जी, बहुराष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरम हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण मंच हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रधान मंत्री जी का हिन्दी में संबोधन भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के उनके आह्वान से इस दिशा में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयासों को गति मिली है और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के आह्वान को व्यापक समर्थन मिला है।

अध्यक्ष जी, ब्रिस्बेन में जी-20 राष्ट्रों की शिखर वार्ता के दौरान भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखा। प्रधान मंत्री जी ने काले धन के खिलाफ सामूहिक रूप से अन्तरराष्ट्रीय कार्यवाही पर बल दिया। उन्होंने विकासशील देशों में अवसंरचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए कम खर्च वाले सामूहिक प्रयासों और नवीन समाधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक नई वैश्विक पहल का प्रस्ताव किया। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और विश्व व्यापार समझौतों के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का माध्यम बनने और गुटों में बंटने के खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया।

दस राष्ट्रों का आसियान समूह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इन राष्ट्रों में रहती है और भारत और चीन के बाद यह दुनिया की तीव्र गति से विकसित हो रही तीसरी अर्थव्यवस्था है। म्यांमार में भारत-आसियान शिखर वार्ता में हमारे आसियान के सहयोगियों के मध्य इस बात को लेकर एक नयी आशा और उत्साह था कि नवीन सुधारों से युक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और आसियान राष्ट्र समूह के मध्य एक गहरी साझेदारी की नींव रखेगी, जिससे हमारे इस साझा क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और संपन्नता का एक नया दौर शुरू होगा।

प्रधान मंत्री जी ने ने-पी-दों की इस यात्रा का लाभ उठाते हुए हमारे इस महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार के नेतृत्व के साथ मजबूत साझेदारी की अपनी वचनबद्धता दोहराई।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी का हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साझा भविष्य में मजबूत विश्वास है जो उनके द्वारा उठायी गयी कई ठोस पहलों से परिलक्षित होता है - पड़ोसी राष्ट्रों के नेताओं का 26 मई के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना, अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुनना, नेपाल की उनकी यात्रा जो पिछले सत्रह वर्षों में भारत के किसी प्रधान मंत्री की हमारे इस पड़ोसी राष्ट्र की पहली यात्रा थी।

काठमांडू में 26-27 नवम्बर के बीच आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने दक्षिण एशिया में साझा संपन्नता के अपने दृष्टिकोण को रखा। उन्होंने इस क्षेत्र के सबसे बड़े राष्ट्र और इसके मध्य में स्थित राष्ट्र होने के कारण इस क्षेत्र में आपसी सहयोग और दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सार्क के माध्यम से और इसके बाहर सामंजस्यता विकसित करने की ओर भारत के मजबूत इरादों की तरफ

ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री जी के दृष्टिकोण और इस क्षेत्र के लिए की गयी पहलों से दक्षिण एशिया के हमारे सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक नयी आशा का संचार हुआ है। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह कहा है कि हम अपने विकसित भविष्य की नींव एक सुरक्षित भारत पर ही रख सकते हैं।

प्रत्येक अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक स्थाई और शांतिपूर्ण एशिया और इसके आस-पास के समुद्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वीकार्यता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें समुद्रीय सुरक्षा भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने साइबर सुरक्षा और अन्तरिक्ष सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए खतरे की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम एशिया में इस्लामिक राष्ट्र के उभार और इससे विश्व पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ताओं को साझा किया। उन्होंने आतंकवाद के वैश्विक खतरे से निबटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ विभिन्न आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को अलग-थलग करने के लिए विश्व स्तर पर एक व्यापक नीति बनाने की सलाह दी, जिससे कि इन आतंकवादी गुटों के प्रायोजकों को अलग-थलग किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रों की मदद का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद को धर्म से अलग रखने और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के एकजुट होने पर बल दिया। हमारे विदेशी आदान-प्रदानों से मुख्य सहयोगियों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिली है।

अध्यक्ष महोदया, विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय में जोश, ऊर्जा और विश्वास, चुनाव के बाद के राष्ट्रीय माहौल को परिलक्षित करता है। प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय तक उस स्तर तक पहुंच बनाने की कोशिश की और उस स्तर तक पहुंच बनाने की ओर ध्यान दिया है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। विदेशों में स्थित भारतीय समुदाय द्वारा पी आई ओ और ओ सी आई कार्डों पर हमारे निर्णयों को व्यापक रूप से सराहा गया है। आज भारतीय समुदाय न केवल अपने को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करता है, बल्कि उसने भारत में बदलाव की पहल में अपनी सहभागिता को भी सकारात्मक रूप में स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्व में भारत की भूमिका और स्थान को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि रखी है, जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते विश्व नेतृत्व को ग्रहण करने की अपनी स्वीकार्यता भी शामिल है। हमने वादों को कार्यवाही में, अवसरों को परिणामों में बदला है। हमने उन सम्बन्धों को पुनर्जीवित किया है, जो लंबे समय से उपेक्षित पड़े थे। हमने अपने सुरक्षा हितों को खुलकर व्यक्त किया है और जोरदार तरीके से उनकी रक्षा की है।

आज भारत को लेकर विश्व में एक नया विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के विदेश दौर से विकास के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी वातावरण बनाने में मदद मिली है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इससे हमें आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने, नये रोजगार के सृजन करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने के हमारे मिशन को हासिल करने में बहुत-बहुत मदद मिलेगी।

12.22 hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO.
622 DATED 26TH NOVEMBER, 2014
REGARDING “DECONGESTION OF DELHI”***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, with your permission, I would like to lay a statement correcting the reply (English and Hindi version) to Unstarred Question No. 622 given on 26th November, 2014 by Shri Jyotriaditya M. Scindia, MP regarding “Decongestion of Delhi”.

* Placed in Library, See No. LT 943/16/14

Corrected copy of the Lok Sabha Unstarred Question No. 622 answered on November 26, 2014

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 622
TO BE ANSWERED ON NOVEMBER 26, 2014
DECONGESTION OF DELHI

NO. 622 SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

- a) Whether the measures taken by the Government to improve mobility in the National Capital so far have been ineffective;
- b) If so, the reason therefor;
- c) Whether the Union Government has recently constituted a committee to prepare a report to decongest Delhi; and
- d) If so, the terms of references of the committee and the time by which the committee is likely to submit its report to the Government?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(SHRI BABUL SUPRIYO)

- a) :No, Madam
- b) :Question does not arise
- c) :Yes, Madam
- d) :(i)The Terms of Reference (TOR) for the committee was the Committee will take into account all the technical, financial and administrative aspects on " How to Decongest Delhi".

(ii)As per TOR the Committee will submit the report along with proposed action points within 30 days.

12.24 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Advisory of the Delhi Development Authority

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to move:

“That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act.”

The motion was adopted.

(ii) Council of Indian Institute of Science, Bangalore

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam Speaker, I beg to move the following:-

“That in pursuance of the clause 9 (1) (e) of the Scheme for the Administration and Management of the Properties and Funds of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with Regulations 3.1 and 3.1.1 of the Regulations of the Institute, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the

Council of the Indian Institute of Science, Bangalore, subject to the other provisions of the Scheme and the Regulations.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of the clause 9 (1) (e) of the Scheme for the Administration and Management of the Properties and Funds of the Indian Institute of Science, Bangalore, read with Regulations 3.1 and 3.1.1 of the Regulations of the Institute, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore, subject to the other provisions of the Scheme and the Regulations. ”

The motion was adopted.

(iii) National Board for Micro, Small and Medium Enterprises

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में, दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य को निर्वाचित करें।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, read with sub-rule (1) of Rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, for a period of two years, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

The motion was adopted.

12.32 hrs

**MOTION RE: SEVENTH REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ -

“कि यह सभा 2 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से इस आशोधन के अध्याधीन सहमत है कि क्रमांक 1 से 3 में मर्दों से संबंधित सिफारिशें जिनका निपटान सभा के द्वारा पहले ही किया जा चुका है, का लोप किया जाए।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd December, 2014 subject to the modification that the recommendations regarding items at Serial Nos. 1 to 3 already disposed of by the House, be omitted.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभागृह में पेश कर रहा हूँ, जोकि पिछले 6 वर्षों से लॉ एंड जूडिशियरी मंत्रालय के पास अनिर्णित है। **Changing the name of the High Court, Bombay to High Court, Mumbai,** यह मुद्दा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे का नाम बदल कर मुम्बई किया गया उसे केन्द्र शासन की अनुमति मिली। उसके बाद दिसम्बर, 2008 से आज तक इसके बारे में महाराष्ट्र शासन की तरफ से केन्द्र शासन को बार-बार खत लिखे गए। जनवरी, 2009 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी केन्द्रीय लॉ एंड जूडिशियरी मंत्री जी से मिले। केन्द्रीय मंत्री जी ने उस वक्त आदेश दिया था कि "New Delhi is requested to instruct the concerned official to take immediate step to change the name of High Court of Judicature at Bombay as High Court of Judicature at Mumbai." लेकिन दुर्भाग्य से वह आज तक नहीं हो सका। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़णवीश जी ने अगस्त, 2012 में आदरणीय पंथ प्रधान जी से मिले और उनको खत लिखा, उनसे निवेदन किया।

मैं शून्य काल में आपके माध्यम से आदरणीय पंथ प्रधान जी से विनंती करता हूँ कि 26 जनवरी से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदल कर मुम्बई हाई कोर्ट करने का निर्णय लें और वे खुद मुम्बई में आकर उसका नामकरण करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, श्री राहुल शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Thank you very much, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak in this august House and to raise before you an issue related to my constituency, Lakshadweep.

You know that the entire population of Lakshadweep is categorized as Scheduled Tribe through the People's Act, 1956. Under the light of this, the students of Lakshadweep and the children born to the parents of Lakshadweep are given free education. You also know that after we achieved Independence and entered in a democratic set up, Lakshadweep has witnessed enhancement of scholarship only once in 2006. Right now I wish to point out that just three days

before there was a huge strike before the Department of Education for clearing the existing scholarship bills which is pending not because of shortages of fund but just because of the administrative delay.

My submission before the Government through you, Madam, is that the proposal pending before the Ministry of Human Resources Development for enhancing the scholarship for Lakshadweep students may be expedited.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 एवं 85 बिहार राज्य में क्रमशः छपरा से मोहम्मदपुर तथा छपरा से सीवान होकर गोपालगंज तक जाता है। उक्त दोनों मार्गों का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी जर्जर अवस्था में है। इन मार्गों से गुजरने वाले पैदल एवं सवारी यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है। वाहनों के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिकों का समय बर्बाद होने के साथ-साथ आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इस संदर्भ में मैंने पूर्व में भी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 3.06.2014 को पत्र लिखा था किन्तु अभी तक सड़क की स्थिति पूर्ववत है।

महोदया, मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह तुरंत इस राष्ट्रीय राजमार्ग 101 और 85 को आम लोगों के चलने की स्थिति में लाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएच 101 के जो कौन्ट्रैक्टर और अभियन्ता हैं, मुझे लगता है कि वे वहां की सरकार को कहीं न कहीं सहयोग करके भारत सरकार की उपेक्षा करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल बात कीजिए, आरोप नहीं लगाइए।

... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : इसलिए एन.एच. 101 के निर्माण कार्य जो प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए जिससे पथ निर्माण कार्य में लगे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना किसी का नाम लिए केवल अपनी इन्क्वारी की बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा-अमरावती-यवतमाल प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुए पथ निर्माण के कार्य में पिछले पांच वर्षों में हुए अत्यधिक भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके बारे में

काफी शिकायत मिली है।... (व्यवधान) इस संदर्भ में विदर्भ को अवगत कराया है।... (व्यवधान) जब भी एस्टीमेट बनता है तो पांच साल तक जो ठेकेदार कार्य करता है, उसका ही काम करने का जिम्मा होता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने रिपेयरिंग की मांग की है तो करने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस : किन्तु रोड की रिपेयरिंग के नाम पर दोबारा हमारे संसदीय क्षेत्र वर्धा में टैंडर निकालकर नए ठेकेदार को कार्य दिया है जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।... (व्यवधान) उन पर इन्कावारी होनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं आई है।

... (व्यवधान)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं वहां के गरीब तबके के वर्गों की आवाज, गुहार लेकर आपके समक्ष आया हूं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you to raise your issue.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I know it. Yesterday or so, I allowed you to speak on the issue related to Church.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसे क्यों कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं कि आप चर्च वाला ईशू उठाना चाहते हैं। मैंने कल भी एलाऊ किया था। मंत्री जी ने कुछ बात भी बोली थी। अगर दोबारा बोलना चाहेंगे तो मैं एलाऊ करूंगी, लेकिन बाकी विषय होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल यह विषय हो चुका था। ऐसे नहीं होता कि जब चाहें तब खड़े हो जाएं। बाकी लोगों का अधिकार मत मारिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी जानते हैं बाकी लोगों ने भी नोटिस दिया है, कल भी आपको एलाऊ किया था वही सेम विषय

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this issue was raised yesterday. The Minister for Parliamentary Affairs had assured that the Government would respond today. The Minister was here ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is there.

जब वे बोलते हैं तब आप बाहर जाते हैं, इसके पहले भी

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I am telling you. ... (*Interruptions*) If you do not allow the Minister for Parliamentary Affairs to speak, I am going to speak what they have spoken. If this is the way they are going to talk, it would become impossible to run the House.

What I am saying is that we admit that yesterday the senior Minister for Parliamentary Affairs did say that when the Home Minister returns back, he would find out the details and come back to you. I have taken note of it. Hon. Home Minister has come back. Please have the patience to let the proceedings go on. That is what we are doing for you. ... (*Interruptions*) You relax. He has come back. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. आप भी नहीं

... (व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: We are doing your job. ... (*Interruptions*) That is what we are doing. ... (*Interruptions*) He has come back.

HON. SPEAKER: Let Shri Mahesh Girri complete his statement.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The problem is that you do not want to listen. ... (*Interruptions*) You do not want to have an answer. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : महेश गिरी जी, आप अपनी बात कम्पलीट करें। Let them complete. ऐसा नहीं करते। प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री महेश गिरी : मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर गरीब ... (व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, hon. Home Minister had gone to the other House. He has come back. He is going to reply. That has been taken note of. They just react without even ascertaining the facts. Please also give time to the Government to respond. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप आपस में बात नहीं करेंगे। मैं सबकी चिंता कर रही हूँ। मंत्री जी आ गए हैं, मगर वे खड़े हैं उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। साढ़े आठ बजे नोटिस देते हैं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरा कीजिए।

श्री महेश गिरी : मैं पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ गरीब वर्ग का तबका बहुत ज्यादा है, वहाँ की गुहार लेकर आया हूँ। यदि कोई गरीब अपने घर की समस्या के लिए, अपने प्लॉट की समस्या के लिए न्यायालय में सुनवाई चाहता है। जब उसे कोई समस्या हो जाती है, कभी उसे प्लॉट मिलने वाले हों, उसकी घर वहीं झुग्गी पर होने वाली है। पिछली सरकारों में बहुत वायदे हुए, लेकिन केवल सर्टिफिकेट ही बांटे गए। उन्हें जब न्याय मांगना होता है तो वह निचली अदालतों में जाते हैं। जिस जगह की वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक होती है और जैसे ही उस जगह की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक होती है उन्हें तुरंत यह कहा जाता है कि यह निचली अदालतों में नहीं, यह उच्च न्यायालयों में केस लड़ा जाएगा। जब उच्च न्यायालय में लड़ने की बात आती है तो उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि वे इतनी बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं। निचली अदालतों के वकील भी उनका केस नहीं लड़ पाते, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। एक, हाई कोर्ट में इसकी वजह से बहुत सारे केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। दूसरा, गरीब तबका इसका बोझ नहीं ढो पाता।

महोदया, इसके लिए कई बार वहाँ के वकीलों ने हड़ताल भी की है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसे वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, वे उच्च न्यायालयों में केस नहीं लड़ते, निचली अदालतों में लड़ते हैं। कुछ समय पहले इसके लिए एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि 20 लाख रुपये की सीमा को 2 करोड़ रुपये तक की जाए। मैं कानून मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बाकी

सभी राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपये से असीमित तक है, तो केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों, जिससे बहुत बड़ा समाज प्रभावित हो रहा है। खासकर मेरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मैं उनकी गुहार लगाकर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कानून मंत्री इसके लिए जल्द से जल्द कोई निर्णय लें।

12.40 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

(i) Re: Issue of alleged destruction of a church in East Delhi due to fire prompting allegation of foul play by Church Authorities

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कल के विषय में कुछ कहेंगे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जिस समय मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि दिल्ली में एक चर्च के जलने की घटना हुई है। मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस संबंध में बात की और मैंने उनसे कहा कि इस मामले की तुरंत जांच कराई जानी चाहिए। सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के चेयरमैनशिप में एक एसआईटी बना दी गई है ताकि पूरे मामले की ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसे टाइम बाऊंड भी कर दिया है कि ज्यादा लम्बा समय नहीं लगना चाहिए, बल्कि दो महीने के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, there has been ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing else will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाला कोई भी समुदाय हो, यदि किसी भी व्यक्ति के धर्म और आस्था पर चोट पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा, तो हमारी सरकार उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। एसआईटी पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच करेगी और दो महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी। यदि आपका निर्देश होगा कि वह सदन के पटल पर भी रखी जानी चाहिए तो उसे मैं सदन के पटल पर भी रखने को तैयार हूँ। ... (व्यवधान)

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Now, Shri Innocent.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होती।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं क्षमा चाहती हूँ। किसी का न नोटिस है और न कुछ और है।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I have already given notice. ...
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम भी इन्नोसेन्ट है।

... (व्यवधान)

श्री इन्नोसेन्ट (चालाकुडी) : स्पीकर मैडम, मैं हिन्दी में बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने बात की तो भी आप समझ नहीं पायीं और न ही मैं समझा पाया, इसलिए मैं मलयालम में बात करूंगा।
... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग सुनिये। वे जिस बात को उठा रहे हैं, उससे खुद भी जूझ रहे हैं, इसलिए कृपया आप उनकी भी चिंता कीजिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Innocent Have you give notice to speak in Malayalam? Mr. Innocent, please listen to me. You have not given notice that you desire to speak in Malayalam. Hence, no translation is taking place. Therefore, please give it in writing.

SEVERAL HON. MEMBERS : Madam, it is there.

HON. SPEAKER: Is it available?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Madam.

HON. SPEAKER: If it is available, then it is okay. Please make your submission continue with your submission.

* Not recorded.

*SHRI INNOCENT : I express my gratitude to Hon'ble Madam Speaker, for allowing me to speak. This is my maiden speech, on the floor of this august House, and I want to raise a very important subject.

Madam, myself and my wife were cancer patients till last year.

Cancer had affected five parts of my body.

While I was under going treatment in the hospital, my wife Alice underwent mammogram test.

The test was done, three days prior to my discharge from the hospital.

While I got discharged and was returning home, the doctor telephoned me and told me that the result of mammogram test has come – and my wife too was suffering from cancer.

But he assured me, that there was nothing to worry; because it was detected at the earliest stage.

Therefore unlike me; she did not have to undergo Chemotherapy or even medicines.

I narrated this story because I am told that the Central Government is planning to provide free medicines to cancer patients.

This is indeed a good idea. But Madam after developing cancer when the patients go to the doctor for treatment; it is often found that cancer growth has reached the 2nd stage; 3rd stage, or even the last stage.

Therefore, for the early detection of this disease; the Central and State Government should jointly organise mobile cancer detection units.

It should travel to all panchayats, municipalities, and corporations.

All across the country, in all the states, we should be able to detect cancer at the earliest; and there by ensure full recovery of the patients.

* English translation of the speech originally delivered in Malayalam

We can thereby reduce the mortality rate due to cancer.

I certainly hope and request the Central Government to take immediate steps; to wards this end.

HON. SPEAKER: Both he and his wife are suffering from cancer. Whatever issue he has raised, he has raised it very sincerely.

Hon. Members, Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju and Shri Ashwini Kumar Choubey are permitted to associate themselves with what hon. Member Shri Innocent has said.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): I wish to bring to the notice of the Government the alarming situation arising out of depleting groundwater table in the country. We have been seeing in rural areas that even after digging 1500 feet, we are not getting drinking water. The survey conducted by the Government of India and the information given to us clearly show that in more than 60 per cent of all the bore-wells that were surveyed, there is depletion of groundwater due to overuse and unsustainable exploitation of water. Of course, some States have enacted laws to prevent overexploitation and unsustainable exploitation of water.

Hence, remedial measures have to be taken by the Government of India because the non-perennial rivers in the country are drying up. Therefore, my suggestion and request to the Government of India is that taking some remedial measures with regard to recharging of groundwater is of paramount consideration. We also require watershed management, percolation tanks and even diversion of flood waters. Otherwise, in future, we will have to face severe consequences in regard to drinking water. Therefore, I would urge upon the Government of India to take immediate measures with regard to this.

HON. SPEAKER: Hon. Member Shri D.K. Suresh is permitted to associate himself with what the hon. Member has said.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam, I would like to take this opportunity to once again request the Central Government to

include the town of Srikakulam, which is in my constituency, under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. The State Government has also requested the Central Government to include this town under this Scheme. Srikakulam is a city of great historical and tourist importance. We have got temples that are thousands of years old. There are a lot of tourists who are coming in. This would really help develop the town of Srikakulam. So, I would urge the Central Government to consider this proposal.

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Madam Speaker, I wish to bring an important issue to the notice of the Government through this august House.

Nearly 350 farmers in the Telangana State have committed suicide in the six months since the State came into being on June 2 this year due to massive power and water crises. These crises led to these tragic deaths. While delayed and deficit rains have played havoc in the State, crop failures due to poor rains, non-existent irrigation system and debt burden have pushed them to suicides. No fresh bank loans and poor power supply in this season have pushed farmers into despair. Some of the main reasons are lack of Minimum Support Price to the agricultural produce of farmers and their inability to repay their borrowings which they have taken at high rates of interest from private moneylenders. They were hoping that one bumper crop will solve all their woes. But monsoon failure and the absence of any crop insurance scheme make suicide the only escape route.

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़े में अपनी बात कहिए। You are not supposed to read all these things; you only have to point it out.

SHRI P. SRINIVASA REDDY : I would urge upon the Government to declare this as a national disaster and 'agriculture emergency', apart from taking immediate confidence building measures to curb suicides in Telangana.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि जिला सवाई माधोपुर से जयपुर तक हजारों ग्रामीण लोगों को शिक्षा, रोजगार एवं सरकारी

कार्यों के लिए राजधानी जयपुर जाना पड़ता है। इस सैक्शन पर लगभग 100-150 पंचायतें हैं जो रेलवे स्टेशन के समीप हैं एवं इससे जुड़ी हुई हैं। इस सैक्शन पर चौथ माता का मन्दिर भी है, जो पूरे भारत वर्ष में एक मात्र मन्दिर है, इसकी मन्दिर की एक अलग ही प्रसिद्धि है। इसलिए यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदया, अभी कल-परसों माननीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि बजट की कमी है। टोंक को रेल से जोड़ने के लिए मैंने पिछली बार आग्रह किया था, उनसे अनुरोध किया था कि टोंक को रेल से जोड़ने के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। मैं माननीय रेल मंत्री से पुनः निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर एक पैसेंजर रेलगाड़ी चलाने की कृपा करें, जो सवाई माधोपुर से जयपुर सैक्शन पर कार्यालय के समयानुसार सुबह 9 बजे जयपुर पहुंचे और शाम को छः बजे जयपुर से सवाई माधोपुर पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर एक बार फिर से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह एक नवम्बर को हरियाणा के नारनौल में एक नौ साल की बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में है।

माननीय अध्यक्ष : आपने मनरेगा के संबंध में नोटिस दिया था। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में बोल सकती हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं उसी विषय पर बोल देती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि मनरेगा की स्कीम, जो कई मज़दूरों के पलायन को रोकने का काम करती थी। यू.पी.ए. सरकार ने मज़दूरों के पलायन को रोकने और गाँव के बेरोज़गार युवकों को रोज़गार देने के लिए यह योजना चलायी थी। मई महीने से उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। उसके कारण बिहार में पलायन के संख्या 50 हजार तक पहुंच गयी थी। सिर्फ कोसी रेंज से चाल लाख मज़दूर दोबारा पलायन के लिए मज़बूर हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक तो योजनाओं को रोक दिया गया है, इंटरलॉकिंग की योजना थी, पेड़ लगाने की योजना थी, शौचालय बनाने की योजना थी। एक तरफ सरकार शौचालय बनाने की बात कह रही है लेकिन मनरेगा की पेमेंट न होने के कारण पी.एस.जी. का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन शौचालय नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ, मैं सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि आप जो दूसरी स्कीमें लाएंगे, वह एक दूसरी बात है। लेकिन तब तक किस कारण से मई महीने से उन मज़दूरों की पेमेंट

रोकी गयी है, जो पाँच महीने काम कर चुके हैं। क्या जल्द से जल्द सरकार उनकी पेमेंट की राशि मुहैया कराएगी?

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वीणा देवी -उपस्थित नहीं।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, farmers are facing a lot of troubles in Telangana especially in Mahabubnagar district, Alampur Taluka and in various other States as there are not purchasers for cotton and other products. CCI and Food Corporation of India are not opening their purchasing centres in various places where they have opened earlier. Cotton, paddy and other products are not getting proper price. We request the Government to examine the price fixed by them which is not according to the product cost. We therefore, request that the matter may be discussed in the House as a Short Duration Discussion.

माननीय अध्यक्ष : आपको इसका नोटिस देना पड़ेगा।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : It also shows that the banks are discriminating against the farmers. The banks are writing-off and rescheduling the Non-Performing Assets (NPA) by the corporate sector. However, similar support is not available to the farmers.

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAYAN (ERODE): Thank you madam for giving an opportunity to speak in this august House. Our agro-economy and railways are interlinked and help the Indian population in a big way. The Railways help the farmers to transport agricultural produce. It also provides direct selling opportunity to sell fruits and fruit juice. In many railway stations, fresh fruit juice is made available to passengers.

Sugarcane and coconut growers are not finding it profitable in the absence of marketing facility. Hence I urge upon the Railway Minister to give proper permission to operate stall to sell tender coconut and sugarcane juice in platforms. The Government may also consider of giving proper permission to the farmers to sell tender coconuts and sugarcane juices in all railway stations of our country.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): This request is to set up a science city in Guntur, Andhra Pradesh. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the residuary State of Andhra Pradesh is left with no scientific establishment and knowledge centre as the existing one has gone to Telangana.

Amravati is an ancient centre of learning situated in my constituency of Guntur. Guntur has gained immense prominence since centuries in the field of education and is distinguished as the knowledge centre of Andhra Pradesh with the presence of numerous engineering, medical, pharma and other colleges.

13.00 hrs

The new Capital of Andhra Pradesh is being developed in Guntur. Further, Guntur which has established its name as the Knowledge City is centrally located for its people in the State, in other parts of the State. A.P. Government is also willing to give land for this purpose.

In view of the above, I would request the Government to take up this project at the earliest to extend scientific benefits to the people of Andhra Pradesh that is now left with little scientific activities and scientific guidance to the young children and students.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, टीकमगढ़ छतरपुर सहित बुंदेलखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी टीकमगढ़ में मिनोरा फार्म और कृषि विज्ञान केंद्र के पास लगभग 700 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया गया है। छतरपुर में नौगांव के पास भी सैकड़ों एकड़ जमीन खाली है, जिसको राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बुंदेलखण्ड पैकेज के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में छोटे-छोटे काम जैसे छोटी-छोटी नहरों एवं बांधों के काम कराए गए, लेकिन बुंदेलखण्ड के सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए अगर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी अवसर उपलब्ध होंगे।

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर): मैडम, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ग्यारह गांवों के 1000 किसानों का यह मामला है। 15 वर्षों से सरकार ने जमीन एक्वायर कर रखी है। पहली नवम्बर से वे लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 नवंबर को वहां पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गयी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ दिखाना नहीं है, जो बोलना है, बोलिए।

श्री राम चरित्र निषाद : मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि उन ग्यारह गांवों के लोगों को मुआवजा मिले और जिन लोगों को संगीन अपराधों के आरोप में जेल में रखा गया है, उनको धाराएं कम करके बाहर निकाला जाए। यही आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, there is an urgent need for direct flight connectivity between New Delhi and Thiruvananthapuram, the State Capital of Kerala not only to prevent the loss of valuable time for my constituents but also to strengthen Kerala's tourism industry.

I might add that a dozen MPs including one of the Government's Ministers use that airport. So, I hope the Civil Aviation Minister takes it seriously. It is a big irony that you can fly directly from Thiruvananthapuram to dozens of various Gulf countries like, Bahrain, Kuwait, Muscat, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Jeddah and even Singapore. But you cannot fly directly to Delhi.

Now our domestic services have been deregulated. The Central Government could incentivise airline operators to provide for direct flights. Alternatively, the Government could expand category-I routes mentioned in the

Route Dispersal Guidelines and require direct flights between the national Capital and State Capitals. That will also grant Thiruvananthapuram a connectively. I would, therefore, urge the Government to do it. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can associate. You give it in writing.

Shri N.K. Premachandran, Shri P. Karunakaran, Shri M.B. Rajesh, Shri Jose K. Mani, Adv. Joice George and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

HON. SPEAKER: What is it? It is a State matter. How can we take it up? ठीक है, आप संक्षेप में बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : मैडम, डब्ल्यू.एच.ओ. की स्टडीज के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 25,000 से 30,000 डेथ्स हो रही हैं। इसकी वजह से सारी दुनिया में होने वाली डेथ्स का 36 प्रतिशत हमारे देश में होती है और खास तौर से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। केंद्र सरकार का जो नेशनल रैबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें स्टरलाइजेशन, वैक्सिनेशन और पीड़ितों के इलाज के लिए कुल 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस रकम को बढ़ाया जाए।

श्री रवनीत सिंह : मैडम, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उसका बजट कई गुना बढ़ाया जाए, जिससे इस बहुत घातक समस्या का हल हो सके।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर) : अध्यक्ष महोदया, कोल्हापुर एक ऐतिहासिक शहर है तथा प्राचीन समय से यहां महालक्ष्मी का स्थान है। यह एक धार्मिक स्थल है और अम्बाबाई का मंदिर भी यहां पर है। देश के साढ़े तीन शक्तिपीठों में से यह एक मंदिर है जिसका निर्माण 634 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ कोल्हापुर जिले में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर, खिदरापुर मंदिर, नरसभावाड़ी दत्त मंदिर, स्वयंभू गणेश मंदिर, त्रिभूलि मंदिर, रेणुका मंदिर, जैन मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर हैं। ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर पन्नालगढ़, विशालगढ़, भूदरगढ़ जैसे 13 किले कोल्हापुर जिले में हैं। न्यू-पैलेस, शालिनी पैलेस, रंका ि तालाब, कलम्बा तालाब भी वहां पर हैं। कोल्हापुर और चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे चप्पलें, कोल्हापुरी गुड़ तथा खुफरी में सिल्वर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जहां से सिल्वर एक्सपोर्ट होता है। देश-विदेश से हर साल यहां पर 40 से 50 लाख लोग महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आते हैं। शहर में विजिटर्स के हिसाब से सुविधाओं की बहुत कमी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और शहर के रास्ते और अप्रोच रोड खराब हैं।

वहां पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पब्लिक शौचालय नहीं हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है। रेस्ट हाउस, बस स्टेशनों को दुरुस्त करने की जरूरत है। रेलवे स्टेशन 125 साल पुराना हो चुका है। एयरपोर्ट पिछले पांच सालों से बंद है। कोल्हापुर एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल या पर्यटन स्थल हो सकता है। हैरीटेज डिवेलपमेंट के लिए कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2300 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर केन्द्र के पास भेजा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि विशेष सहायता कोल्हापुर के लिए दी जाए और जल्द से जल्द इस ओर कदम बढ़ाए जाएं।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, today is the day which is celebrated by the United Nations as the day for disabled persons or persons with different abilities. ... (*Interruptions*) My friend has objection to the word 'celebration'. It is also an attitudinal question because a person's ability to perform is not dependent on the disability a person is suffering from क्योंकि अपंगता किसी वजह से हो सकती है लेकिन विकलांगता समाज की देन है। जो विकलांगता समाज की देन है उसे सुधारने की आवश्यकता है और उस सुधार में तीन-चार विशेषरूप से जो चीजें हैं, वह मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांगना चाहती हूँ। पहला विषय है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर बहुत जोर दिया है। Till now the schemes have been oriented to be welfare schemes; we want to make them empowerment schemes. And empowerment is possible only through education and development of ability, self-sustaining ability, and ability to earn money. That will happen through skill training centres. Till now 72 per cent of Districts in India have got skill training centres, ITIs, but not one exclusively dedicated to disabled people. Though there is a certain percentage reserved for disabled, a more friendly atmosphere needs to be observed.

The second aspect is regarding the sports facility. Para sports is another issue which is very prevalent in the country. All over the world our para sports athletes have won several medals. From my Constituency there are people who have got Dronacharya awards and several other Asiad awards. There should be a para sports facility in New Delhi because Delhi happens to be the hub of various universities.

The third point is that positive examples should be set and sensitization of children from a very young age should be done. Stories like Ashtavakra and others be included in the syllabus.

With these words, I wish the observation would be complete as UN charter demands as we are signatories and we are bound by the law.

HON. SPEAKER: Very good suggestions. Yes, you can give them a good subject.

Shri M.B. Rajesh, Adv. Joice George, Shri Jose K. Mani, Shri Innocent, Shri Arjun Ram Meghwal, Shrimati Jyoti Dhurve, Shrimati Jayshreeben Patel and Shrimati Mala Rajyalakshmi Shah are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakshi Lekhi.

13.09 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERSContd.

(ii)Re: Alleged Misbehaviour with a woman Member of Parliament by Local District Administration during foundation stone laying ceremony for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Munger, Bihar.

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): अध्यक्ष महोदया, हम पहली बार इस सदन में आये हैं, इसलिए हमें सदन में बोलने में भी कठिनाई आ रही है। हम मुंगेर क्षेत्र से आते हैं। हमारे जिले लखीसराय के कार्यपालक-अभियंता ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास करने के लिए हमें फोन किया था। हम जब पहली बार 21 तारीख के कार्यक्रम में गए थे तो पूरी जनता हमारे साथ थी। हमने सारा कार्यक्रम खुशी-खुशी मनाया। लेकिन जब दूसरे दिन 22 तारीख को हमने वहां के लिए प्रस्थान किया उसके पहले ही बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री, जिनको हमने लोक सभा चुनाव में हराया है, उन्होंने साजिश करके पूरी रात शिलान्यास के शिलापट्ट की तोड़फोड़ करवाई और सभी अधिकारियों को धमकी दी कि तुम को बर्खास्त कर देंगे या मार देंगे।

महोदया, हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्य में आतंक फैला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के खौफ से उनको नींद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने यह तोड़फोड़ की है। उनको और जितने अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, उन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। आप मेरी मां के समान हैं और आप हमारे साथ न्याय करेंगी। बिहार में पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। बिहार सरकार के उस मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जितने भी अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं,

उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को यहां से कोई भी फण्ड नहीं जाना चाहिए। यह सारा फण्ड हमारे यहां के डीएम द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि वही काम करवाएंगे। हमें दो दिन में न्याय चाहिए और उन लोगों को, जिन्होंने यह तोड़फोड़ करवायी है, उन पथ निर्माण मंत्री जी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने इलेक्शन के समय भी हम पर हमला किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गयी है। उस समय हम झांसी की रानी की तरह से अकेले ही बूथ पर उसका मुकाबला कर आ गए थे। बिहार सरकार को हमने धूल चटा दी है।...(व्यवधान) हम उसको वर्ष 2015 में फिर से धूल चटा कर रहेंगे। आप हमारी मां की तरह हैं, हमें दो दिन में न्याय मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, मैं श्रीमती वीणा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदया, माननीय सदस्या ने हम से आ कर मुलाकात की थी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या सभी न्याय देने के लिए खड़े हो गए हैं? हम हैं न, और इस बारे में बात कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, श्रीमती वीणा देवी मुंगेर से सांसद हैं। इन्होंने आ कर के अखबार की पूरी कटिंग मुझे दिखायी थी। इनको एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने कहा था कि आप आ कर के शिलान्यास कीजिए और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा कर सड़कों का शिलान्यास किया था। अगले दिन जिस शिला पट्ट को लगाया गया था, उसको पूरा का पूरा उन्होंने ध्वस्त कर दिया गया। एक तो यह महिला सांसद हैं, इसके अलावा देश में किसी भी सांसद के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप शिलापट्ट लगाएं और उसको बाद में कुछ लोग तोड़ दें। This is a very serious matter. I request the Hon. Speaker to give a direction. This is a matter related to a Member of Parliament. If such things happen with Members of Parliament, it should be taken up very seriously.

माननीय अध्यक्ष : इस की कोई जरूरत नहीं है रूडी जी। हम सारी बात समझ रहे हैं। वीणा देवी जी, आपने जो बात उठायी है, अगर ऐसा हुआ है तो हम उसको नोटिस में लेंगे। आप चाहें तो लिखित में भी मुझे दें। मैं उसको गृह मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय को भेजूंगी। इसकी रिपोर्ट हम राज्य सरकार से भी मंगवाएंगे और कुछ न कुछ हम मंत्रालय के स्तर पर भी करेंगे। आप मुझे लिखित में भी देना चाहें तो दे सकती हैं। आपने जो विषय उठायी है, उसका भी मैं संज्ञान ले लूंगी।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड - उपस्थित नहीं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदया, दिल्ली एनसीआर में 360 गांव हैं। इन 360 गांवों में अंग्रेजों के समय का काला कानून चल रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद ... *

माननीय अध्यक्ष : आप यहां-वहां की बात क्यों बोलते हैं, अपनी बात बोलिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, यह बात रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य के ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। आप थोड़ा ठीक तरह से बोलना सीखिए।

श्री रमेश बिधूड़ी : दिल्ली लैण्ड रिकार्ड एक्ट, 1947 की धारा 81 और धारा 33 के तहत गांव की ज़मीन...(व्यवधान) गांव की एग्रीकल्चर ज़मीन में जब वे कुछ बनाते हैं तो सेक्शन 81 के तहत उसको ग्राम सभा के तहत कर दिया जाता है। अगर वह सुविधा शुल्क अधिकारियों द्वारा ले लिया जाए तो उसको रिलीज कर दिया जाए। इसी प्रकार से सेक्शन 33 है, उसके अंदर एक व्यक्ति के पास अगर 8 एकड़ जमीन है और उसमें से अगर कोई छोटा टुकड़ा बेचना चाहता है तो या तो वह पूरी जमीन को बेचेगा वर्ना, बाकी जमीन वे ग्राम सभा को दे देते हैं। जिससे गरीब, किसान आदमी को बेटी की शादी करनी है या मकान बनाना है तो वह अपनी जमीन बेच नहीं पाता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि सेक्शन 81(33) हर पार्टी के मैनीफेस्टो में हमेशा आता है, इसलिए इसे दिल्ली से वेव-ऑफ किया जाए, जिससे दिल्ली के किसानों का शोषण न हो।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : हमारे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधान सभा के अन्तर्गत असनहरा गांव में विगत तीन दिनों से वहां के ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे थे। कल हमारे विशेष अनुरोध पर वे किसी तरह से जल से निकलकर बाहर आंदोलनरत हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैं केन्द्रीय मंत्री महोदय को पत्र भी लिख चुका हूँ, केन्द्रीय मंत्री महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों की जायज मांग को पूरा करने की कृपा करें।

SHRI R. DHROVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Thank you for giving me an opportunity to raise an important issue regarding the wild boar menace across the country as well as in my constituency.

* Not recorded.

My constituency, Chamarajanagar, is having two tiger projects – Bandipur and BRT, and two wild life divisions. The incidence of wild boar attacks is very frequent; the wild boars enter the farmers' fields and destroy the standing crops severely. But the Forest Department is not giving any compensation for this. When the elephants enter the fields and destroy, then the Forest Department is giving compensation, but in the case of wild boar attacks, which are very severe, the farmers are not getting compensation.

My request to you, Madam, is to instruct the Government, especially the Ministry of Environment and Forests to extend compensation to farmers when the wild boars attack.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Shri M.B. Rajesh and Adv. Joice George are allowed to associate with the matter raised by Shri Dhruvanarayana.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के एक मंत्री ने अंडमान सैलुलर जेल संग्रहालय में स्थापित एक प्लेट, जिस पर स्वतंत्रता सैनानी वीर सावरकर जी का नाम और उनकी एक प्रसिद्ध कोटेशन, जो राष्ट्रभक्ति पर थी, उसे वहां से हटाकर उनका अपमान किया। वीर सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वीर सावरकर जी का नाम एवं उनकी एक मशहूर कोटेशन एक प्लेट पर अंकित करके अंडमान जेल स्मारक में लगी हुई थी। हम सभी जानते हैं कि वीर सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार ने काले पानी की सजा दी थी और उन्होंने अंडमान निकोबार सैलुलर जेल में 13 साल की सजा काटी थी। जहां उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध कभी सिर नहीं झुकाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान महान कविताओं की रचना वहां पर की थी। यू.पी.ए सरकार के मंत्री (*Interruptions*) ... *
ने...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मांग रखिए।

श्री राहुल शेवाले : उन्होंने संग्रहालय से उस प्लेट को हटाने का हुक्म दिया जिस पर वीर सावरकर का नाम और कोटेशन अंकित था। स्वतंत्रता सैनानी भारत के महान सुपुत्र रहे थे। वे किसी पार्टी या समुदाय से संबंधित नहीं थे। यू.पी.ए सरकार का यह कार्य निंदनीय है, जिसके द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान

* Not recorded.

हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ समय पहले वीर सावरकर जी की कविताओं का एक म्यूजिकल एलबम जारी करके स्वतंत्रता सैनानी का सम्मान किया था।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि सम्मान सहित वह प्लेट, जिस पर वीर सावरकर जी का नाम और कोटेशन अंकित है, उसे उसी स्थान पर एक समारोह करके लगाना चाहिए जिससे स्वतंत्रता सैनानियों का सम्मान होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री रमेश बिधूड़ी, डॉ.किरिट पी.सोलंकी, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अश्विनी कुमार चौबे एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को एशोसिएट किया जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती तथा पूर्वी जिलों, जहां रोजगार के अवसर न के बराबर हैं तथा वहां बाढ़ व अन्य कारणों के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, यहां के नौजवानों तथा जरूरतमंद लोगों को अच्छी जिंदगी व अच्छी नौकरी का लालच देकर खाड़ी के देशों, ज्यादातर अरब देशों में, इन क्षेत्रों में सक्रिय दलालों द्वारा भारी रकम लेकर भेजा जा रहा है, जहां पर कई लोग जाकर फंस गये हैं। उनके साथ मार-पिट्टाई तथा जबरदस्ती गैर-कानूनी तरीके से काम लिया जा रहा है। उनके पासपोर्ट और आई.डी. सर्टिफिकेट वगैरह छीन लिये गये हैं और उन्हें भोजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने अपने परिजनों से सम्पर्क किया है। परंतु क्षेत्र में सक्रिय उक्त दलालों की शिकायत करने तथा पुलिस व सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क करने के बावजूद दलालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने के कारण वहां फंसे हुए लोगों के घर-परिवार के लोग हताश व परेशान हैं। जिसके कारण दलालों के हौसले बुलंद हैं तथा वे लोगों से भारी रकम लेकर खाड़ी देशों में लगातार व्यक्तियों को भेज रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के ग्राम कमलापुरी, थाना संपूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी के ब्रजानंद व शंकर दयाल, श्री उस्मान पुत्र हदीस, कमलापुरी से दो लाख रुपये लेकर सऊदी अरब भेज दिया था। जहां उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों व अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। मैंने विदेश मंत्रालय से सम्पर्क किया था, वहां से सकारात्मक कार्रवाई हो रही है तथा पीड़ित परिवार भी विदेश मंत्रालय द्वारा दी जा रही सूचना व पत्रों के माध्यम से सरकार के सम्पर्क में है तथा संतुष्ट है। परंतु जिला स्तर पर दलालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : आप कार्रवाई की मांग कीजिए, लम्बा-चौड़ा क्यों पढ़ रहे हैं।

श्री अजय मिश्रा टेनी : मैं केवल एक सैन्टेंस और बोलूंगा। परंतु जिला स्तर पर दलालों के विरुद्ध पुलिस व सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने के कारण दलालों के हौसले बुलंद हैं तथा उक्त प्रकार

की घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीड़ित परिवारों की सुनवाई न होने के कारण जनता में आक्रोश है। अतः आपके माध्यम से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सबको समझना चाहिए कि शून्यकाल में लम्बा-चौड़ा लिखा हुआ पेपर लाकर नहीं पढ़ते हैं, अपनी बात थोड़े में उठाते हैं, वही महत्वपूर्ण है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूरे विश्व में और हमारे देश में तम्बाकू एक ऐसा मीठा जहर है, जिसके सेवन से प्रति वर्ष लगभग दस लाख लोग कैंसर जैसे खतरनाक रोग के शिकार होकर मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। जी.ए.टी.एस 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 27 करोड़ लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं और इनमें से करीब एक-तिहाई लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। इन दिनों चबाने वाला तम्बाकू काफी प्रचलन में है और ऐसे तम्बाकू का अपने देश में करीब 21 करोड़ लोग सेवन करते हैं। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पूरे विश्व में चबाने वाले तम्बाकू से 90 परसेन्ट लोग मुख कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं और जिसमें अधिकांश संख्या भारत में है। आज का युवा वर्ग विशेषकर चमकीले और सुगंधयुक्त पाउच का तम्बाकू खाने का काम करते हैं।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारत सरकार अविलम्ब इस पर प्रतिबंध लगाये। कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। मैंने स्वयं बिहार में गांव में जन चेतना स्वास्थ्य यात्रा चलाकर तीन साल तक इस अभियान को चलाया था, जिसमें बहुत सफलता मिली थी। बिहार में इस पर प्रतिबंध लगा है, अन्य कई राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध है। बिहार के अलावा मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब आदि राज्यों में इस पर प्रतिबंध है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगे और प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि स्कूलों और कालेजों के सामने कोई भी तम्बाकू आदि के प्रकार की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। आज धड़ल्ले के साथ इसकी बिक्री हो रही है। अतः सरकार को इस पर शीघ्र प्रतिबंध लगाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन मेघवाल, डा.किरीट सोलंकी, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह और श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ कि हमारे यहां सीमा सुरक्षा ब्यूरो हुआ करता था, जिसका काम यह था कि वह बॉर्डर से हटकर सीमा की सुरक्षा

किया करता था, उसमें सिविलियन हुआ करते थे, जो बिना यूनिफॉर्म के सेवा करते थे और वे विभिन्न कैटेगरी के लोग थे। उनमें एनिमल हजबैंडरी का डाक्टर भी हुआ करता था, वह पोल्ट्री का काम भी देखता था और किसान भी होता था। उनमें हर तरह के लोग हुआ करते थे और इन्हें बाकायदा इंटेसिवली ट्रेड वालंटियर्स आईटीवी ट्रेनिंग दी जाती थी और वूमैन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल वाट्स में महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। परंतु 2001 में जो सीमा सुरक्षा बल बन गया, उसके बाद इसमें जो ट्रेड लोग थे, इन्हें उस नौकरी से वंचित कर दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में हैं, जो ट्रेन्ड लोग हैं और इन्हें बार-बार राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से निर्णय लेकर कहा जा रहा है कि आप इन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में और जो सैंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें नौकरियां दी जाएं। किंतु दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, बिहार, यूपी, बंगाल, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि पूरे देश में सब जगहों में हैं। इन लोगों की उपयोगिता है, ये नौजवान हैं, पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं और आज ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है, हम स्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी स्किल्ड हैं। इनको एकोमोडेट करने की जरूरत है। बार-बार केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि गृह मंत्री जी अपने स्तर पर सभी राज्यों की एक बैठक बुलाएं और बैठक बुला कर इसका निबटारा करें।

श्री फगन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। टाइगर रिज़र्व फोर्स पूरे देश भर में संचालित है। यह काफी प्रचलित है। लोग लगातार इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो टाइगर रिज़र्व फोर्स है, उसको जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की योजना है। कान्हा और पेंच, ये पहले से ही स्थापित हैं। इसके पूर्व में वहां पर बफर जोन के नाम से एक पैच बनाया गया था। उसमें बहुत सारे गांव, विशेषकर जो आदिवासी गांव हैं, वे प्रभावित हुए हैं। उसका कारण है कि वहां पर जितने भी जंगली जानवर रहते हैं, खास तौर से जो शेर हैं, अगर एक शेर मरता है और इसके कारण वहां के आदिवासियों को बेघर किया जाए तो यह ठीक नहीं है। यह कहा गया है कि उस कॉरिडोर के बनने से, वहां रोड़ नहीं बन सकती और रेलवे की कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। हम आज लगातार इस यूनीपैच के लिए, कान्हा के लिए इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस टाइगर फोर्स के कारण वहां पर हमको परमीशन नहीं मिली है। अभी-अभी इस सरकार के बनने के बाद परमीशन मिली है। एक नया कानून फिर आने वाला है। इस कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तीन किलोमीटर की इस रेंज में वहां पर घने जंगलों का विस्तार किया जाएगा।

मेरा इतना ही कहना है कि यह बड़ा गंभीर सवाल है। मैं यह चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकार बड़ी गंभीरता से विचार करे। लोगों को उजाड़ने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने शेर मरने वाले हैं, उसकी एक अलग व्यवस्था है, परंतु मैं इतना चाहता हूँ कि कनैक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए। वहां पर एक नई रेल लाइन का विस्तार हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो चुकी है। श्री विनोद चावड़ा जी, आप बोलिए। आप सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : महोदया, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में पहले पासपोर्ट ऑफिस का केंद्र कार्यरत था, लेकिन दो-ढाई साल से यह केंद्र बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य डिस्ट्रिक्ट राजकोट या अहमदाबाद जाना पड़ता है और लोगों को बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ती है। मेरा संसदीय क्षेत्र कच्छ देश के बड़े क्षेत्रों में से एक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा विस्तार है। कच्छ से अहमदाबाद और राजकोट जाने का अंतर 300 से 500 किलोमीटर का हो जाता है। मेरे क्षेत्र के सरहदी विस्तार से गांवों में और भी अंतर ज्यादा होता है और पूरे गुजरात में कच्छ जिले का पासपोर्ट बनाने का रिकार्ड भी दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है। मेरी विदेश मंत्रालय से मांग है कि पुनः मेरे संसदीय क्षेत्र कच्छ में पासपोर्ट ऑफिस केंद्र को कार्यरत करना चाहिए।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.29 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.31 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty-One Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Matters under Rule 377.

Shrimati Santosh Ahlawat – not present.

Shri Ramesh Bidhuri – not present.

**(i) Need to make Gorra and Ami rivers in Gorakhpur
pollution free**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, जल जीवन का आधार है। भौतिक विकास के अन्धानुकरण ने जीवन के प्रमुख आधार को प्रदूषित कर जीव और जगत के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। देश की माँ तुल्य प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी आदि बड़ी नदियाँ हों अथवा उनसे जुड़ी सहायक नदियाँ, उन सभी को अनियोजित एवं अवैज्ञानिक विकास की सोच ने या तो पूरी तरह अवरूद्ध कर दिया है अथवा प्रदूषित कर दिया है। गोरखपुर (उ०प्र०) में बहने वाली राप्ती नदी की सहायक नदियाँ आमी और गोर्गा नदी पिछले कई वर्षों से इस अभिशाप से अभिशाप्त हैं। आज से 30-35 वर्ष पूर्व इन दोनों नदियों का तटवर्ती क्षेत्र खेती किसानों के साथ-साथ पशुधन के लिए जाना जाता था। मछुआरों की आय का भी प्रमुख साधन ये नदियाँ थीं, लेकिन आमी नदी रूधौली तथा खलीलाबाद की औद्योगिक इकाइयों और नगरीय कचरे के कारण पूरी तरह प्रदूषित हो गई हैं। इसी प्रकार की त्रासदी का शिकार गोर्गा नदी भी हुई है। इस नदी के तटवर्ती गाँव में पशुधन, खेती किसानों, मछली पालन सभी जल प्रदूषण की भेंट चढ़ गए हैं। वर्तमान में ये नदियाँ भयंकर जल प्रदूषण के कारण बदबू फैला रही हैं। राप्ती नदी में मिलने पर कई किलोमीटर तक इन नदियों के कारण बड़ी संख्या में मछलियाँ मर रही हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश की नदी संस्कृति के संरक्षण के लिए इन्हें प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त रखा जाए और इनकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखा जाए।

(ii) Need to provide honorarium at uniform rate to Anganwadi workers and extend them social security benefits particularly in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा स्वस्थ एवं समर्थ भारत को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से "समेकित बाल विकास योजना" (आई.सी.डी.एस.) को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान समय में 14 लाख से अधिक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 28 लाख से अधिक महिला कार्यकर्त्रियाँ एवं सहायिकाएँ हैं। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को भिन्न-भिन्न मानदेय मिल रहा है, जिसके कारण उनमें काफी असन्तोष है। उत्तर प्रदेश में 3500 रूपया प्रतिमाह जबकि हरियाणा में 7500 रूपया प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इन लोगों पर पुष्टाहार के साथ-साथ जनगणना, पल्स पोलियो एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने का दायित्व है। इतने वर्षों के बावजूद इन्हें अभी तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की पदोन्नति भी समय से नहीं हो रही है, न ही उनको समय से वेतन भुगतान हो रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी घोषित कर इनको सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का प्रावधान किया जाए।

(iii)Need to take action on Report of National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, भारत में 64 हजार और महाराष्ट्र में लगभग 16 सौ भटके विमुक्त जाति श्रेणी का समाज शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास से वंचित रहने की बात हाल ही में प्रकाश में आई है। इस समाज के विकास के लिए वर्ष 2008 को " रेणके आयोग " ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अभी तक रेणके आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है जिस कारण इस पिछड़े श्रेणी के समाज को असुविधाजनक जीवन जीना पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह रेणके आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने हेतु अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

(iv) Need to include Bikaner City in Rajasthan in the list of 100 cities proposed to be developed as smart cities.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान के बीकानेर शहर को भी सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। बीकानेर अपने आप में ऐतिहासिक शहर है। इसे रेगिस्तान की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इस शहर की जनसंख्या 7 लाख के करीब है। देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए बीकानेर शहर आकर्षण का केंद्र है। इसे सोलर हब के रूप में भी विशिष्ट पहचान मिली हुई है। बीकानेर में नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी हो चुका है और यह शीघ्र ही वायु सेवा से जुड़ने वाला है।

ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का तपस्वी स्थल श्रीकोलायत और विश्व प्रसिद्ध चूहों वाली करणी माता का मंदिर भी बीकानेर जिले में स्थित है। प्राकृतिक तेल, गैस, कोयला एवं पोटैश जैसे खनिज पदार्थों की सम्भावित खोज होने से बीकानेर के विकास की संभावनाएं प्रबल हैं।

कृषि क्षेत्र में भी नए-नए नवाचार हो रहे हैं। जैतून की रिफाइनरी का उद्घाटन हाल ही में हुआ है जिससे कृषि क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। पशुपालन के क्षेत्र में भी बीकानेर अग्रणी स्थान रखता है तथा एशिया की ऊन मंडी के रूप में बीकानेर को ही यह गौरव प्राप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर शहर को भी 100 स्मार्ट शहरों की श्रेणी में सम्मिलित कर इसे विकास की राह में तेज गति से अग्रसर होने का अवसर प्रदान करें।

(v) Need to include 12 key cancer drugs recommended by Tata Memorial Centre in the list of essential medicines.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, टाटा मेमोरियल सेन्टर ने कैंसर की बारह दवाओं को राष्ट्रीय मौलिक दवाओं की सूची में शामिल किये जाने हेतु सरकार को लिखित में सुझाव दिया है। यह एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है। यदि इन दवाओं को राष्ट्रीय मौलिक दवाओं की सूची में शामिल किया जाता है तो कैंसर पीड़ित लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। दवाओं की कीमत भी इतनी कम हो सकेगी कि गरीब कैंसर पीड़ित लोगों और अन्य सभी कैंसर पीड़ितों की पहुंच इस दवा तक आसान बन सकेगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि टाटा मेमोरियल सेन्टर के सुझाव को मानते हुए इन बारह दवाओं को राष्ट्रीय मौलिक दवाओं की सूची में शामिल किया जाए ताकि कैंसर से पीड़ित लोग इसका लाभ उठा सकें।

(vi) Need to provide compensation to families of victims died in gas tanker explosion at Charoti Naka on National Highway No. 8 in Palghar District of Maharashtra

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): In April, 2014, a Gas Tanker explosion took place at Charoti Naka in Palghar District of Maharashtra on National Highway No.8. The offence is registered against the owner of Tanker as CR. No.34-2014 at Kasa Police Station. 10 persons had died on the spot. All the deceased persons were poor Adviasies except the driver and one other person. No compensation has so far been given to any person either by the Central Government or the State Government.

Sir, I have already taken up this matter with the hon. Minister of Road Transport and Highways and wrote a letter to him on 14th July, 2014 but nothing has so far been done in the matter. I am, therefore, raising this issue through this august House to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways for awarding the compensation to the next of kin of deceased persons at the earliest.

**(vii) Need to establish a Cancer Institute in Rampur, Uttar Pradesh
by the Central Government**

डॉ. नेपाल सिंह (रामपुर) : देश में कैंसर से ग्रसित मरीजों की संख्या में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन इस जानलेवा बीमारी के उपचार के लिए अपेक्षाकृत अस्पतालों/संस्थानों की भारी कमी है। इस कारण गरीबी की पृष्ठभूमि वाले मरीज अस्पतालों के अभावों और इसके उपचार में भारी रकम के चलते अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कैंसर से ग्रसित कोई रोगी न हो। इस पूरे क्षेत्र और आस-पास के इलाके में कोई भी कैंसर का अस्पताल नहीं है। ऐसी दशा में हजारों कैंसर के गंभीर मरीजों को नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का रूख करना पड़ता है जहां पहले से ही ऐसे मरीजों की संख्या अधिक होने से इन्हें संस्थान में सांसदों के अनुरोध के बावजूद भी दाखिला नहीं मिल पाता है। कमोवेश यही हालात दिल्ली के अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के भी हैं। बार-बार दिल्ली आने-जाने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है तथा उन्हें अपनी अकाल मृत्यु का डर सताने लगता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस भयावह हो रही स्थिति से निपटने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाकर रामपुर, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय कैंसर संस्थान खोले जाने पर विचार करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rahul Kaswan – not present.
Shrimati Krishna Raj.

**(viii) Need to take remedial measures to check annual floods
occurring in various parts of the country**

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): देश के कई हिस्से हर वर्ष भयंकर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ की विभीषिका से जान-माल के नुकसान के साथ-साथ फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचता है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. Only the approved text will go on record. You cannot go beyond that. What is the approved text, only that will go on record.

श्रीमती कृष्णा राज : मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में इस प्राकृतिक आपदा से बचाव के उपाय करे एवं शीघ्र इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

(ix) Need to ensure proper implementation of electrification of villages under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in West Bengal

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) was launched by the Government of India as a flagship programme to provide access to electricity to all rural households. As on March, 2013, a total of 12,594 villages with 9.92 lakh BPL rural households were electrified by West Bengal State Electricity Distribution Company Limited under RGGVY scheme against the target of 14,113 villages covering 15.39 lakh BPL rural households.

The C&AG State Audit Report for the year ended March, 2013 reveals:

1. DPRs were prepared without preparing the Rural Electrification Plan or conducting field surveys. Consequently, BPL households had been omitted from the DPRs, while villages not requiring or facing statutory/physical constraints in electrification had been included in the DPRs.
2. Tenders were floated without inserting clauses to ensure reasonability of prices of materials to be supplied leading to varying ex-works prices for the same materials supplied by the same contractor in different packages. Execution of works and creation of infrastructure was delayed on account of belated delivery of materials, inadequate deployment of manpower, lack of coordination, etc., leading to shortfall in the number of BPL rural households electrified. Besides, liquidated damages were not imposed on the contractors.
3. Although adequate funds were received, the progress of works was not commensurate with disbursements. Further, the receipt of funds had not been reconciled.

4. Monitoring was ineffective with belated third party inspections.

I would like to know from the hon. Minister of Power whether the Ministry has taken cognizance of these Audit observations and, if so, what action the Ministry has taken for proper implementation of Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana and the extent to which the remaining villages in West Bengal have been electrified as on date.

(x) Need to introduce New DEMU Train Service between Salem and Puducherry via Vriddachalem

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Sir, the train services in the State of Tamil Nadu are inadequate and the railway track between Salem and Vriddachalem is underutilized. In order to provide better rail connectivity to the general public, students, labourers, employed people, business people, agriculturists and patients traveling to Puducherry and Salem, I request the hon. Railway Minister to introduce New Diesel Multiple Unit (DEMU) train services between Salem and Puducherry via Vriddachalem, two each in the morning and evening.

At present, there is only one train between Chennai Egmore and Salem via Vriddachalem and that too in the night only. Passengers who want to travel during the day time find it very difficult. Therefore, I demand that one Express Train from Chennai Egmore to Coimbatore via Vriddachalem and Salem may be operated during the day time to cater to the traveling public especially those who finish their work in Chennai during day time and want to go back.

(xi) Need to provide adequate grant under subsidy component to Government of Tamil Nadu and also permit cooperative banks to operate accounts for transfer of LPG subsidy to consumers

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Sir, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has made a representation regarding cooking gas subsidy on 3rd June to the Prime Minister of India.

Transfer of LPG subsidy directly into the bank account of customers under Direct Benefit Transfer Scheme of the Central Government Programme has been rolled out in the country in 54 districts from 15th November 2014. From 1st January, 2015 in Tamil Nadu, this project is proposed to be introduced.

In addition, the Tamil Nadu State has good governance. The benefits like education allowance, maternity benefits and other social security benefits are directly paid to the beneficiaries through their bank accounts. At the same time, for the goods offered under the public distribution system including kerosene and fertilizers, the amount of grant provided under subsidies being paid to Tamil Nadu is not adequate.

I am glad that the Central Government has accepted the idea of Tamil Nadu State Government that Aadhar number is not necessary for receiving LPG subsidy. But the Central Government accepts subsidies. Public sector oil marketing companies are under the Central Government and cooking gas supply is subject to the Central Government's administrative power.

For Rural hamlet residents, it is difficult to access National Bank branches. It is easier for the people eligible for various subsidies to get grants through primary cooperative societies and post offices. Even in urban areas, urban cooperative banks can be used to provide subsidy.

The State Government is already facing the problem in the distribution of pension for elders since they have no accessibility of bank account in rural areas. Therefore, the elderly pensioners are being sent the pension amount by Money Order. Moreover, according to international price fluctuations in the market price

of cooking gas, consumers may be affected by the hike in price and hence need a shield from such price-fluctuations.

(xii) Need to provide adequate funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in West Bengal

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme (MGNREGS) is one of the major schemes that is being implemented by the Union Government through the State Governments. The main role being played by Panchayati Raj Institution, other implementing agencies like Public Sector Undertakings, Zila Parishad, Gram Panchayat, local authority etc. In such a scenario slashing of funds for implementation of MGNREGS would be detrimental to the welfare of the people of the State. This is not acceptable. The employment generation under MGNREGS is huge. Before slashing the funds under MGNREGS there is a need to assess as to how States would be able to cope with this loss. In a federal structure, there is a need for active interaction between Centre and State before arriving at any decision. Under such a situation, West Bengal Government would find it difficult to implement the scheme at the State level.

Hence, I would strongly urge the Central Government not to slash funds meant for implementation of MGNREGS at the State level particularly in West Bengal.

**(xiii) Need to take suitable steps for revival of the
Mumbai Port Trust**

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, in Mumbai, on the eastern coast, there is nearly 1700 acres of land. This land belongs to Mumbai Port Trust. During the British Regime and after Independence this port was known as the best port for commercial purpose. Thousands of vessels used to come to the port to offload the huge materials from grains to oil. Over a period of time as the desilting was not done and as the size of vessels & its capacity to carry the goods increased substantially, the Mumbai Port has almost become redundant and now the old godowns are lying vacant. The land has become vacant and remains unused and is being encroached upon rapidly. Hence to protect and develop this land immediate action by forming a committee with the representatives of Parliament and Vidhan Sabha as well as representative of Mumbai Municipal Corporation has to be taken for revival of Mumbai Port Trust.

**(xiv) Need to take remedial measures to check increasing
number of fatal road accidents in the country**

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। पंजाब में हर रोज 15 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। सड़कों पर मृत्यु दर में भारत देश बहुत ऊपर के स्थान पर है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिन-प्रतिदिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(xv) Need to provide free sanitary napkins to women to boost female health and hygiene in the country

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): महोदय, हमारे भारत देश की महिलाओं की आबादी तकरीबन 61 करोड़ है। स्वच्छता संबंधी शारीरिक सुरक्षा हर औरत का अधिकार है। ए.सी. नेल्सन के सर्वे के अनुसार 12 प्रतिशत महिलाएं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkins) का प्रयोग करती हैं। बाकी 88 प्रतिशत महिलाएं कपड़ा, राख या भूसा इस्तेमाल करती हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है। इस तरह के विकल्प का इस्तेमाल करने की वजह से 70 प्रतिशत महिलाओं में प्रजनन संबंधी संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से 72 हजार से भी ज्यादा महिलाओं की मौत हर साल भारत में होती है। इस तरह मासिक धर्म के दौरान मलिनता की वजह से स्कूली छात्राओं को 4 से 5 दिन स्कूल मिस करना पड़ता है। सर्वे के अनुसार 23 प्रतिशत से अधिक लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। इसकी वजह है मासिक धर्म के दौरान सही तरीके से मलिनता की रोकथाम करने वाली साफ-सुथरी नैपकिन का प्रयोग न करना। साफ-सुथरी नैपकिन का उपयोग न करने की सबसे बड़ी वजह है 70 प्रतिशत महिलाएं इसका खर्च नहीं उठा सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां हो जाती हैं और स्कूल छोड़ना पड़ता है। साफ-सुथरी और उचित नैपकिन का प्रयोग नहीं करने की वजह से नौकरी या रोजगार करने वाली महिलाएं 2 से 3 दिन काम नहीं कर सकती हैं।

97 प्रतिशत स्त्री रोग विशेषज्ञ यह मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान साफ-सुथरी नैपकिन का उपयोग करने से सर्वाइकल कैंसर और प्रजनन संबंधी संक्रमण (Reproductive Tract Infection) जैसी बीमारियों से महिलाएं बच सकती हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा सरकार अपने-अपने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त में साफ-सुथरी सैनिटरी नैपकिन देती हैं, उसी तरह अन्य राज्यों में भी इसका निःशुल्क वितरण हो। 'सबला योजना' के तहत 0.006 महिलाओं को इसका लाभ मिलता है जो पर्याप्त नहीं है।

(xvi) Need to observe 19th February, the birth day of Shivaji Maharaj as 'Rashtra Bhakti Prerna Diwas'

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : हिन्दवी स्वराज्य निर्माता विश्वसंघ और सभी भारतीयों के प्रेरणास्रोत, अखंड देशभक्ति का जीता-जागता उदाहरण और सामान्यजनों को ऊंचा स्थान देने वाले आदर्श राजा शिव छत्रपति याने श्री शिवाजी महाराज की जन्म तिथि 19 फरवरी को पूरे देश-विदेश में 'शिव जयंती' के रूप में बहुत धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है।

आज अपने देश के अलावा विश्व के अन्य कई देशों में छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति एवं आम जनता के प्रति उनके व्यवहार को आदर्श के रूप में देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा माता-बहनों का उचित सम्मान, दूसरों के प्रति आदर एवं सद्भावना और बुरा रास्ता अपनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने जैसा गुण सराहनीय ही नहीं बल्कि आदर्शव्रत है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री से अनुरोध है कि राष्ट्रभक्ति, जनता के प्रति समर्पण, आदर्श युद्ध नीति आदि गुणों को अगली आने वाली पीढ़ी की ओर पहुंचाने हेतु '19 फरवरी' को पूरे भारत भर में राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्र भक्ति प्रेरणा दिवस' घोषित कर उत्साहपूर्वक मनाया जाए।

15.00 hrs

HON. DEPUTY-SPEAKER: Generally, when we are calling out the names of hon. Members to raise their matters, the Members concerned must be present in the House. Then only, they can participate in the discussion or raise matters under Rule 377. After calling out their names, if they are not present, they lose their chance. It is very difficult to call out their names once again and allow them to speak.. It is not the practice to call out the names once again.

I would, therefore, request the hon. Members to strictly follow the practice and be present when their names are being called out. Otherwise, we will not call out their names again to raise their matters. This is the general information, I want to pass it on to you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): You are very right, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, as an exception, because of the requests received, I am giving chance to the hon. Members, who were not present when their names were called out, to raise their matters under rule 377. It should not be repeated next time.

**(xvii) Need to resume extraction of copper in Khetri
Copper Complex in Jhunjhunu, Rajasthan**

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): महोदया, मैं आपका ध्यान 1967 में झुंझुनू में स्थापित खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। इसमें कुछ वर्षों से उत्पादन बंद है, जो पुरानी उत्पादित एम.आई.सी. है, उसे निजी कंपनियों को बेचा या टोल स्मेल्टिंग करवाया जा रहा है। इससे सालाना 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। देश में कुल ताम्बे के भंडार का 48 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। इस बहुमूल्य धातु के उत्पादन को बढ़ाने के बजाए प्रबंधन इसको बंद करने की ओर अग्रसर है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में बंद पड़े स्मेल्टरों को खुलवाया जाए, ताकि राजस्थान एवं देश को हो रहे नुकसान से बचा जा सके।

(xviii) Need to improve the standards of teaching and facilities in Government-run educational institutions for higher education in the country and also establish more colleges keeping in view the large number of students seeking admissions in such colleges, particularly in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : वर्तमान में देश एवं राजधानी दिल्ली की उच्च-शिक्षा व्यवस्था में आयी गिरावट के परिणामस्वरूप अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए माध्यमिक बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के बढ़ते दबाव के कारण छात्रों में आत्महत्या की संख्या में वृद्धि चिंताजनक है।

देश में 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जबकि मंत्रालय के अनुसार 2011-12 के दौरान 2.17 करोड़ छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया तथा वर्ष 2012-13 में यह संख्या 2.60 करोड़ हो गई, अर्थात् 43 लाख छात्रों की बढ़ोत्तरी। लेकिन उसी अनुपात में विश्वविद्यालयों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। आज छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। वर्ष 2011-12 में 18-24 वर्ष की आयु के 17.9 प्रतिशत युवा छात्रों ने उच्च शिक्षा पाई, जबकि अमेरिका में यह 33 प्रतिशत है। आज सरकारी विश्वविद्यालयों से कहीं ज्यादा निजी कॉलेज खुल रहे हैं। लगता है कि उदारीकरण और बाजारवाद उच्च-शिक्षा पर भी हावी हो गया है। वर्ष 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 लाख सीटें थीं, जो 2012 में 25 लाख हो गईं। भारत की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि कुछ विश्वविद्यालयों में अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता तथा दूसरी ओर हजारों कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्र तैयार नहीं होते।

इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर मारा-मारी व प्रतिस्पर्धा किसी से छुपी नहीं है। पूर्व में लोगों के लिए दाखिला काफी आसान होता था लेकिन आज परिवार की चिंता एडमिशन से ज्यादा ब्रांड की है। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में 89 कॉलेजों में 1,32,435 छात्र नियमित रूप से पढ़ रहे हैं व 2,61,169 छात्र अनौपचारिक रूप से पढ़ रहे हैं। इनमें प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र पड़ोसी राज्यों से दाखिला लेने आते हैं, क्योंकि, यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। पिछले 20 वर्षों में दिल्ली की जितनी जनसंख्या बढ़ी। उसी अनुपात में दिल्ली में कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ी, यह एक चिन्ताजनक विषय है।

अमीर, उच्च एवं मध्य वर्ग के बच्चे नामी-गिरामी संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं या फिर मोटी फीस देकर निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लेते हैं अथवा विदेश चले जाते हैं लेकिन गरीब का बच्चा कहां शिक्षा ग्रहण करे, इसकी गारंटी कौन सुनिश्चित करेगा?

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों की दयनीय स्थिति में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तब तक भारत की उच्च शिक्षा में यही विरोधाभास बना रहेगा। इसके साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं के साथ दिल्ली के छात्रों को भी दाखिले में विकल्प मिल सके।

(xix) Need to expedite gauge conversion of Ratangarh-Sardarshahr and Sadulpur-Hanumangarh railway lines in Rajasthan and augment train services in the State connecting Churu Parliamentary Constituency

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं अथवा चालू नहीं की गयी हैं, जिससे इस क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रतनगढ़-सरदार शहर, सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेल लाइन आमामान परिवर्तन कार्य विगत पांच वर्षों से अधूरा पड़े होने के कारण चालू नहीं हो पाया है, न ही चुरु-सीकर-जयपुर रेल लाइन का आमामान परिवर्तन का कार्य आज तक चालू किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण गाड़ियां श्रीगंगानगर-जयपुर रेलमार्ग पर पांच वर्ष से भी अधिक समय से बंद है। इसके कारण क्षेत्र की जनता सड़क मार्ग से अथवा दिल्ली होकर जाने के लिए बाध्य है। इसके कारण समय व धन दोनों का अपव्यय हो रहा है। जनता त्रस्त है व निरन्तर कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग करती आ रही है।

रेल बजट में घोषित नई रेल परियोजनाएं, जिनका सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण हो चुका है, सरदारशहर-हनुमानगढ़, चुरु-तारानगर-नोहर, सीकर-सालासर-बीदासर-नोखा, सूरतगढ़-सरदारशहर-तारानगर-सादुलपुर, सरदारशहर-गोगामेड़ी-सिरसा आदि परियोजनाएं मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने वाली अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनके पूरा होने पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े चुरु लोक सभा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी तथा क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बजट में घोषित कामाख्या-जोधपुर गाड़ी को अविलम्ब चालू किया जाये व जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट गाड़ी को हरिद्वार तक बढ़ाकर इसे प्रतिदिन चलाया जाये। बान्द्रा-जम्मूतवी, बान्द्रा-हिसार, जैसलमेर-हावड़ा साप्ताहिक गाड़ियों को प्रतिदिन किया जाये।

15.02 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Item No.15—The School of Planning and Architecture Bill, 2014, for consideration and passing.

Hon. Members, before we take up the consideration of the School of Planning and Architecture Bill, 2014, we have to allot time for discussion. If the House agrees, we may allot two hours.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, yesterday also we had discussed the same issue. I have the Business Advisory Committee Report with me. Last Thursday we had met in the Business Advisory Committee meeting. We had already agreed to take up four items, one is Labour Law; second is Merchant Shipping (Amendment) Bill; third is Merchant Shipping (Amendment) Second Bill and fourth is discussion on the Supplementary Demands for Grants. This Bill has not been listed in the Business Advisory Committee meeting. If there is any urgency, the Government has the freedom and the hon. Speaker has also the freedom to include any business. Has this Bill got any urgency? Every day they are pushing new Bills. The Members are very much interested to participate in every Bill. Without prior notice, how can they participate in the discussion and passing of this Bill? This is the type of attitude. Yesterday, we had discussed the same thing. Today also the Government is pushing the Bill without any prior notice. This is going on. Sir, I need a ruling from you.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): There is no need for having a ruling on such matters. It is the question of convenience of the House, Government and the Members. Please try to understand that the business is arranged in such a manner that we have something in Lok Sabha and something in Rajya Sabha. Suppose Rajya Sabha does not function or does not transact business

and we do not get business, then what will happen? I do not want to blame anybody. Who is responsible is a different matter. First, Parliament is collective of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Secondly, the House is supreme. The House allots the time. This Bill is listed in the regular business. It is not supplementary. It is in the regular business. So, please try to understand and take up the discussion.

SHRI K.C. VENUGOPAL : What is the purpose of BAC?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The BAC has got its own importance. I am not denying it. But sometimes it happens in the House. We will take to the BAC other issues which are there.

SHRI K.C. VENUGOPAL : You have already listed Discussion under rule 193.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Yesterday also it happened. It cannot be made as a practice.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There is no violation of anything.

SHRI K.C. VENUGOPAL : It is not the question of violation.... *(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Bill is not a controversial Bill. So, we have no objection in that way. But please understand that unless the Members know beforehand what is being debated, how can they prepare? This was listed in the business. The List of Business came to our house this morning. So, when will the Members have the chance to prepare?

Secondly, as far as amendment is concerned, normally amendments are to be given one day ahead of listing of the Bill. Now, if you place the Bill today, how will they prepare and give amendment? Still two amendments have been given by Shri Tathagata Satpathy. He must have given them today. So, please advise the Government so that there is enough time to prepare and give amendments.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Saugata Roy Ji, to my knowledge, this Bill was introduced yesterday and it has been listed in the List of Business of today. It is not supplementary business. That is why, he has moved amendments also. Let us discuss it. If the House normally functions, I have no problem at all. ... *(Interruptions)* You participate in it as much as you can.... *(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY : They must have a plan that this is the routine for this week. Then we can prepare ahead.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Your point is well taken.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Then, why is Business Advisory Committee there? ... (*Interruptions*) Whenever we raise an issue here, you say that no notice is given; no information is given. I respect the Chair and also Shri Venkaiah Naidu's Government. But, when you say something, you should also follow it. You should not say one thing and do the other. That is not fair.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are a very senior Member.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I never questioned it... (*Interruptions*) We respect the Chair. I said that such things are always taken in the Business Advisory Committee meetings. You always insist that you are for Calling Attention, Half an Hour Discussion and all other things. But, many things are pending. For other things you ask the rules and question the timing. You take up the discussion, which is already continued under Rule 193 about flood and natural calamities.... (*Interruptions*)

15.06 hrs**SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE BILL, 2014**

HON. DEPUTY SPEAKER: I hope that whatever views the hon. Members have expressed, the Government will take note of it. Now, we shall take up item no.15.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

“That the Bill to establish and declare Schools of Planning and Architecture as Institutions of national importance in order to promote education and research in architectural studies including planning of human settlements, be taken into consideration.”

Sir, it has been once famously said that planning is to bring the future into the present so that you can do something about it now. The School of Planning and Architecture Bill, 2014 seeks to address challenges that have been presented by our past, course corrective in the future and edge a vibrant future for our children and especially for our nation.

Sir, the School of Planning and Architecture, Delhi was established in the year 1959 and conferred the status of deemed to be a university in 1979. However, in the event of rapid urbanization and looking at the needs of our countrymen, there were two Schools of Planning and Architecture that were set up in Vijayawada and Bhopal in the year 2008. However, students from both these institutions have been unable to get their degrees till now. I urge you to implore the hon. Members of this august House to kindly give their views and suggestions on this Bill so that the long pending demand and very deservedly right of the students in these schools can be in some way preserved, can be upheld and also with the blessings of this House the Schools of Planning and Architecture become institutions of national importance.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to establish and declare Schools of Planning and Architecture as Institutions of national importance in order to promote education and research in architectural studies including planning of human settlements, be taken into consideration.”

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, with your permission, I would like to speak from here.

Sir, the discipline of planning and architecture is a very important discipline given the context of our present country. Our country is rapidly urbanizing. Young people are leaving their villages and migrating to cities in large numbers. When they migrate to cities, one of the common problems they face is of housing. Urban housing, especially for the urban poor will become a major challenge in the future. As hon. Minister rightly said, if we do not plan for the future challenges right now, we will be faced with the ticking time bomb. We will have a overflowing population without access to the basic public services that they need.

In this context, the School of Planning and Architecture plays a very important role. It is one of the few academic institutions teaching students the discipline of urban planning, teaching students the technology tools that come handy when it comes to urban planning like GIS and others. It is very important that as our population is expanding – be it in villages, be it in small towns, be it in cities or mega cities across the country – planning needs to be an important part of our envisioning process.

We need planning for our villages as to where the drains will be, where the sewerage be, where the parks will be located. We need the same kind of planning and foresight for our towns as to where our garbage dumps will be, how we take care of problems of water logging in terms of a heavy downpour or rainfall. We need the same kind of discipline when it comes to problems of mega cities. What is our solution towards public transport? What is our solution towards parking? How do we decongest our roads? In all of these problems of the present and problems of the near future, we need institutions of excellence and the School of Planning and Architecture, as said by the hon. Minister, established in 1959 becoming a deemed university in 1978, plays a very important role.

Sir, this Bill has a very noble intention. As hon. Member, Prof. Saugata Roy, said, it is not a controversial Bill. We do want our institutions to become institutions of excellence. Especially the students, who are in Bhopal and Vijayawada, have graduated and are awaiting their degrees and it is the right of the Government to look after the plight of the students there and confer the degree to those students.

Another important part of this Bill is that it institutes a Council for the School of Planning and Architecture. This Council will comprise of representatives from the Governments, representatives from the academia, representatives of the public administration and it will function under the leadership of the hon. President of India who has been accorded the high position of Visitor.

Of course, there are numerous benefits associated with this Bill. One of the objectives of the Bill is to promote education and research. That is something that all of us agree because when it comes to higher education institutes in India, specifically in the field of research, we are not able to produce research that is of international recognition. Sir, it is very disappointing for a young Member of Parliament like me when I see my peers and young scientists going to universities outside of India. They are getting the necessary support for research and winning awards and fellowships, but the same kind of necessary research support and academic environment is not provided to institutes in India, especially in the field of higher education. That is why, many of our higher education institutes, despite boasting of reputed faculty and despite being proud of an amazing student community, do not produce enough research when then helps propel these universities to higher rankings in the global fora of universities across the world.

Of course, it is a very important initiative to promote research, but the Bill does not specifically address how the research will be promoted. Will specific grants be given to researchers? Will it encourage joint research projects between institutes in India and outside? Will those of our students and professors, who are

currently working or teaching in universities outside of India and want to come back as either faculty or guest faculty, be given the necessary research support? That is not mentioned.

If we want, as this Bill says, the School of Planning and Architecture to provide global leadership, then global leadership is not possible without engaging our global India diaspora and wherever the professors of planning and architecture are, we must provide them the necessary incentives to come back and bring their vast experience to India and teach our students as well as encourage our students in the area of research. Too often our students go to the market and buy research projects. It has become a transaction and research is done as very matter of fact without much discipline and without much vigour. So, it is very important that if you want the School of Planning and Architecture to be a global leader in research, then specific research initiatives should have been highlighted in this Bill.

Similarly, Sir, if we do ask for global leadership, it is not possible to be a global leader unless you have a global faculty, unless you have a global student body and unless you have global best practices. Now, how do we encourage those Indian professors who are earning very high salaries, teaching the very same subjects in universities across? How do we encourage and motivate them to come back? They would want to come back, but they would want some necessary support services for their spouses and their children. What kind of necessary support will we provide to them? What kind of necessary support will we provide to the students who want to study and be part of this global leadership institute?

There are many meritorious students in India. India is the land of *Vishwakarma*; India is the land of designers; and India is the land of urban planners. Specifically coming from the North East, I know the entire community of young people, who are excellent in design and have a very strong creative bent of mind. It is important in the fellowships and scholarships that these three Schools of Planning & Architecture will provide that they must aim and have

certain criteria, which will benefit students who come from poor areas; which will benefit female students; and which will benefit students from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and give opportunities. I am saying this because the eligibility criterion of this University is quite stringent, and the fees are quite high. These are the only three institutes in the country. If somebody has to come from a remote village in Nagaland and study in Bhopal, then he has to incur a lot of fees. So, the scholarship and fellowship programmes 'must' have specific criteria, which will enable the students body -- within these three institutes -- to be diverse and to come from diverse backgrounds of gender, race, caste and economic backgrounds.

But at the same time, there are certain limitations or certain questions that this Bill does not address. One of the limitations is that of the problem of fake universities. So many universities are there in India, which are offering fake degrees. They are operating under fake names. If you search School of Planning & Architecture, then thousands of institutes will come up, which have some fraud name at the beginning and then School of Planning & Architecture. How will this Bill really penalise those who are the promoters of these fake universities, and those promoters who give fake degrees? As a result of this, so many students face problems. They spend a lot of money on tuition and hostel, and after the end of 3-4 years they realise that this university is not legitimate and not worthy enough to grant degrees. Thereafter, they have to go to the High Court and challenge the university, and their fees are never recovered. How will this Bill protect those students from all the various fake universities out there in our country and all the fake degrees, which are being provided? I am asking this because this has not been taken care in this Bill.

Secondly, if you look at the composition of the Board, it is comprised of Members of the Government; Members of the Academia; and Members of other Associations. But the Schools of Planning & Architecture is a professional discipline. Many of our students will leave these institutes to go and work in

professional design institutes, and some of them will work in professional consulting firms. Is it not necessary that we have somebody from the industry also to be on the Board even if for a short tenure of two years as opposed to five year tenure that you have? They could come there and give the necessary industry experience and also provide the real-world experience that we need in our classrooms.

Thirdly, the Bill provides Rs. 50 crore to the institute in Bhopal; Rs. 30 crore to the institute in Vijayawada; and Rs. 5 crore plan support to the institute in Delhi. These institutes are going to be the pillars of excellence not only for the next 5-10 years, but for the next 50 years. This amount of Rs. 50 crore; Rs. 30 crore; and Rs. 5 crore, at some point, will prove to be insufficient, and that is why I am again asking the Ministry to have a separate Board, which would be the Fund-Raising Board. This will comprise of representatives from the industry whose sole objective is to ensure that this institute becomes a global leader amongst all the Schools of Planning & Architecture, and of course, give the sector the necessary corpus support so that they can have the best of laboratories, systems and faculty. It is important that these Members of the Fund-Raising Advisory Board provide the necessary financial advice to these institutes so that whatever corpus they have, they can provide the necessary investment advice whether to invest them in mutual fund or in any other long-term pension funds.

A lot of universities across the world become independent of Government support through the active fund-raising efforts of the alumni as well as of their Board. This is what helps them get the best of faculty; best of systems; and provide the maximum number of scholarships. So, fund-raising is a very important part.

Lastly, in conclusion, it is very important in our current environment that we must promote a scientific temper in education. Education is the pillar of our society. It is through the road of education that any great society is formed.

When India won its hard fought Independence, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru Ji at that point of time envisioned an IIT, at that point of time envisioned the All India Institute of Medical Sciences, and at that point of time envisioned the Indian Institute of Management. Despite facing severe criticism that the country was only having 50 per cent literacy rate, the first Prime Minister of India envisioned a bold institute that would still stand the test of time, and till today our students vie and compete with each other to get into an IIT, to get into an IIM, and to get into an AIIMS. This is the kind of scientific temper that we must push and inculcate in our discourse and in our environment.

We have to be cautious that what we are also gradually seeing is that this scientific temper and scientific environment is gradually being eroded, and science is being mixed with religion and science is being mixed with mythology. We must accord due respect and understand that there is a separation that exists. We must ensure the sovereignty of these institutes and do not dictate what students should eat, whether it is vegetarian food or non-vegetarian food. We should not dictate what students should wear. We should focus on how do our students become the best students, and how do our institutes become best institutes. I do not think by promoting vegetarian food in IITs, we are going to make sure that the IITs become the top-ranked engineering institutes. Therefore, we must be careful, that we must have our Ministers not talk about *rakshasas*, but talk about technology, talk about satellites, talk about landing on the Moon because that is the vision of the first Prime Minister of India Shri Jawaharlal Nehru Ji. We must salute his vision and that is the vision of education. We hope that this Government would be an 'education Government', we hope that this Prime Minister will be an 'education Prime Minister' and will teach that climate change is real as opposed to his other speeches where he has discouraged the theory of climate change. This Prime Minister, I hope, will encourage genetic research and not confuse with mythology. We must accord due respect to science, due respect to religion, due respect to

mythology and let us not confuse our students. We want our students to be the best in the world. We want our institutes to be the best in the world.

With that I fully support this Bill. I am always happy when Education Minister is here. Personally being from Assam, I feel that we have second a Minister from Assam. She is the daughter-in-law of our district, so we always feel happy of Dhubri. I am sure, Madam, if you are kind enough, you will provide a School of Planning and Architecture in your district in Assam.

HON. DEPUTY-SPEAKER: As far as food is concerned, it is the choice of the students. The choice of vegetarian or non-vegetarian food should always be left to the students. Regarding the advertisements being given by many bogus institutes, a point which you have raised, we have to take some action.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I will answer that question while replying to the debate. Whatever action has been taken, through you, I will inform the House.

श्री आलोक संजर (भोपाल) : उपाध्यक्ष जी, योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014 पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको और अपने दल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आश्वासनों से ऊपर उठकर, इस सरकार ने जमीनी स्तर पर इसकी नींव को रखने की शुरुआत की है। योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, इस दिशा में केन्द्र सरकार का मजबूत एवं सार्थक कदम है। किसी ने ठीक लिखा है कि “मेहनतकश इंसानों को ये दुनिया करे सलाम।”

आज हम देख रहे हैं कि देश में और प्रदेशों में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां सिर्फ विकास कार्य हो रहे हैं और योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज मैं अपने को गौरवाचित महसूस कर रहा हूँ कि एक जनसेवक के रूप में ऐसे संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जिसे झीलों की नगरी भोपाल शहर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां तीन योजना और वास्तुकला विद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं, उनमें से एक भोपाल राजधानी में स्थापित है। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाना प्रस्तावित है, इसका मैं समर्थन भी करता हूँ। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के पीछे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, सारी दुनिया जानती है कि भारत एक विकासशील देश है और नगरीयकरण एवं औद्योगिककरण करने में हमारे सामने कई चुनौतियां रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद जो देश में उप-नगर विकसित करने की कल्पना और क्रियान्वयन की योजना बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता देश के सामने रखी है। योजना को सुनियोजित आकार देने के लिए जो राष्ट्र को भविष्य में वास्तुकार एवं योजनाकारों की आवश्यकता होगी, उनकी गुणवत्ता इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने से सुनिश्चित की जा सकेगी।

हिन्दुस्तान बहुआयामी धार्मिक, सामाजिक, संस्कारों एवं रीति रिवाजों को मानने वाला देश है, इस कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतवर्ष के योजनाकार व वास्तुशिल्पी संसार की उच्चतम तकनीकी से परिपूर्ण होते हुए भी हमारे देश की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय, ग्रामीण, आदिवासी, वनांचल, पर्वतीय, नदीय एवं समुद्रीय क्षेत्र के आस-पास के भौगोलिक दृष्टिकोण से योजनाओं का क्रियान्वयन सम्भव कर सकें।

आज हमारे देश के सामने ऊर्जा एक बड़ी चुनौती है, हमारे देश के भविष्य के दृष्टिगत हमारे योजनाकार व वास्तुविद इस प्रकार के भवनों का निर्माण करने की दिशा में शोध करेंगे, जिससे ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल हो। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश का क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय है, इस कारण से सूर्य देवता हमारे देश पर मेहरबान है। अतएव भविष्य में इमारतें इस योजना से बनें कि बिजली का उपयोग दिन के समय में कम से कम हो। यह भी शोध से ही सम्भव है और हम को इस विधेयक के माध्यम से सम्भव प्रतीत होता है।

पर्यावरण भी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण और समझने वाली चुनौती है इसलिए मेरा मानना है कि देश के नगरों का विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय विकास की ओर केंद्रित होते हुए किया जाए। इस तरह के विकास में वॉटर हारवेस्टिंग, वृक्षों का सुनिश्चित एवं पर्याप्त मात्रा में रोपण, रिहायशी इलाकों, कार्यालयों, उद्योगों आदि की लोकेशन का यातायात एवं परिवहन से सटीक लिन्केज प्लान करना आदि किया जा सकेगा।

वर्ष 2007-2008 में योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के बारे में विचार किया गया था, लेकिन सात वर्ष से यह विधेयक जन्म लेने की प्रत्याशा में अटका हुआ था। पिछली यूपीए सरकार कुम्भकरीणीय नींद में सोई हुई थी, लेकिन जनता जानती थी, समझती थी। पिछली यू.पी.ए. की सरकार ने देश को सिर्फ सपने दिखाने का काम किया है। देश अब यथार्थ में जीना चाहता है, इसलिए भोपाल की जनता ने साधारण कार्यकर्ता को ऐतिहासिक जीत दिलवा कर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। सात-आठ साल से लटके विधेयक के कारण अनेकों बच्चों का भविष्य बिगड़ा है, लेकिन आज भोपाल के छात्र-छात्राओं की तरफ से माननीय मंत्री महोदया को हार्दिक बधाई देता हूँ कि जो किसी सरकार के लिए असम्भव नहीं था, किन्तु आत्मबल नहीं होने के कारण विधेयक लटका हुआ था, उसे आपने सम्भव कर दिखाया है। किसी शायर ने ठीक कहा है कि 'मोहताज वो नहीं जेवरों का, जिसे खूबी खुदा ने दी।'

हमारे देश के सामने रोज़गार की बहुत बड़ी चुनौती है, यह हम सब जानते हैं। योजनाकार एवं वास्तुविदों को रोज़गार देने में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण अंग होगा। मेरा मानना है कि सरकार को इसकी गुणवत्ता के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान विद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित होने पर दिया जाना चाहिए।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के बाद भोपाल में अभी डिग्री नहीं मिल रही है, उनको डिग्री मिल सकेगी, जिससे ये विद्यार्थी उस डिग्री के

आधार पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीबद्ध हो सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। अतः देश के छात्र-छात्राओं के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अंत में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ जरूर विचार करें कि जो राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, वह वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित हो जाती है, उसे समायोजित न करके, निरन्तरता के आधार पर संस्था को जिस कार्य हेतु दी गयी है, उसे पूर्ण होने तक उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए।

हमारे राजा भोज ने भोपाल, धार तथा मांडू जैसे शहरों को योजनाबद्ध तरीके से हजारों साल पहले बसाया था। स्थापत्य एवं वास्तुकला पर उनका ज्ञान समृद्ध था, इस विषय पर राजा भोज ने कई ग्रंथ लिखे हैं। इनका उपयोग भी एस.पी.ए. की शिक्षा में शामिल करने का मैं सुझाव देता हूं।

मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक की सफलता की कामना व समर्थन करता हूं। मैं भोपाल से आता हूं। वहां गैस की त्रासदी हुई थी। आज भी वह भयावह रात हमारी नींद उड़ा देती है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Hon. Deputy-Speaker, infrastructure development especially in the context of urbanization and modernization needs to have professionally trained planners and architects. They need to be moulded by centres of excellence so that our efforts really can meet our international standards. It is important and has a vital role to play.

On behalf of our Party AIADMK guided by our inspiring and our beloved leader, the architect of Tamil Nadu, Dr. Amma -- who was for making every effort of the Government to give an excellent gift to the people -- let me welcome this Bill heartily and with honesty. The Union Government now seeks to make the three Schools of Planning and Architecture in New Delhi, Bhopal and Vijayawada as institutions of national importance and centres of excellence.

Really, we are sitting in this august House under the roof of the great architectural structure of the country, the Parliament House Building. This temple of democracy was constructed between 12th February, 1921 and 18th January, 1927. Two famous architects Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker from France and England designed and raised this building which has the aesthetic blending of both the Western and the Eastern traditional architecture. Apart from that, close imprint of Indian tradition has been well established. This is important. As displayed in the ancient monuments and memorials, we find the rich use of Indian symbols like “*chhajjas*” which shade the walls and windows in various forms of marble *jaalis*. We have also mingled modern scientific facilities like acoustics, simultaneous Interpretation system and computerized automatic voting system. This monumental building can richly contribute to any school of architecture.

Now this building of our Parliament aims at establishing a Council for Schools of Planning and Architecture similar to IITs and NITs to advice the Central Government on policy matters related to architecture and planning. While empowering these institutions to grant degrees, this Bill also provides for

establishing Boards of Governors for every school along with academic councils in every school. This Board can issue ordinances and make statutes corresponding to designing of courses and conferment of degrees. This Bill also provides for annual grants by the Centre while authorizing the Ministry concerned to review the performance of the Schools.

It is also spelt out in the Bill that two Members of Parliament representing both the Houses of Parliament would form part of the Council of Architecture for all schools. Among others, like the Chairman, UGC and the Minister and the Secretary of the Union Government, in-charge of the Ministry, I find the inclusion of the Chairman, AICTE as an *ex-officio* Member.

Sir, this prompts me to point out certain anomalous, conflicting situations arising out of the exercise of powers by the Presidents and Chairmen of various bodies both in establishing and smoothly running such technical and professional institutions. We have the experience of running professional institutions. I and our Hon. Deputy-Speaker have been leading educationists for 35 years. AICTE gives clearance to certain institutions but without obtaining prior approval from such professional bodies, such schools are established. This happens the other way also.

In between we also find several other agencies coming into the scenario. There are State Universities created by the State Legislatures which are authorised to accredited professional institutions. It is mandatory also for States. For instance, Anna University is there as a parent university for a large number of technical institutions in Tamil Nadu. All professional institutions, be it engineering or technical institutions like schools of architecture, have to be affiliated to Anna University which was carved out by the State Government as a technical university.

Approval by one authority is not recognised by the other authority which puts the management of technical institutions into great difficulty making them to run from pillar to post. I am pointing this out without specifying any instance because this happens all over the country. Creating unnecessary hurdles in

managing technical institutions will only come in the way of ensuring quality education.

Sir, at this juncture I would like to make a special request through you to the Union Government to set up a gateway of higher education in Tamil Nadu. We request for a Tamil Nadu School of Planning and Architecture as a premier Central institution for the south as the region is known for mixing architecture with the art of sculpting. This is my chanting of this prayer through this House.

Let me conclude.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, as I have mentioned to you earlier, we object to the way in which Bills are being brought in the House without giving the Members a chance to study them and also to give amendments.

I looked at the Bill this morning very carefully. I found that basically we agree to the principle of the Bill. So, I did not insist on giving amendments because I think the draft of the Bill prepared by the officers of HRD is good and there is nothing very objectionable. Having said that, let me welcome the new idea of having three Schools of Architecture and Planning as deemed institutions of national importance.

This Bill must have been ready for a long time. I envy the HRD Minister because she is the inheritor of the best institutions in the country none of which was set up by her party or her government. Look at the IITs. All five were set up by Pandit Jawaharlal Nehru. The School of Planning and Architecture was also set up by Pandit Jawaharlal Nehru in 1959. Why was it set up? That was because after Independence we wanted to have a new capital for Punjab. We could not find a good town planner for the job. Pandit Nehru deputed Le Corbusier from France who designed the most beautiful city in the country, Chandigarh. So it occurred to Pandit Jawaharlal Nehru that we need our own School of planning and architecture so that we could design the new cities. Now, during the last Government, they have extended the School of Planning and Architecture to two other cities, Bhopal and Vijayawada. That was also a welcome step. Now, the hon. Minister wants to declare all these institutes as institutes of national importance. We have no objection to that. I would like to mention that the main thing is to maintain the quality of excellence in these institutes because they are the best institutes. IITs, IIMs, National Law School, All India Institute of Medical Sciences, National Institute of Design in Ahmedabad which was earlier declared institute of national importance, the Indian Statistical Institute in Kolkata—all of these are excellent institutes. Our main emphasis should be to preserve the high quality, to preserve the excellence of these institutes.

Now as far as architecture is concerned, India has great tradition for architecture. You see the Moghul architecture, the architecture of Vijayanagara Hampi, or the Chalukya or Chola architecture in Tamil Nadu-all over we have great tradition. There has been mingling during the British time as somebody pointed out that this city of New Delhi was designed by Lutyens who blended Moghul architecture and modern British architecture. So, we have a great architectural tradition. But till now we have not achieved the excellence in architecture that was expected. Let me repeat why an architecture, why the school of planning and architecture was necessary. .

Earlier also and even now, all good engineering colleges have a separate faculty of architecture. Engineering is for 4 years while architecture is for 5 years. Later this degree is called B.Arch. It was changed to be Department of Architecture and Town Planning. So the students are supposed to study both these things. But there is also civil engineering. So, many people are confused what is the need for architecture. A civil engineer will determine the structure-how much strength, how much steel and cement will be needed. The architect will design the façade. An architect is basically a dreamer, an artist. He will give a holistic view to the building. Today when large number of high rise buildings have been designed, the role of architect has become even more important. I would draw the HRD Minister's attention to two famous novels, written by an American novelist called Ayn Rand- The fountainhead and Atlas Shrugged. In The Fountainhead, he describes an architect's dream of building a huge house and how he fulfils this dream. That is what an architect has to be. He has to be a dreamer.

Architecture also today includes landscaping, interior decoration and basically the façade design-how the building should look ultimately. Big building projects even in Chennai are having promotions and they produce small models and photographs so that they can sell their flats at a high cost. The role of the architect is becoming even more important. Hence, there is need for these institutes to be institutes of national importance and more such institutes in the

country. Of course I would ask for one in West Bengal which also has a good tradition of architectural education.

Next thing, I want to mention is that she has devised a three-tier structure for the schools. I don't know how it will work. One is, there is a Board of Governors; for three different schools, one school will have a Board of Governors, which will be headed by a person from outside, appointed by the President of India. They will take general policy decisions, with regard to the institute. Under that, there will be a senate, like we have senates in universities, who run the regular functioning. But what is new? Like in the IITs, they planned a council, which will be covering all the aspects of education in all the streams. It is a good model; if you can have a two-tier structure at the school level and the third tier at the composite level, which includes all the three institutes. So, it should be done.

May I mention this? When I made a mention of excellence, why have our universities and institutes of national importance not achieved the international standards, in spite of their excellence? It is the problem of in-breeding. In most universities or such institutes, people enter at the bottom as a lecturer. The same man will form an association; it would say that nobody should be brought from outside; we should be given promotion to rise up to the top. To maintain excellence in education, there should be horizontal entries. You may get a bright person working outside the country; you bring him as a professor to plan like this. This was the idea of Tagore, when he founded Viswabharti. Tagore said, "I want knowledge of the world to come into India". Tagore got the best – Andrews, Elmhirst and other brilliant people, though they worked at a very low salary. Due to the attraction of Tagore, they came. I would expect that there would be scope for horizontal entries into the schools.

Let me talk a bit about town planning. Town planning is becoming very important today. The Government has declared smart cities. But I doubt if the Urban Development Minister knows the smart cities are. We have intelligent

buildings in many cities. If you stand in front of the door, it would open; if you enter the room, the light comes up; if you hold your hand under the tap, there is a sensor and water flows down. Smart cities need not be that. That is simple electronic arrangement. Smart cities have to be a whole one. What do you do about water supply, sewerage, drainage, waste disposal in the cities, etc. The Schools of Planning and Architecture should do research in development of future cities, not only new green field cities, but also cities which will use green buildings where solar power would be used, maximum amount of day light will be used. All these designs must come into our architecture, if you want to have a real smart city.

Unfortunately, in spite of the Finance Minister's announcement, in six months, the Government has not laid the plan of the smart cities. Where are the 100 smart cities? One smart city has not been designed yet. There is a good scope for building new cities along the DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor. There is a separate Corporation; they are saying that along the corridor from Delhi to Mumbai, there will be 20 new cities. What is the plan? Nobody in the country knows how the DMIC or Chennai-Bengaluru Industrial Corridor, how the new townships will develop. The research should be done in the Schools of Planning and Architecture, on how new smart cities would be developed.

The Urban Development Ministry has a plan to set up satellite townships, close to our big cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru. We should have satellite towns along the cities. But no clear cut plan has emerged. I know it is not within the ambit of the HRD Minister; she is to only look after the educational institutes.

The Government must come forward with a clear cut plan of what they want and how they want urbanisation to be five years from today. As somebody has said urbanisation is an unstoppable process. More and more people will continuously leave the villages and come into cities. We have to make our cities habitable and that challenge has to be faced by the architect and town planner of

today. But unfortunately in our country there are big time architects. You must have heard of Charles Correa, Hafeez Contractor and Balkrishna Doshi. They all design houses for the rich. They are not designing houses or towns for the poor. We need to change our very basic approach towards architecture and town planning. I hope and expect that the new institute will produce people who can make our cities better. The Delhi School has already been established. The new schools are established at Bhopal for which Rs.50 crore have been allotted. I think it is good. Sir, Rs.30 crore have been allotted for Vijayawada. I think it is a good thing.

Lastly, I must compliment my young friend Gaurav Gogoi. He gave an excellent speech. Afterwards I asked him if he is an architect himself. He spoke of the most important point Jawaharlal Nehru spoke about which is the need is to develop a scientific temper. A scientific temper cannot be attained through either astrology or mythology. Science is a system which is certain and systematic. In science we say that unless something can be proved experimentally that is not accepted as truth. Now, the Prime Minister goes on saying that in ancient India Ganesha's head was attached by plastic surgery. We all worship Ganpati Baba but that does not mean that we all agree that there was plastic surgery done at that time. Similarly, if we take the Ramayana and Mahabharata seriously and if we really believe that those things existed, it would be playing truant with science. Science has developed through big experiments. Nothing should be done by the Government or the people in leadership which will dilute the scientific temperament of our young people. They must learn not to accept anything that is not proved by experiment. He may have any faith. I have every respect for all faiths but as far as science and technology is concerned, it must develop a scientific temperament.

Sir, the HRD Minister may have her own preference but when the HRD Minister who is to look after all our institutes of higher learning, goes and spends four hours with an astrologer, it sends a wrong message. It is not being personal.

It sends a wrong message. May I politely ask her to please avoid this from being public? She may go secretly. Nobody will object. Do not do in such a way that it comes out in Papers and sends a wrong message.

AN HON. MEMBER: Dada does it very secretly.

PROF. SAUGATA ROY : People do so many things secretly. अगर एच.आर.डी. मिनिस्टर ऐसा करेंगी, तो ठीक इम्प्रेसन नहीं जाएगा। On the one hand we are sending Mangalyaan. We are sending a man to the moon. On the other hand we are going to astrologers, babas and what not. That is creating a wrong impression...
(Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain order in the House. Prof. Saugata Roy, please address the Chair.

PROF. SAUGATA ROY : Lastly, unnecessarily by going to the Hindu Conference on education she has again created a fear that saffronisation will come. Where is the scope of saffronisation in architecture? You teach them the history of architecture but do not say that Hindu architecture was good and Muslim architecture was bad.

16.00 hrs.

Let her give them genuine history and as far as the Kendriya Vidyalayas are concerned do not remove... (Interruptions)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to seek a clarification from the senior Member. Has he heard ever a statement coming out of me pertaining to architecture that he refers to in his speech?

PROF. SAUGATA ROY : No. I am talking of scientific temperament which my young friend Shri Gaurav Gogoi mentioned.

The last point that I would like to make is about this controversy about teaching German was unnecessary. What is the harm if the Kendriya Vidyalayas teach German? ... (Interruptions) You say that you want to remove German and teach Sanskrit. If children want to improve, why do you stop that? ...
(Interruptions) With that, I am saying that there is nothing wrong with the Bill. It

is a perfectly drafted Bill. Let the schools of planning and architecture run and let there be more schools of planning and architecture including one in West Bengal.

Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you for giving me this opportunity. I was listening to Gaurav babu and now Saugata babu. They have been informative speeches. This is a good Bill. There is nothing to criticise in this Bill. I have found certain faults and glitches in the Bill and I have given two amendments which I think, the hon. Minister would be kind enough to consider. We have come to a stage in our democracy where any amendment given by a Member from the non-Ruling party seems to be an affront, seems to be an inimical move, so to cut it down, to thrash it, to weed it over is our divine duty. So, I wish that this attitude would change and practical suggestions would be taken.

16.02 hrs

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

Sir, you may remember that in the last Session of the Sixteenth Lok Sabha, the hon. Minister of HRD had brought in a Bill regarding the Centres of Excellence which enveloped some other institutes of higher learning. This could have also been brought in at that time. I am surprised as to why this was not brought in at that time because if this is going to be another centre of excellence, then it could all have been done together. Somehow the Government has chosen to keep it separate. So be it.

I may have to speak a few harsh words. First of all, these schools are not like IIMs, IITs and IIITs. An architect or a planner, to my mind, signifies an artist, signifies someone who is creative. It is not a mere job seeker, unlike IITs and other institutes where the students, soft in the head, are actually aspiring for a job in the US. Their whole aim is campus recruitment where before they gain any experience or before they gain any mastery over their subjects they want to be employed with very high salaries. This school of architecture and planning and this thought itself is something completely different and so it needs to be dealt with separately.

As you know, in India we always pride ourselves with history. It is fine. Prof. Saugata Roy also mentioned some points. I do not wish to rub it in. Our history has primarily been recorded only about the rulers, about the administrators.

So, the general social life somehow has been neglected by the Indian history scribes. Therefore, the buildings that we see today, the architecture that we see today, the building in which we are sitting today, our colleague from the AIADMK mentioned, unfortunately, might have used Indian labours to carry the bricks and stones up to a certain level, but the planning and design everything else has not been done by Indians, it has been done by white skinned people, which Tamilians will understand as *Vellaikarars*. These are foreigners who have designed these things. Whether we look at the Taj Mahal, the Qutab Minar or anything, we may see that these are associated with the rulers. If you go further back to Hampi or Konark, again it is the rulers or the kings who made these things. I assume that these were probably like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme of those years. Whenever there was a drought or distress amongst the populace, the kings started projects such as Hampi or Konark or canals and they were used to give grains to people to survive.

So, these are not, really speaking, signifying Indian architecture. If you go to the villages of India or any rural area from Bihar to Odisha, you may find it. I have travelled in Tamil Nadu. I have travelled in Karnataka also. I have unfortunately or fortunately not had the good fortune of travelling in the model State of Gujarat but otherwise in the North-East also, you will find that villages are simple in nature.

Adivasi villages have a very simple design and simple kind of cleanliness and there would be an art there. But if you see the so-called other villages of upper caste, if you believe in casteism which I know that you do not, you will realise there that villages are very badly planned. Whenever there is a conflagration, a whole village gets razed to the ground in a matter of an hour or two. Before the fire brigade lands there, the whole village is burnt. That means there has been an innate deficiency in our planning and architecture. This is not something that has happened today. It has been there from our history.

Therefore, the cities that you see today are also ill-planned and not able to cope with the huge population growth that this sub-continent is facing.

Let us go back to Mohanjadaro. I have had the good fortune of visiting Mohanjadaro. It had a very sparse population to handle. It had small drains. They used to put limestones on top of the drains as a cover so that any water running through it would get sanitised because of the limestone. But on the other hand, they had a great bath which you would have read about in the history books. Everybody used to come and bathe in the great bath. Water used to be pumped from the Sindh River that flowed nearby. That sort of a living is not possible in a densely populated country like India today. So, what do we see today? We see monstrous cities coming up like Gurgaon, for example.

Gurgaon is a great example. It has no electricity. There are outages everyday. It has no water worth mentioning the name. There is no sewage or drainage system or treatment system. Apart from that, because of no green coverage, it is a completely dusty city and this is right next to the capital of India.

What does it signify? It signifies that when you give things to private players, especially in India, it does not signify that private players are going to create an island of heaven. They will most likely create something so wretched and so miserable that whoever moves in there will suffer for the rest of their existence. Unfortunately, in most of the urban clusters in India, the free land around them, whether you go to Bangalore or any other city for that matter, has been swallowed up and gobbled up by private developers who are hell bent on making their money but all the creations that they have, all the malls and theatres have a life span of barely three to five years. So, we are not really looking into the future of this country.

The former US President, John F. Kennedy, when he was questioned about infusion of huge amount of federal funds into city planning, had said that we will neglect our cities to our peril for in neglecting them, we neglect the nation. This is probably extremely valid for a nation like the U.S. which is solely dependent on its

cities. Their urban centres are very self-contained and they produce enough to hold the nation together. We, fortunately or unfortunately, do not come from that milieu or that kind of a background. Our whole concentration should not be on building 100 smart cities. Nobody is smart. We have heard the description of SMART also, every letter standing for two words. The people of India decide about all these smartness every five years. Once our colleagues sitting to my right thought – Mr. Chairman, Sir, you and I used to sit here – that they were the Gods of the Universe and that what they knew nobody else knew. Today the people of India said in very clear terms, ‘Sorry, we know a little better than you’. So, Mr. Chairman, since you are a great believer of socialist democracy this will be applicable to you, nobody today in this country can actually claim to be smarter than the people. The people are the smartest. Today we are here. Tomorrow we may be there or we may be out of this little place. So, it is not smart cities we should be looking at. We should be looking at what people want. ... (*Interruptions*) I have more time, thank you.

I would request the hon. Minister to tweak certain things so that this does not become a fiefdom of the babus in her Ministry or in the North Block and in the South Block. All these Bills seem very monotonous without any imagination, without any concept of what the future will demand from us. One little example I will give you. They have very categorically mentioned – this is in page 4 – that these will be “institutes of not for profit”. If you look to the future, look to the future of not 500 years, but of 10 years or 100 years, the Government is becoming more and more incapable of infusing funds into so many schemes. So, why not consider making these institutes financially capable of standing up for themselves by generating funds so that they can actually be centres of excellence? If they have good funds on their own, let them have some kind of independence of their own. Let them get teachers, let them get professors and lecturers from abroad. Let these institutes become centres of international excellence.

I will shut down my babbling in a short while. Prof. Saugata Roy mentioned about Le Corbusier. I just read in the newspapers recently that in

Chandigarh some of these *babus*, not knowing what they were dealing with, have given off very expensive, very well designed, old and awesome furniture, designed by Le Corbusier and by his colleagues, his group of designers and architects, which were lying in very many buildings, have been hived off and given away for a pittance. They did it not knowing their real value. Those are now going abroad and they will be auctioned at extremely high cost. This is how we treat excellence in art and designing. ... (*Interruptions*)

Prof. Saugata Roy mentioned the names of a lot of big planners and architects, who design homes for all the big people. In this country also there have been people like Lori Becker, Udhar Pinto and other small and medium architects who have designed homes which are beautiful, well ventilated, well lit which would require very little fans or electricity, which would be nature friendly and which would be built with local material. But our big builders have ensured that those people are crushed. ... (*Interruptions*) While supporting this Bill, I would only want that the hon. Minister should consider setting these institutes of excellence comparatively free. Let them earn their worth. Let them be competitive at the global level. Let them have research because we do not allow research. They are not growing. So, let us allow research. Let those who pass out be mandatorily asked to work because they are doing it at the largesse of the Government. Let them be asked, through the ULBs, to work in the country for at least two years.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon Chairperson, Sir, I am really honoured to speak here today for the reason that the HRD Minister is bringing forward such wonderful Bills one after the other. The earlier one was about the IIITs. Today, it is a Bill to establish and declare Schools of Planning and Architecture as Institutions of national importance in order to promote education and research in architectural studies including planning of human settlements.

Sir, I will not deviate myself from the hon. Members who have spoken earlier. Let me heartily congratulate Shri Gaurav for his wonderful speech except one or two sarcastic comments which are political in nature. Otherwise, he has made a wonderful speech. You have given a direction for today's Bill and the speech in respect of the Bill. I, for one, born and brought up in Mumbai do not agree with the statement made by the hon. Member. People were saying that because of poverty, the MNREGS was there and people were asked to create some structures. I do not agree with the statement made by my colleague.

Look at even the railway stations. Look at the Chatrapathi Shivaji Terminus in Mumbai, You go to the Mumbai Municipal Corporation. Look at some of the forts and palaces. Look at the wonderful temples we are having. Such wonderful structures have been created in this country by architects only! Who is an architect? An architect is one that whenever he creates a thing, he immediately expects the way he wants the country to go. The moment you create a fort, you know that you want to protect the people. You want the people to survive with whatever necessities they want. It is not only to rule the people of the country but also you want to give them assurance that the fort is going to protect every one who is there. Look at the forts which have been created by Chatrapathi Shivaji Maharaj. I would request some of the hon. Members who are here to go to the forts which are there right at the top of the hills.

Today, we are worried about water supply. Today itself, even if you go to the forts, you will find ample water is there at the top of the forts which are 3000-

4000 metres high. Such is the vision of those people! Today, you have brought forward this Bill. I, for one, feel that while doing so, you should take care of one thing. Urbanisation is going on very rapidly. That is my real concern. The laws are having their own limitations. The Corporations are not ruling the villages. Their laws are not applicable to the villages. Small towns are being created everywhere without sewerage facilities, water supply, sanitation, etc. Where to dump the garbage? How to use it for creating energy? Nothing is there. All small towns are coming up. He has given the names of the architects. These are the big architects in Mumbai. They never created small homes. They once tried the CIDCO project but failed miserably because they never had the application of mind for the poor people, what is the need of the common man and the need of the poor people.

Of late, we have faced a very devastating catastrophe at Pune when the whole Malin village got devastated in one rain. The next day, you did not see a village at all there. Not a single house was there. So, planning needs to be done there. I, for one, feel that when you want to create an institution of national importance, why do you come up with only three?

I would like to inform the hon. Minister of Human Resource Development that the JJ School of Art in Mumbai is one of the pioneers of architecture in this country. The building of that school itself is again a monument like structure. A number of architects have been produced by that institute. It is one of the best institutes for architecture and art in India. I think this Bill is ignoring that institution. I do not know how that institute can be covered under this Bill. I would like to know from the hon. Minister whether it is possible to cover that institution. I request that it should be covered so that this wonderful institution can be made as an institute of national importance.

Then, what is the intake of the students? Where the students are going to come from? The students are going to come to these institutions only after completing their 12th Standard. Today we have got Common Entrance Test and Joint Entrance Examination for medical and engineering courses. But what is the

position about architecture? When we are going to create institutes of national importance, what are the conditions for admission of students? Are we going to conduct Entrance Examination for the students? Are we going to set up more and more institutes of architecture in this country?

As the number of students is increasing, the number of private colleges is also increasing. I think Prof. Saugata Roy has very rightly mentioned about fake institutes. In Pune, Maharashtra, a number of higher educational institutes are there. But there are many fake institutes.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Member's time is up.

SHRI ARVIND SAWANT : Sir, I will conclude soon. Unlike others, I am not going to deviate from the subject or deviate from the Bill.

So, a number of fake institutes are there in the country. I, therefore, request the hon. Minister to kindly look into this issue. Such institutes are neither affiliated to the State nor to the Centre. But they are run by some private organizations. When the students reach the final year, they come to know that their institute is not recognized by anybody and their career is spoiled.

Then, Clause 1(2) of the Bill states:

“It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act, and any reference to the commencement in any such provision of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.”

When an Act is passed, it is passed with all the clauses included in it. I do not understand the logic of appointing different dates for implementation of different provisions of this Bill. I would like to know the reason for this from the hon. Minister.

Sir, again I would like to quote another clause here. Clause 4 of the Bill says:

“On and from the date of commencement of this Act, the Schools specified in column (3) of the Schedule, shall be the body corporates having perpetual succession and a common seal with the power subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall by their respective names mentioned in column (5) of the Schedule, sue or be sued.”

We are not creating these institutions for selling properties. They are created to impart education to students.

With these words, I wholeheartedly support this Bill and I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the School of Planning and Architecture Bill, 2014 moved by the hon. Minister which aims to confer the status of institute of national importance to three Schools of Planning and Architecture out of which one is situated near Vijayawada in Andhra Pradesh.

Sir, in every crisis there is also an opportunity. In our new State of Andhra Pradesh, we find that in the midst of all the crises that we are facing, we also have a once in lifetime opportunity to create a new Greenfield Capital City near Vijayawada and Guntur. In fact, it is quite a fortuitous coincidence that the School of Architecture and Planning happens to be in Vijayawada and that we are also having the opportunity to build a brand new Capital City very close to Vijayawada. Every top Architecture and Planning Firm in the world is competing for the honour to work with us.

Sir, along with our Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu *garu* we have visited Singapore and Japan so far. In Japan, three out of the top ten most livable cities in the world Kyoto, Tokyo, Fukuoka and Singapore are among the most livable cities in the world. We plan to visit a few others in Europe as well to learn from them as to how to make a city livable because unfortunately we do not have such examples here at home yet. The Singapore Government has agreed to partner with the Government of Andhra Pradesh and the aim is to build one of the most livable cities in the world; a people's capital which takes into account a smart, connected, green, efficient, sustainable, inclusive and above all, happy and within Indian ethos. In the process of doing this, we also need to ensure that the knowledge that is gained and the capabilities that are developed remain in India as we embark on building on 100 more cities across the country.

The School of Planning and Architecture in Vijayawada is in an ideal position to work closely on this project so that India can retain the learning and build on these capabilities. I would like to give two examples as to how it should

be done and how it should not be done. We have examples of Dubai and Singapore. Dubai was built by some of the most fascinating architects in the world but none of the capabilities have been retained by Dubai. They still depend on foreign firms and foreign Governments to support those capabilities. Whereas in Singapore, they have developed institutes and they are now supporting countries around the world even such as ours to help us build such type of cities.

I would like to know whether we can create such kind of frameworks so that the School of Architecture and Planning can work with these institutions in building our new Capitals. In this way our capabilities are also retained in our place.

When smart cities are being built lakhs and crores or rupees are required. While doing such work, investing some of that amount in starting a School of Architecture and Planning in each smart city, would ensure that those capabilities are being developed locally and remain there even after the development work is over.

This Bill is as important as the maiden Bill on IIIT moved by the hon. Minister of HRD in the Rajya Sabha the other day. It was very necessary for the students of Kanchipuram who are waiting for their degrees for the last many years. In the same way, passage of this Bill is equally important as the students of School of Planning and Architecture at Bhopal and Vijayawada are eagerly waiting for the passage of this Bill for the last six years. The School at Delhi is in comfortable position as it is given the 'deemed university' status unlike the other two Schools. As these Schools have not been conferred 'deemed university' status, they are now not able to issue degrees to students since 2008-09. So, to confer degrees to graduates, the Schools will get authorisation only when this Bill becomes an Act. I sincerely thank the hon. Minister on behalf of students from Vijayawada School of Planning and Architecture.

Sir, there is no representation of students in the Governing body under Clause 13 or in the Council under Clause 33. I strongly feel that there has to be a

representative from students to ventilate their grievances or ideas or suggestions for improvement of the School. So, I request the hon. Minister to consider including a student representative on the Board of Governors and also in the Council. Further, in the Council, you are proposing to nominate two Members, one from Lok Sabha and one from Rajya Sabha. I failed to understand as to why they need to be nominated as the contribution they would make for the betterment of the School, since it is technical in nature, may not even be required. So I suggest for consideration to delete Clause 33(b) of the Bill.

I would be failing in my duty if I failed to point out about reservation for SCs, STs and OBCs in the Schools. Nowhere in the Bill there is a mention about reservation of students belonging to SCs, STs and OBCs. Reservation in these Schools has to be followed like any other premier institutions such as IITs, IIMs etc. So, I would like the hon. Minister to please consider these points as well.

With these words, I conclude my observations on the Bill. Thank you very much.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Hon. Chairperson, Sir, at the outset let me congratulate the HRD Minister for bringing various Bills in this Session. The first one was IIT Bill. Now, she has brought the School of Planning and Architecture Bill. I would like to appreciate the HRD Minister for having a will to bring this Bill but I would request the Minister to continue the same will to make it really a national centre of excellence. That is what is required. Merely making the Act will not suffice.

As you know, Sir, the mother of all arts is architecture. Without architecture of our own, we have no soul of our civilization. If you remember, today India is recognized because of its architecture, because of its past. When people think of India, they think of Taj Mahal. When they come to Delhi, they would like to see the Parliament building, Qutub Minar and Lal Quila. When they go to Hyderabad, they would like to see Charminar, Golkonda, Thousand Pillars Temple. When they go to Maharashtra, they would like to see Ajanta and Ellora. When they go to Odisha, they would like to see Konark Sun Temple. For remembering our civilization, we have to definitely build architectural monuments. That is how, our civilization would be remembered.

If you look at the various architectural wonders, you would know that our country is a land of Vishwa Karmas. Look at Harappa Mohenjo Daro. Today we remember because they built a fine city with whatever capacity that they had at that time. That is why I would like to say that planning and architecture are the combination of *dil* and *dimaag*, which are very much required.

Today, we speak about smart cities. When we speak about smart cities, it is very unfortunate that most of us, even the Members of Parliament, do not have any idea about smart cities. Recently, there was an advertisement or publication asking people to give the meaning of the visualization of smart cities. We had a very good past and somehow we lost in the middle. This Bill is very much required.

I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this important Bill. In the last five or six years, students were unable to get degrees. I do not know why the earlier Governments had neglected it. It is a small issue. Even at that time, all Parties would have supported it.

One of my young colleagues mentioned about Jawaharlal Nehru but he forgot to mention about Maulana Abdul Kalam. He was the first Education Minister. He was the person who started IITs, who started higher education and who started the Aligarh Muslim University. Thus, our forefathers had laid a good foundation. We must be very thankful to them for having given a good foundation.

Now, coming to the present Bill, the School of Planning and Architecture Bill, one of my colleagues has talked about architecture and astrology. Now, I would like to mention about *vastu*. I noticed that when the various Chief Ministers moved to the Secretariat, they changed the entire building. Definitely we have our own culture, ethos and sentiments. We have to incorporate those sentiments, *vastu* and architecture into the present one. That is not a bad idea. We should not feel bad about that. We will have to carry on with it. That will actually be more useful.

Regarding this Bill *per se* I would like to say a few words. As one of my colleagues has pointed out, there is no mention about reservation. So, it will not be legally tenable. Any government institution cannot run without the rule of reservation. I do not know why this issue has not been taken into account in this Bill.

Secondly, the mode of admission has also not been mentioned here. The issue – whether it has been a separate examination or a national examination – has also not been mentioned. I would request the Minister concerned to take this aspect into account. Otherwise, this Bill will get entangled in judiciary.

Thirdly, when I look at the logo of the School of Planning and Architecture Bill, I was disappointed. When you look at the logo of the School of Planning, it

looks like a pyramid. The School of Planning and Architecture should reflect our culture, our architecture and ourselves, and not the pyramid. But whether it was an oversight, I do not know. So, I would request the HRD Minister to kindly look into this matter and Indianise the logo.

Sir, regarding the Board of Governors, Parliament's nomination is there. Appointing the Members of Parliament in the Board of Governors is a good idea. But if the Members of Parliament with technical knowledge in that particular field, are there, it would be an ideal thing. So, in the Clause of Board of Governors, if the discretion of the Speaker or the Chairman of the Rajya Sabha is maintained, it would be a good thing.

As you know 'power corrupts and absolute power corrupts absolutely.' There is a clause regarding the Tribunal. The Tribunal consists of the institutions. It is mentioned that no decision of the Tribunal can be challenged in the court. Sir, it cannot sustain. Even ordinary rulings are challenged in the court. That is why, I would request the hon. Minister to please look into this clause.

Sir, I wish to tell about my profession. We Indians are capable of doing the world class architecture, provided we are given the opportunities, provided we are supported, provided we are taken care by the public institutions. So, we all Indians are capable. I would give one example. Twenty-five years back, when I was an MBBS and PG students, all the big time politicians, if they had a chest problem, for the CABG, they used to rush by a private plane to America and Europe. But today, no Indian politician would think of going outside the country for treatment. They are more than happy to get themselves operated upon in this country itself. In fact, it is a medical tourism, which is occurring. Most of the big people from outside the country, are coming now to India for their treatment and operation. This is the strength of India. The only thing is that we have to pave the way so that the intellectual people can bring in their planning and architecture here. The people, who have built so many monuments in our country, can also build the cities here.

Sir, before I conclude, I would say that we must differentiate between the smart cities and great cities. Smart cities need not be great cities. We have to see how best cities we can build with a simple investment. We have to think in this way. Then only, with the vast population like India, we can sustain.

With these words, I conclude. Thank you very much for giving me the opportunity.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this important Bill. First of all, I am in agreement with the present Bill. I am supporting this Bill.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons, the Bill, *inter alia*, proposes to –

- (i) declare those three Schools of Planning and Architecture as institutions of national importance;
- (ii) establish a Council for Schools of Planning and Architecture similar to the Indian Institute of Technology and the National Institute of Technology to advise the Central Government on policy matter in the field of architecture and planning; and
- (iii) empower these institutions to grant degrees to students of these Schools of Planning and Architecture.

Sir, I would like to know from the hon. Minister as to why they have picked up only these institutions. The School of Planning and Architecture, New Delhi was established in 1959 as an autonomous society, registered under the Societies Registration Act, 1860. Similarly, two new Schools of Planning and Architecture – one at Bhopal, Madhya Pradesh and the other at Vijayawada, Andhra Pradesh, were established in 2008 following the same method. They are also registered under the Societies Registration Act, 1860.

I would like to know from the hon. Minister as to how these institutions are treated as institutions of national importance. What is the methodology of obtaining the staff strength and financial situation in these institutions?

Sir, the Architecture institutions are very much needed in our country. The first Council in our country was established in 1972 by this Parliament because of the Architecture of our new India.

So, I would like to ask, through you, hon. Chairman, as to how we would get support from the Central Government to these institutions. What are the mechanisms to seek and improve the financial situations of such institutions? Financial accounts must be coming under the C&AG for audit. That is not mentioned in the Financial Memorandum.

We have created some institutions of national importance. We have already got more than 40 institutions under this category. We have 20 NITs, 5 IISERs, 16 IITs and one AIIMS which is in Delhi. An institution of national importance is an independent statutory body. So, it can award degrees.

But clause 8 of this Bill provides that:

“(1) Every School shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, religion, disability, domicile, ethnicity, social or economic background.

(2) No bequest, donation or transfer of any property...”.

So, as per the Indian Constitution, there is a provision for reservation in such institutions, which is lacking in this present Bill. I would like to ask the Minister to provide for reservation in these institutions. Clause 10 provides that “every school shall be not-for-profit legal entity”. So, how can this institute be kept as a not-for-profit entity? What are the mechanisms with the Government to continue to keep this institute as a non-profit entity? It is because these institutions are registered under the NGO panel. So, how can the Government intervene in the future endeavours of such institutions?

Our country is having a severe shortage of faculty, particularly in higher education. According to the recent analysis done by Technopark, India requires 1.16 million teachers for all the universities in the country. At present, India's total faculty is 8,10,000. The country has a shortage of 3,50,000 teachers. In 2020, the shortage will rise to 1.38 million in all our major institutions of higher learning and institutions of national importance. In IIT we are having one teacher for 15

students. The ideal ratio is 1:10. But in countries like USA and UK, they are having the ratio of 1:6 or 1:7.

Sir, I am going to conclude. So, at this ratio, we are having this much of shortage in the faculty. What are the mechanisms to fill up those faculty positions in our Central institutions?

Second is regarding infrastructure of the present IITs, IIMs and other learning institutes. I was a Member of the MHRD Committee for the last five years. At that time, we had seen that. In 2008, we started eight IITs in our country but one batch of students has already passed out from these institutes but the infrastructure of those institutes is merely that of a polytechnic or ITI of our country. How can we select a few more institutions in the name of national importance? We must do a through check of the present status of those institutions, not only in the Schools of Architecture but in other higher learning institutions like IITs, IIMs and IISER in our country. Then only we can reach whatever we think for the future architecture of this country and particularly, we can achieve the target in higher education. Thank you very much, Sir.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I thank the Chair for giving me this opportunity. By running such a big Department very efficiently, the present hon. Minister is proving that one does not need big degrees. So, I congratulate her.

In fact, the School of Planning and Architecture Bill, 2014 is the need of the hour. Today, when there is a tremendous pressure on the urban, rural and industrial environment in India, we definitely need proper planning and architecture, particularly when the population is ever increasing and the land remains static. In fact, it becomes more important when in costal areas land is getting reduced. Therefore, the proper planning is imperative for a country like India.

This Bill conferring the status of national importance to the Schools of Planning and Architecture is all the more appreciative to make its centers as centers of excellence on par with IITs, NITs and IIMs.

Eighty per cent of our country's population consists of the middle class, below middle class and the poor people. We cannot afford very big structures; we cannot afford very big land also. Therefore, a Bill like this becomes more relevant to have a proper planning and architecture, which is highly Indianized and also where the raw material is available within our areas.

A high level research is required so that the limited land that we have could be used to have more population and to make the surroundings of it more beautiful.

I also have a suggestion that just as we take the services of private individuals and institutions at many places, here also we can take the services of leading architects of India so that they could also contribute for the development of the country.

Reservation for weaker sections should be ensured by proper documentation both at the entry and promotional level as is done in other governmental institutions.

I was the Managing Director of the Slum Clearance Board in Tamil Nadu, which is one of the most efficiently running boards in the country. Earlier we had a multi-rooms concept where all people of a family, parents and children, live together. But, we have strongly objected to the United Nations and other people, who were giving that. We told them that to live a decent life with dignity we need to have a separate living room, separate bedroom and independent toilets. I request the Government to make it a part of its strategies while providing housing to the people, irrespective of their class.

It is very essential that research should not stop at the laboratory level only. If it has to be translated into reality, perfect coordination is required between the planning and architecture institutions and the Government Departments of Town Planning and other related departments.

I also suggest a few more points. To make our youth know the value of planning and architecture right from their formative years, this may also be formed a part of the curriculum even from the school days.

To match with the vision and dream of our beloved Prime Minister's concept of *Swatch Bharat*, I feel that tree plantation should be ensured in rural and urban areas as well as in industrial sectors.

Similarly, rainwater harvesting is extremely relevant to a country like ours. This should also form part of the planning and architecture of the buildings. In the same way, waste disposal is important, and adequate public conveyance should also be made available even at the village level.

Once again, I thank the Chair for giving me this opportunity. Thank you.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Hon. Chairperson, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill.

At the outset, I support this Bill, but I have some comments to make in light of whatever discussion has gone over here and based on my original ideas. I think, the first and foremost or at least one of the important tasks of this institution, which has been given the national status, should be to provide housing for the rural and the urban poor, for those people whose generations have vanished with a dream in their eyes of having their own houses. I think, this should be one of the aims of this institution of architecture.

Secondly, as regards smart cities, I think, our cities may be less smart, but let them be more humane and more nature-friendly. Now-a-days, our cities have become exclusive. There is no place for those who actually run the city. There are hundreds of people who live in tents, build a skyscraper and when it is completed and becomes ready to be occupied, they slip from that place and go to another tent in the nearby place. For all those who really matter in the city and run the city for us – it is not that we run the city – the common people, the labourers, the vendors, the milkwalas and all those people, these cities are becoming exclusive to them and not inclusive. I wish that smart cities are more inclusive. They may be less smart, but more humane and more nature-friendly. This is my contention about the smart cities. I think, this must be kept in mind while planning about the dream of smart cities.

We are building huge institutions like IIMs, IITs, AIIMS and institutions of planning and architecture, but the number of aspirants is going into thousands and thousands. So, there is mushrooming of private institutions all over the country. The phenomena started in early seventies from Maharashtra and Karnataka and now it has spread all over India. There are hundreds of institutions of architecture all over the country which are not only exploiting and looting the students, but are also giving very low quality education. There are such institutions not only in the

field of architecture, but in other fields of science as well, maybe engineering, medicine etc. One person has got five institutions of medicine, five institutions of engineering. The same staff is roaming around. If there is an inspection today, teachers are brought in buses or cars from one institution to the other to show them to the inspecting team. Similarly, patients are brought in artificially and shown to the Medical Council of India. They are not only providing substandard education, but are also exploiting lakhs of students by charging very high fees. If the Government cannot fulfil the requirement of the increasing number of students, the young population of India, they should at least ensure that there is a strong regulatory body which can control these institutions run under various trusts. They are not trusts; they are family trusts only. They are making huge profits at the cost of poor students, the ordinary people of India in the name of imparting education.

On scientific temper, I would like to say only one thing. Article 51A of our Constitution says that we must ensure inculcating scientific temper, sense of reasoning and spirit of inquiry among our students and our people. So, this is the fundamental duty of the Government and all the enlightened people in this House to ensure that all those things which mar the scientific temper of people, especially the students, should be discouraged. All those activities which mar the scientific temper of young generation of students are discouraged. This would help them to step into, as the real enlightened citizens, the 21st century and India become a country of 21st century and not the country of 17th or 18th century.

As regards reservation, there is no mention of reservation in this Bill. I want the Government to insert a clause for reservation also. Due to their economic disadvantage and other disadvantages, the SCs, the STs and OBCs are getting debarred from getting quality education.

Right from the outset, there are two systems of schools everywhere. There is always a comparison between those who are studying in Government schools and those who are studying in convent schools. So, reservation is very much the

right of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and they must be given this right.

I wish that one per cent share of our country's GDP that is going to education must go up to 3 per cent or 4 per cent. I am saying this because countries below us or smaller than us have higher contribution of GDP for education than our country with young people who are extremely talented. Thank you.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति जी, योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014 को सदन में लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस विधेयक के द्वारा योजना और वास्तुकला विद्यालयों को सशक्त, समृद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने की जिस मंशा से लाया गया है, निश्चित रूप से तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के इस युग में अन्य देशों से कदम मिलाने वाले इस विधेयक की आज की परिस्थितियों में नितांत आवश्यकता थी। सरकार इस विधेयक को लाई है, इसके लिए मैं बहुत सारी बधाई सरकार को देना चाहता हूँ।

मैं समझता हूँ कि यह विधेयक जो योजना और वास्तुकला है, यह भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो नये भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित होगा। मैं समझता हूँ कि वास्तुकला 1959 में स्थापित हुई और 1979 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अभी तक यह संस्थान डिग्री नहीं दे रहा है। मेरे लिए यह आश्चर्यजनक बात है। मैं स्मृति जी की बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके से उपेक्षा का दंश झेल रही ये इन तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की योजना के रूप में स्थापित करके न केवल उनको सशक्त करने की बात कही गई बल्कि काउंसिल बनाने की बात भी की गई, उनको डिग्री देने की बात की गई, और वह काउंसिल भारत सरकार को अपना परामर्श देगा। ऐसे संस्थानों को परामर्श देगा जब सारी दुनिया भारत की ओर देख रही होती है।

मुझे कई बार अफसोस होता है, इस तरह की बातें कुछ सदस्यगण कह रहे थे, भारतीय वास्तुकला की दुनिया में कोई तुलना नहीं है। यह अलग बात है कि हम अपने को भूल गये हों और यदि उस भूली हुई चीज को इन्होंने नयी शुरुआत दी तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा तीनों योजनाओं को वास्तुकला के रूप में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित किया और इन तीनों को एक समृद्धता की दिशा में आगे पहुंचाने का काम जो होगा, वह अपने में अभिनव होगा। मेरा यह निवेदन है कि इसमें एक चीज आई है कि इसे नगरीयकरण औद्योगीकरण के नृत्य विस्तार के परिवेश में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में यह समृद्ध बनाने में समर्थ होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जिस तरीके से गांव भी अब शहरों में तबदील हो रहे हैं तो इस विभाग का नीचे तक, राज्यों तक, विस्तार कैसे हो सकता है, इसकी भी जरूरत है। आज योजना और वास्तुकला विद्यालयों की पूरे देश को ही जरूरत है। इसका विस्तार किस तरीके से होगा क्योंकि अनियोजित और अनियंत्रित विकास ने तमाम समस्याओं को खड़ा किया है।

अब हम शहरों की बात करें कि कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सीवर लाइन की समस्या है, जल भराव है, एक के बाद एक समस्याएं हैं और महानगरों की नरक जैसी हालत हो गई है। ऐसे में जबकि देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा हो और गांवों की भी शहरीकरण की स्थिति हो रही हो, रोज एक नयी कॉलोनी का निर्माण हो रहा हो, इस विभाग की निश्चित रूप से आवश्यकता है। मैं बैठे-बैठे यह सोच रहा था कि यदि यह विभाग सक्रिय और सशक्त होता तो आज हिमालय में आने वाली तमाम जल प्रलयकारी भीषण विभीषिका हमारे सामने नहीं आती।

17.00 hrs

क्योंकि, नालों पर मकान बन गये, ऐसे स्थानों पर मकान बन गये, जहां कच्ची मिट्टी है। वहां जो बस्तियां नहीं बसनी चाहिए थीं, उन स्थानों पर मकान बन गये। चाहे वह जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हो या यहां का क्षेत्र हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हिमालय देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके लिए वास्तुकला और योजना का काम जब तक यह बिल पास नहीं होता, तब तक इन्हीं संस्थानों के माध्यम से वह संचालित हो सकता है। चाहे वह पार्किंग की समस्या हो या महानगरों में यातायात या जलभराव की समस्या हो, महानगर आज इन तमाम समस्याओं को झेल रहे हैं। इसलिए इस विभाग की बहुत आवश्यकता है।

मैं यह समझता हूं कि आज अनुसंधान केन्द्रों की बहुत जरूरत है। भारतीय अभियांत्रिकी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं गौरव भाई को भी कहना चाहता हूं। प्रो.सौगत राय जी यहां नहीं हैं, उन्होंने अभी रवीन्द्र नाथ टैगोर जी का उदाहरण दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने उल्टा बोला। रवीन्द्र नाथ टैगार जी ने यह नहीं कहा कि दुनिया की जानकारियों को यहां लाइये, यह अलग विषय है। उन्होंने कहा कि हम इतने समृद्ध हैं कि हम सारी जानकारियों को आत्मसात कर सकें। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का विश्व गुरु रहा है। “एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन पृथ्वियां सर्व मानवः।” रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान सारे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है, इसलिए सारे विश्व के लिए हिंदुस्तान खड़ा है और उन्होंने कहा था कि यहां का ज्ञान-विज्ञान विश्व में जाना चाहिए।

17.03 hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

इसके अलावा नेहरू जी का संदर्भ आया। मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक खोज (डिस्कवरी ऑफ इंडिया) में एक नहीं दसियों जगह नेहरू जी ने लिखा है, मुझे लगता है कि आपको कम से कम उसे पढ़ना

चाहिए। उन्होंने अपनी परम्पराओं, संस्कृति और मान्यताओं को प्राथमिकता दी है और कहा है कि इसी के आधार पर यह देश आगे बढ़ सकता है।

आज ज्योतिष की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि अणुबम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले कणाद ऋषि ने इसी धरती पर किया था। हमारे ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग हो गया तो वह सर्जरी नहीं थी, मैं कहना चाहता हूँ कि वह सर्जरी थी। पूरी दुनिया में वह विज्ञान कहां है, जो हमारे पास है। सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वह गणित था, वह ज्ञान था तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। मैं उस धरती से आता हूँ, जो वेद, पुराण और उपनिषदों की धरती है। जो 'आयुषोः वेदः' आयुर्वेद की बात करती है। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था कि जड़ी-बूटी से इलाज करने की बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं। लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे, आज सारा विश्व 'आयुषोः वेदः' आयुर्वेद के पीछे खड़ा है। यदि आयुषोः वेदः आयुर्वेद कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो केवल आयुर्विज्ञान है। ज्योतिष तो लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पीछे की गणना करने वाला विज्ञान है, उसके सामने सारे विज्ञान बौने हैं। इस विज्ञान को और आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योषित विज्ञान सारी दुनिया के लिए नम्बर एक विज्ञान है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, केवल कुछ शब्दों में न कहकर यह ज्योतिष विज्ञान, जो सारी दुनिया का मार्गदर्शन करता है, इसका उचित सम्मान होना चाहिए।

मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि एक ऐसा ही संस्थान हिमालयी राज्यों के लिए स्थापित होना चाहिए। मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि पुरातन परम्पराओं पर सारे विश्व में काम करने वाला एक संस्थान बनाने का बिल वे लाई ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I welcome this Bill. We can be proud of the School of Planning and Architecture, Delhi and our other two institutions. Our School of Planning and Architecture in Delhi is a top-ranked institution in India and is the seventh best in Asia.

When we are discussing this Bill, my humble submission is about setting our targets or goals. The aim of this Bill is to develop these three institutions into institutions of national level importance and that is all right.

I am of the firm opinion that this is an international era of education. Our goal setting should be that of international standard. India is going to be the leader of technical education in the world. So, I am of the firm opinion that we can become the leader in the technical education. Our future is bright. I understand that the hon. Minister is realising this and this is why, she has now come forward to have this kind of a legislation.

Now, coming to the various aspects, Government's policy support is very much required in all these things whether it be IIT, IIM, NIT. We can be proud of these institutions. Similarly, we are having best technical universities such as Anna University, Chennai, Ambedkar University, Mumbai, Jodhpur University, Kolkata, BITS, Rajasthan, BITS, Ranchi. All these institutions are performing very well. We have to do the maximum possible for the development of these institutions to the international level. As correctly pointed out by my learned friends, we can be proud of our glorious tradition of architecture. Our architecture is a mix of our culture. Whether it is Buddhist architecture or Mughal influenced architecture, temples, mosques, forts and churches, all these things are there. It is a socio-culture face of our civilisation.

Sir, we had a glorious tradition. Our speciality was climate responsive architecture. As I told you earlier, institutes like our socio-cultural background and even the small houses in our village are also as the symbol of it. As far as modern architecture is concerned, we can be proud in many respects. Architecture design in India is marvellous. We can be proud of our international stadiums. Vast dams and bridges were constructed in India. Pandit Jawaharlal Nehru described dams as the temples of our nation. Our country can be proud of this also. We have beautiful harbours. We have fifty plus floor buildings in Mumbai and Bangaluru and other cities of our country.

Sir, I would like to point out one very important thing. Quantity versus quality is a problem. We had many institutions. My friends were saying that mushroom growth of institution is there. That is true. We are having different kind of institutions. We are having different kind of projects like TIQUIP. I congratulate the Government for this project. TIQUIP is one of the best projects for the quality development of technical education. I myself was the Minister for Education for seven years in the State of Kerala. We have made use of it. TIQUIP will have to be strengthened. This kind of quality improvement project in the higher education is very much required. I hope that the Minister will give emphasis in this direction also.

Sir, I wish to point out another important thing. More and more research should be done in two areas – first on eco-friendly building and second on low income group house construction. I appeal to the hon. Minister to give an emphasis on this aspect. Our Indian colleges especially the architectural institution should give importance to this kind of research. I hope that hon. Minister will give direction in this regard also.

Towards the end, I wish to point out one more thing, that is, representation of SC, ST and OBC in the higher education especially in the technical education.

What exactly the Sachar Committee has recommended. If we go through the representation of minorities in the IITs and IIM, I wish to say that it is negligible. We have to correct it. I hope that the Government will come forward to correct this mistake. If you go through this Bill, there is a provision for that. When we talk of social justice, we forget it when it comes to ground realities. I appeal to the Government to ensure social justice here also.

With these few words, I once again support this Bill and conclude.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I rise to support the School of Planning and Architecture Bill, 2014. The Statement of Objects is very clear. It is to declare the three Schools as institutions of national importance, to create the Councils and to empower the institutions to grant degrees to students. I think, all of these objects are laudable.

I would just like to make a mention of a few things. As has been mentioned by many of the speakers, India is a melting pot of so many civilizations. Therefore, our architecture will, in that sense, have to show that. It has to also ensure that those civilizations and what has come from those civilizations will need to be felt through the architectural process. It is also important to understand that since 1959, there has just been one institution, the School of Planning and Architecture in New Delhi. In 2008, two have subsequently come and in 2014 these three institutions is all that we are looking at. What I would like to request the Government through you that more such institutions need to be established because the globalization process is already upon us. We are, as a nation, moving forward. We have to ensure that our architecture and the architectural processes of our country are seen right across the world.

I would like to make a mention of the need for mountain architecture. For instance, in the mountains, there is a need to capture mountain architecture. With the institutions that are available here, perhaps we are not really doing the due justice. That is why, I think, we need to have a School of Planning and Architecture in one of the mountain States. If it is done in the State of Sikkim, we will be delighted. So, I would request that a School of Planning and Architecture may be established in the State of Sikkim because the architecture of the mountains is something which I do not think is seen other than when we talk of other things like organic farming but not in the arena of design.

India boasts of the IITs. We boast of our IIMs. We boast of our so many other institutions which have given to the world a huge number of young people who are doing yeoman's service. Just recently we know that from one of the IITs, girl students have actually been recruited at Rs. 1 crore plus in terms of annual salaries. This itself speaks volumes of the kind of students and the kind of consequent action that is taken up in terms of outcomes. This is where I think, the School of Planning and Architecture would also find its place amongst all these kinds of institutions. I do understand and hope that we will be able to raise many more Schools of Planning and Architecture in our country.

With these words, I support the Bill.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने सदन में जो विधेयक रखा है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सौ स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया है। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी सपना दिखाया है। इस सपने को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में योजनाकारों और वास्तुकारों की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। दलित और ओ.बी.सी. के लोग भी देश में रहते हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। विद्यार्थी की योग्यता का क्या मापदंड होगा, छात्रवृत्ति के बारे में विश्वविद्यालय का क्या मापदंड होगा, उसके बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में कुछ और सुधार करने चाहिए थे, क्योंकि, इस देश में पिछड़े लोगों और दलितों की काफी संख्या है। वास्तुकला और वास्तुकारों के बारे में इन योजनाओं पर जो खर्चा होने वाला है, उसमें भी विभिन्नता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आप बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो दिल्ली में है, उसकी 1959 में स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो दो संस्थाएं हैं वह भोपाल और विजयवाड़ा में हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाएगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। वहां भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी इससे जोड़ा जाए, जिससे कि हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास हो और बिहार का भी विकास हो। यह जो बिल लाया गया है, केवल तीन जगह के लिए ही नहीं लाना चाहिए बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसमें जोड़ने की जरूरत थी। राष्ट्रीय महत्व के और भी संस्थान खोले जाएं, यही बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion. Sir, I rise to support this Bill with certain observations.

There is no doubt that the country as well as the globe is drastically changing at a supersonic speed. Fast development is going on through out the world and it is becoming very difficult to distinguish between rural and urban areas. In such a scenario, definitely it is highly required to have qualified manpower in the field of architecture and planning. The industrial environment in the country is also drastically changing.

I support this Bill which gives not only national status but also statutory backing to these three institutions at Delhi, Vijayawada and Bhopal.

Sir, when I talk about this subject, it is no doubt that it has already been discussed in detail regarding the significance and importance of having scientific planning in the country. Most of the planning in the country is not based on a scientific plan and scientific architecture. So, difficulty is being faced by the country. In order to avoid this situation, we should have that expertise with manpower so as to rectify this mistake. But the main point which I would like to highlight is that the Delhi Institute was established in the year 1959 at the time of Pandit Jawaharlal Nehru and also so many other nationally reputed institutes like IIT, NIT and AIIMS and so many other nationally prestigious institutes have also been set up later. I also remember that during 1986 the New Education Policy was promulgated by late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi and the main ingredient of the New Education Policy at that time was setting up centres of excellence. Now we are all talking about the centres of excellence. Definitely we should remember late Shri Rajiv Gandhi for implementing or promulgating New Education Policy. This time I would like to make certain reservation in respect of this fact also.

Now, we are all behind centres of excellence. Definitely, the country should have the centres of excellence. At the same time, I would like to urge upon the Government and also draw the attention of the hon. Minister towards the

situation of education in other sector, especially the pathetic situation of universities in the country. The new NDA Government is focusing at centralized development like 100 smart cities, 1500 odd small villages or Adarsh Grams and now these institutions. This is against the spirit of decentralization. When we talk about the development of the smart cities, when we talk about Adarsh Grams, when we talk about these institutes and pioneer institutions of national standard, we should also take into consideration other institutions of our country. The universities and colleges of our country don't have even basic infrastructure. That should also be taken care of when we promote and encourage these institutions as national institutions. Also I would like to raise another point regarding education system in our country, especially higher education system in our country. You may be well aware that in our Indian education system there is privatization and privatization has been transformed into commercialization of education. Now the commercialization of education is coupled with saffronization also. We do agree with the privatization because the private sector has contributed a lot in developing universal education of our country in higher education and we do accept it. But subsequently, the main purpose of self-financing institutions and the autonomous institutions is to have business. Now the education has become a lucrative business in our country.

I would like to draw the attention of the Government to a recent judgment of hon. Kerala High Court in which self-financing engineering colleges were evaluated by hon. High Court by appointing a commission and it is being reported that out of the number of engineering colleges in the State, 30 colleges were blacklisted from which none of the students could come out with success. That is the pathetic situation of the self-financing colleges and institutions in our country. Now with self-financing institutions, there is also saffronization of Indian system of education. After this Government assumed charge, controversies are coming up one by one in our country. We know that Sanskrit has been made a mandatory language to be studied in Central Schools. Also, the Chairman of Indian Council

of Historical Research has said that his prime aim and motto is to trace the historic background of Ramayana and Mahabharata and then there is controversy over Aligarh University also. The autonomous and independent character of the universities is being interfered by the Government. It is not fair as far as universities are concerned. The autonomous and independent character of the universities is being interfered by the Government, the political executive. It is not fair as far as universities are concerned. So, the academic excellence and academic freedom should be protected. When we talk about this Bill, definitely we should think about other institutions also.

With these words, I support the Bill.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लोक सभा चुनाव के पहले से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए प्लानिंग और आर्किटेक्चर की योजना बना ली थी। चुनाव से पहले जिस तरीके से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और देश की दिशा और दशा में परिवर्तन करने के लिए जो योजना बनायी, उसी योजना का परिणाम है कि आज यह स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बिल, 2014 हमारे सामने है।

आदरणीय एच.आर.डी. मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी उनके विकास की इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। जैसा कि पिछले ही सप्ताह हमने देखा था कि उन्होंने ट्रिपल आई.टी. बिल, 2014 पेश किया था। ऐसा लगता है कि मंत्री जी देश के विकास और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं उनके इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल में वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से देश में हमारे यहां आर्किटेक्चर प्लानिंग को डेवलप करके विश्व में हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, योग्यता बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह बिल इन संस्थाओं को बनाकर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना सम्मान बढ़ायेगा।

हम किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, वहां प्लानिंग की कोई न कोई कमी लगती है। एक बार सड़क बनती है, तो सीवरेज डालने के लिए सड़क उखाड़ दी जाती है। अगली बार फिर सड़क बनती है, तो पानी की लाइन डालने के लिए सड़क उखाड़ दी जाती है। कोई न कोई समस्या पैदा होती रहती है। अगर बिजली जलती है तो भी खंभे को लगाने के लिए सड़क उखाड़ दी जाती है। घर बनते हैं, तो भी ऐसी कोई न कोई समस्या सामने आती रहती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके लिए प्लानिंग और आर्किटेक्चर की सख्त आवश्यकता थी। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश की इस जरूरत को समझा। देश के विकास के लिए इस स्कूल की स्थापना की, जरूरत को उन्होंने समझा और इस स्थापना के माध्यम से देश के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए कार्य करने का अवसर प्रदान किया।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस चीज की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस के राज में गरीबों को इग्नोर किया गया, गरीबों की अनदेखी की गयी, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं की गयी। मंत्री जी, मैं आपसे इस बिल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए आवास की बहुत

आवश्यकता है। गरीबों को आपकी दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। उनके विकास के लिए, कम बजट वाली कोई ऐसी योजना लाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।

मैं आपका ध्यान राजस्थान की ओर ले जाना चाहूंगा। राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी आपकी तरह एक महिला हैं। प्लानिंग और आर्किटेक्चर में वह भी आपकी तरह बहुत विज्ञानी महिला हैं। राजस्थान देश में विकास के लिए, वास्तु और स्थापना के लिए, प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के सम्बन्ध में ही आपसे बात कर सकता हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजा जयसिंह ने बहुत दूर की प्लानिंग करके आर्किटेक्चर की एक योजना बनायी। जयपुर शहर उसी योजना का परिणाम है। राजस्थान का हवा महल राजधानी जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट भी राजधानी जयपुर में हैं और ऐसी अनेकों बिल्डिंग्स हैं। पूरा शहर इस तरीके से बसाया गया था। यह उनकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर का ही एक नतीजा है।

मैं आपके माध्यम से न सिर्फ जयपुर शहर, बल्कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली, धौलपुर के बारे में भी कहना चाहूंगा। करौली के अंदर भंवर विलास पैलेस, मदन मोहन जी मंदिर, धौलपुर के अंदर धौलपुर पैलेस और मचकुंड जैसी बहुत सारी बिल्डिंग्स प्लानिंग और आर्किटेक्चर के साथ बनायी गयी हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। अगर, मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का प्रत्येक क्षेत्र प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए अपने-आप में गौरव की भावना रख सकता है। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की बात कहना चाहता हूँ। वहाँ के महाराणा प्रताप हमारे देश के गौरव के प्रतीक माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के साथ-साथ, हमें उदयपुर में भी वास्तुकला का बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिल सकता है। हम सिरोही की बात कर सकते हैं। हमें सिरोही में ऐसे वास्तुकला के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। राजस्थान में उदयपुर, कोटा, बूंदी इत्यादि अनेकों जगहों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आर्किटेक्चर का विकास किया जा सकता है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान प्लानिंग और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में वर्षों से गौरवशाली इतिहास रखता है। मंत्री महोदय, मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपसे आग्रह करूंगा कि राजस्थान में भी आपके आर्शीवाद से एक योजना और वास्तुकला विद्यालय की स्थापना की जाये। मैं आशा करता हूँ कि आप राजस्थान की इस मांग पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वहाँ इसकी स्थापना करेंगे। धन्यवाद।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to speak today for my Thanjavur constituency. I would humbly submit my profound thanks to the Tamil Nadu Makkal Mudthivar hon. Puratchi Thalavi Amma. I would humbly request Madam to consider the long pending request of the people of my constituency to lay a new railway line and to introduce a new train service between Thanjavur to Ariyalur BG line. People of my constituency have been demanding this for long.

Secondly, a railway line between Thanjavur and Pattukottai has already been approved but no fund has been allotted for it till now. I urge upon the Government to consider the above proposals favourably and expedite its implementation.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this Bill. I rise to support it. I sincerely wish and hope that our school of planning and architecture in our country will not only be the institution of national importance but also be international excellence too.

We have a lot of institutions of national importance but out of 200 institution of excellence at the international level none of our institutions is being enlisted. This means that we are lacking behind the international excellence and international standards in technical as well as professional education. We should take some initiative in that regard too. All of us believe that we are fortunate enough to have this kind of education sector but we should move from good to great otherwise we will lack opportunities in the international education scenario and the employment market.

Coming to the Bill, we are talking of the welfare of the students. This Bill has especially been introduced to give certificates to the students who have completed their studies in Bhopal and Vijayawada Schools of Planning and Architecture. Section 32 of the Bill deals with the dispute redressal system but there is no mention as regards the disputes redressal mechanism of the students. The mechanism is there only for redressal of disputes between teachers and schools. In our education system today, under the guise of internal assessment, students are being harassed by the schools. Sarcastically it is termed as 'Internal Assassination' rather than 'Internal Assessment' in many of our schools. In some of the private colleges and institutions this instrument of internal assessment is being used for making the students failed for the purpose of getting more fees from the students. So, I urge upon the hon. Minister, through you, that there should be a mechanism, a statutorily recognised mechanism for redressing the grievances of the students, especially the harassment meted out to the students from the internal assessment under the guise of improving the quality of education and all.

The other thing is as per the 256th Report of the Departmentally Related Standing Committee on HRD, a sum of Rs. 2214 crore has remained as unspent

balance. The institutions are not able to spend the money earmarked for higher education. But on the other hand, all our educational institutions are starved of funds and are running for money for improving their quality of education by appointing more faculties etc. So, I urge upon the hon. Minister to look into this matter and make some arrangements for appointments of faculties in all our universities and institutions. There is a shortage of 1,70,000 teachers all across the country.

Once again, I support this Bill and congratulate the hon. Minister for introducing such a fantastic Bill for improving our education system.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, thank you for giving me this opportunity. I have only two suggestions to make.

Architecture is a multi-disciplinary subject. Besides structural engineering it involves art and aesthetics, sociology, about how people live and work and environment and culture. My suggestion is that we need to involve eminent sociologists and artists possibly in the Board.

Secondly, it is highly connected to life style and regional cultures. So, I think, there should a school of architecture and planning in every region since it is associated with regional culture and life styles.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, at the outset I would like to appreciate the valuable suggestions given by every Member of Parliament and also for the unanimous support given to this Bill. Today I speak with a little bit of a conflicting emotion. I had a learned man say in this House that he envied me, a man I have deep respect for, a senior, Prof. Saugata Roy ji. He spoke presumably about two books written by Ann Ryan – *At Last Shrugged* and *Fountainhead*, presuming possibly and I say the word presuming possibly that I might not have had been blessed with an opportunity to read either. While I do not express the anguish of the protagonist Howard Roark, let me say that there have been question marks which have been put forth with regard to what Education policy is being envisaged rather than pertaining discussions by certain Members only to the elements of the Bill. Shri Roy was kind enough to accept that he did not get into the depths of the Bill and hence used his time judiciously to mount a personal attack to which I have absolutely no problems about. There was time when Albert Einstein said that science without religion is lame. Thankfully, he did not have to pass through the scrutiny of Prof. Saugata da, otherwise he would have to wonder if he was communal.

There are some contentious issues though that have been raised with regard to scientific temper. आज इस सदन में भगवान के होने का प्रमाण मांगा गया। लेकिन मेरे पास जिम्मेदारी प्रभु के होने का प्रमाण की नहीं ज्ञान का संचार कराने की है। Scientific temper vis-à-vis the Ministry has been questioned today. I have access to certain articles where my predecessors refused to get into office without getting the *vastu* checked first. I am sure Saugata da can be having the time to peruse the same articles. But the intention here is not to create a contentious environment. The intention here is to carry forward a consensus on issues which are extremely important to our students and it is famously said that we shape our buildings and thereafter, they shape us.

Shri Ramachandran spoke about architectural glories of the very building in which this Bill is being debated. I, as a Member of Parliament, extend my

compliments to a youngster who defines what new Indian politics is all about. Shri Gaurav Gogoi, my compliments for your speech in Parliament today! My compliments to you because you spoke with passion on issues pertaining to education.

You made some charges on me. I do not accept the same. One of the charges was that we have turned IITs into a vegetarian complex. I would like to, through you, Sir, tell my young and learned friend that the IITs students in Delhi explained and, in fact, expressed their anguish at the high cost of non-vegetarian food and it was stopped in April, 2014 much before I took office.

In fact, the IITs are exploring through three organisations or individuals the possibility of providing non-vegetarian food to its students. These are decisions in which I do not interfere with.

There have been mentions made about legacy of education in our country. We paid obeisance to Pandit Nehru. A Member here paid obeisance to Rajiv Gandhi Ji and also how Education Policy was crafted by certain leaders.

I do not, in anyway, deny their contributions to the Indian political system or for that matter, the Indian educational system. But when I am accused of only upholding Sanskrit because I am saffron, I would like to remind my learned friends that I was upholding an aspect of the National Policy on Education, as envisaged by Shri Gandhi, which spoke of the three language formula.... (*Interruptions*) But it is the law of the land now.

I uphold an MoU - and it is a question which the House should answer - which says that German is the third language of India. Can I, as a representative of our nation, sign that? Honestly, I cannot. The only thing I can do is to ensure that the children in our schools and colleges have access to Indian and foreign languages. And I tell you, Sir, today that let this House know that, apart from German, French, Japanese, Mandarin are continued to be taught in Kendriya Vidyalayas. While everybody seeks to embrace legacies, let us even embrace this for if we do not embrace our languages, then who will? We embrace Maulana

Azad; we embrace Pandit Nehru; we embrace the legacy of Rajiv Gandhi but this is also the 900th year of Bhaskaracharya. Would we leave our legacy behind when it is inconvenient?

Sir, the question that needs to be asked today is that when we talk about scientific temper, what is that we attribute that thought process to? Mr. Gogoi spoke about the need to inculcate that temper in our youngsters. There are concerns that the learning outcomes from Grade 6 to Grade 8 in Science and Maths have fallen to as below as 30 per cent and for addressing that concern, a whole week will be dedicated to Maths in our country, that is, the week preceding the 22nd December which is the National Mathematics Day. We call that week *Ganith*. *Ganith* is meant for growing aptitude for numerical innovation and training. Through this, we are trying to infuse innovations in numericals and innovation in mathematics and help increase scientific temper but to compliment scientific temper and enquiry-based learning, we are also, in the Ministry, working so that patents, research and all issues pertaining to science are something that can be strengthened within our institutions and through the efforts of various State Governments and agencies in conjunction with the Central Government.

Sir, our Members have expressed concern as to whether Reservation Policy is applicable to these institutions or not. Let me assure them that it is. It is not only for admission of students but also the reservation structure, as has been envisaged by an Act of Parliament in IITs and NITs, is also applicable to the Schools of Planning and Architecture.

There is a mention here as to whether our faculty can be made world class. Through the global initiative of academic networks, we have implored to all industry experts worldwide. We are engaging in conversations with nations like the United Kingdom and the United States as to highlight to us who are their best academicians who can be brought to teach at least one semester at the cost of the Government of India in all our Central Universities, IITs, IIMs and even the Schools of Planning and Architecture.

There was a concern expressed that architecture is not only about buildings, but it is also about other aspects. I agree with that. Architecture begins where engineering ends. It is blessed that in our SPAs we also teach environmental planning. We also teach heritage conversation.

There has been a concern expressed as to whether the finances of these institutions will be audited. As in the case of IITs and NITs, let me assure the House, that at the end of the financial year, the Annual Report and the Audit done by the CAG will be laid on the Table of the House.

There was a suggestion made whether these schools can be made functional in such a fashion that they profit from our students. Since these are institutes of national importance and funded by the Government of India, it is not the intention of the Government of India to accrue profits from its own children, from its own citizens.

There have been some wonderful suggestions made as to whether students of these institutions can work with our urban local bodies, especially by Shri Satpathy, through the Ministry of Urban Development and through my own Ministry, I will appeal to each State Government so that they can look towards the prospects of engaging these students at a local level from the perspective of planning and architecture.

I would here, given the exhaustive time we have taken in discussing every detail of this particular Bill, also highlight certain international tie-ups that have already been explored and which are already underway in the three institutions, and in the SPA, Delhi. For those who are concerned whether world class education will be given in these institutions, let it be known that the University of Washington, Architectural Academy, U.K., the Georgia Tech University, Atlanta, the Norwegian Institute of Technology, the Well School of Architecture, the Kyoto University, the United Nations University, Tokyo, the Copenhagen University, have already entered into tie-ups with these three institutions.

I have had the privilege of debating in this august House two Bills before this one. In those Bills as well as this Bill today, I see an air and a cohesive decision to have a situation of consensus.

I extend, through you, my gratitude to all Members of Parliament who are today coming forth and supporting this Bill. I see that my senior colleague, Shri Arvind Sawant, is bothered about the JJ School of Art. It is a private institution, which receives some funding from the UGC. But within the UGC, we are also exploring possibilities of supporting those institutions which have heritage value. I will go back to my office and with authorities in the UGC explore certain possibilities with regard to the JJ School of Art, but I cannot give you an assurance till I study the matter in great detail.

Once again, through you, I thank this House.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill to establish and declare Schools of Planning and Architecture as Institutions of national importance in order to promote education and research in architectural studies including planning of human settlements, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 6 do stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 7

Powers and functions of Schools

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Premachandran, are you moving your amendment?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, I beg to move:

Page 4, *after* lines 18, *insert*, --

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a School shall not receive or insist any donation from students seeking admission.”. (1)

It is said that the property of the institution or the school should never be sold without the prior approval of the Central Government. So, I would like to add another clause, sub-clause 3, because it is donation. It is being stated not only here but also in Chapter IV. It also specifically states about “all monies received by school by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequeaths and transfer.”

So, the reasonable apprehension on my part is that whether a huge amount of donation will be received from the students because most of the institutions like this, if they are facing some financial crisis, resort to this practice. This is the way of mobilising resources. Will it be applicable in this school also? That is my apprehension.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, if you permit me to answer, let me assure the hon. Member that no donation will be asked for from any student. In fact, as per the rules, if anybody does ask for donation, he will be severely penalised. That is an instruction I will give.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will now put Amendment No.1 to clause 7 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 Powers and functions of Board

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, are you moving Amendment No. 2 to clause 15?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I wanted to move the amendment but after listening to the very passionate speech of the hon. Minister, I am not moving both my amendments. She has pointedly addressed what I wanted to know. So, I am not moving both my amendments.

HON. DEPUTY-SPEAKER: So, you are not moving them.

The question is:

“That clauses 15 to 29 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 15 to 29 were added to the Bill.

Clause 30 Ordinances

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, are you moving your amendments?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : No, Sir, I am not moving my amendments.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is

“That clauses 30 to 42 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 30 to 42 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary, if you want to ask any question, you can ask.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I am putting my question to the hon. Minister through you, Sir.

In section 32, although it is well-worded and it is for the purpose specially of constitution of the Tribunal of Arbitration, although it provides for resolution of the dispute between an employee and the school yet it nowhere includes the student. We see the litigation of the students is also there. So, my request to the hon. Minister is that the word “student” may also be included.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri C.R. Chaudhary, you have given the name. Do you want to say anything?

SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): No.... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would just like to highlight to the hon. Member through you that there will be a provision of Students’ Council in these institutions. A Dean of Students Welfare in the institution will be appointed and the students’ grievances will be resolved through the Faculty and Students interaction.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The motion is adopted and the Bill is passed.

17.54 hrs

**REPEALING AND AMENDING
(SECOND) BILL, 2014***

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Bill to be introduced. Shri Sadananda Gowda.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: After that, you can say. I will call you.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.”

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, the practice of this Government is to bring forward either a Bill or amendments at the very last hour itself. This is not the democratic practice and best Parliamentary practice.... (*Interruptions*) This should not be allowed. You have to protect the interests of the Members of Parliament. You are the custodian now. This practice cannot be allowed because every day, at the last hour, they bring forward either a Bill or some amendments. If we have got objection, we should have the opportunity to express it. There is no opportunity provided to Members to study the Bill. What is the emergency for the introduction of this Bill now? This is not a good practice. ... (*Interruptions*)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, we are only introducing the Bill.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Deputy Speaker, Sir, earlier also during the discussion on the School of Planning and Architecture Bill, we had objected. Then the Parliamentary Affairs Minister said that the Bill was included in the List of Business today and so there should be no objection. Now we are repeatedly pointing out that the Government is suddenly bringing out of its hat

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section-2 dated 03.12.2014

newer and newer Bills without sufficient notice and without giving us an opportunity to study the Bills. If this practice continues, then much of Parliament would become infructuous.

Sir, you have been here for a long time. You have been Deputy Speaker in the past also. You sat on the Opposition Benches also. So you may please appreciate our concern and I request you not to allow the Government to introduce Bills in this manner.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy Speaker, Sir, we are not going to discuss the Bill now. We are only introducing it.

PROF. K.V. THOMAS : Sir, this is not a good practice. This should not be done.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Speaker has permitted introduction of the Bill at short notice today. The Supplementary List of Business and copies of the Bill have already been circulated. Therefore it can be introduced.

Now the question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.”

The motion was adopted.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow the 4th December, 2014 at 11.00 a.m.

17.57 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday,
December 4, 2014/Agrahayana 13, 1936 (Saka)*
